www.indiatodayhindi.in
DABAD/46/2020-22
LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDA
-02/MP/2022-23-24, DL(ND)-11/6042/2021-22-2023;
RNI NO. 45823/86 REGISTRATION NO. DL(DS)-02
OC
आंशिक सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; फूल पृष्ठों की संख्या 70 (आवरण सहित) वर्ष 37; अंक: 02

बिहार: ये धुआं कहां से उठता है

उत्तर प्रदेश: विधानसभा का नया विधान

ऑटो रिपोर्ट: हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन

इंडिया टुडे

14 दिसंबर, 2022 50 रुपए

भारत का दौर

सबसे प्रभावशाली देशों के समूह के अध्यक्ष के नाते भारत प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहमति कायम कर बन सकता है वर्ल्ड लीडर

VISIT…

प्रधान संपादक की कलम से

दिसंबर से शुरू एक साल के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों के केंद्रीय मंच पर अपनी जगह लेगा. वह विश्व शक्तियों के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक जी20 की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है जिसका दायरा इतना बड़ा है कि भू-राजनैतिक चर्चाओं का संचालन किया जा सकता है और यहां तक कि रास्ता बदला जा सकता है. यह वह भूमिका है जो उस पर फबती है—एक किस्म का न्यूट्रल रेफरी, जो ऊंची पदवी से बोलता है, पर अनूठे ढंग से निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती आवाज है जिसे हरेक राष्ट्र सुन सकता है. संयोग से दिसंबर में भारत ने एक महीने के लिए सर्वशक्तिमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण की और सितंबर 2023 तक दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय मंच शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता करेगा. अचानक ऐसा लगता है मानो धरती पर यह भारत का लम्हा है. जी20 रसूखदारों की मेज पर बेशकीमती कुर्सी है. इसमें नई दिल्ली के पास मौका है जब वह बहुपक्षीय वार्ताओं में विश्व मंच पर अपनी शासनकला और स्वतंत्र रूप से गढ़ी गई हैसियत की धाक जमा सकता है.

अब से 2023 के आखिर तक भारत श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक और कच्छ के रण से कोहिमा तक अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करते हुए अपने समूचे नक्शे पर फैली 56 जगहों पर 200 से ज्यादा वैश्विक बैठकों की मेजबानी करेगा. विषयों में विभिन्न देशों को सता रहे मुद्दों का समूचा फलक शामिल होगा—व्यापार और अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय कराधान, वित्तीय समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यटन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और कृषि, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन. इन्हें दो प्राथमिक ट्रैक में संजोया गया है—फाइनेंस ट्रैक, जो आठ कार्य धाराओं से मिलकर बना है, जिसमें 40 बैठकें होंगी; दूसरा शेरपा ट्रैक जो 13 कार्य समूहों से मिलकर बना है, जिसमें 60 सत्र होंगे. फिर 15 मंत्री स्तर की उच्चस्तरीय बैठकें होंगी, जिनमें विदेश और वित्त मंत्रियों की बैठक भी है. इसके अलावा, कारोबार, विज्ञान, लैंगिक मुद्दों और स्टार्ट-अप—जो भारत ने जोड़ा है—से जुड़ी गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए 12 एंगेजमेंट ग्रुप हैं. इनकी 50 से ज्यादा बैठकें, 25 सेमिनार और कार्यशालाएं होंगी. प्रगति मैदान सितंबर 2023 में मुख्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा—विशेष आमंत्रितों के अलावा इसमें 43 राष्ट्रों, सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के आने की उम्मीद है.

इस समूची हलचल से क्या हासिल होगा? यह इसके साथ आने वाले अवसरों और चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा. जी20 अनूठा मंच है. यह निर्णय लेने वाला कार्यकारी निकाय नहीं है, जिसके पास कोई ऐसी सत्ता हो जैसी यूएन, आइएमएफ, विश्व बैंक या डब्ल्यूएचओ सरीखी बहुपक्षीय एजेंसियों के पास है, बल्कि ऐसा निकाय है, जो राष्ट्रों की मंडली में सर्वानुमति बनाने की अद्वितीय जगह देता है, जिसकी बात फिर अक्सर नियम बनाने वाली संस्थाएं आगे बढ़ाती हैं. मसलन, पिछली जुलाई में जी20 ने ओईसीडी के साथ एमएनई के लिए 15 फीसद न्यूनतम कॉर्पोरेट कर का विचार विकसित किया—वही एमएनई जो अन्यथा टैक्स हैवन से काम करके अपने मुनाफों पर कुछ भी देने से पल्ला झाड़ लेते रहे हैं.

जी20 का गठन 1999 में हुआ था जो बताता है कि हाल के दशकों में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती रही. एशियाई वित्तीय संकट ने इसके जन्म की पटकथा रची, जो शुरुआत में वित्त मंत्रियों का मंच था और जिसमें यही देश शामिल थे. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने वैश्विक आर्थिक संकट के बाद 2008 में इसका दर्जा राजनैतिक नेतृत्व के स्तर तक बढ़ाया और इस तरह इसे पूर्ण विकसित भू-राजनैतिक आयाम दिए. विकसित और विकासशील देशों का यह समूह अब विश्व के 85 फीसद जीडीपी, 75 फीसद अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पृथ्वी की 60 फीसद आबादी—कोई 4.6 अरब लोगों—की नुमाइंदगी करता है. इस वैश्विक क्लब के सदस्य जब विचार-विमर्श करेंगे, भारत समारोहों का अगुआ होगा.

यह अहम पदवी क्यों है और महज रस्मी क्यों नहीं है, यह समझने के लिए दुनिया के हालात पर नजर डालिए. तमाम मोर्चों पर हमारे चारों तरफ उथल-पुथल है. महामारी के बाद का परिदृश्य अब भी उस तरफ धकेला जा रहा है जहां हर कोई अगले साल वैश्विक मंदी की भविष्यवाणी कर रहा है. हमारे पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान सहित 70 से ज्यादा देश कमरतोड़ राष्ट्रीय कर्ज के बोझ से दबे हैं. रूस-यूक्रेन टकराव ने कोविड-19 के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में आए व्यवधानों को और तीखा किया है. यह वह पायदान है जहां भारत महज एक प्रस्तोता की तरह नहीं बल्कि ऐसे देश के रूप में प्रवेश कर रहा है जिसके अपने अनूठे पदचिह्न हैं और विश्व मामलों को प्रभावित करने की क्षमता है.

वह ऐसी उभरती शक्ति भी है जिसमें अब भी विकासशील देशों के साथ एकजुटता के जीन हैं. इस तरह हम समाधानों की बात करते हुए ईमानदार बिचौलिए हो सकते हैं. पश्चिमी आलोचक मॉस्को के साथ नई दिल्ली की पुरानी दोस्ती को हितों के टकराव के रूप में देख सकते हैं. तिस पर भी यह भारत को एक पक्ष के रूप में ऐसी गुंजाइश देता है जिससे वह दोनों पक्षों से बात करके युद्ध को खत्म करने की सर्वानुमति पर पहुंच सकता है.

इस हफ्ते हमारी आवरण कथा के लिए ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी व्यापक विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए इस जटिल लेकिन अंतहीन रूप से बेहद दिलचस्प तस्वीर को खोलकर रखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को उसके अनगिनत रंगों में प्रदर्शित करते हुए वैश्विक मामलों में कूटनीतिक जगह की भारत की तलाश को वैधता देने के लिए अगले साल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा. भारत की थीम—'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'—इसी सहऊर्जा की अगुआई करने की इच्छा दर्शाती है. संरक्षणवाद को उलटने के बजाए अपनी कोशिशों को सरल और कारगर बनाना मानवता के लिए एकमात्र रास्ता है.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादकः अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सनः कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टरः राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः मनोज शर्मा
एडिटरः सौरभ द्विवेदी
डिप्टी एडिटरः मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटरः शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
सीनियर असिस्टेंट एडिटरः पवन वर्मा
असिस्टेंट एडिटरः मनीष दीक्षित, प्रदीपिका सारस्वत
वरिष्ठ विशेष संवाददाताः हिमांशु शेखर
विशेष संवाददाताः विनय सुल्तान
राज्य ब्यूरोः पुण्यमित्र (पटना), आनंद चौधरी (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटरः नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टरः चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टरः असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटरः बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंटः राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवघर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चरः प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चरः सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफः अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर (इंपैक्ट): विद्या मेनन, सुपर्णा कुमार
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजरः मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजरः सैयद नवीद (चेन्नै)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसरः विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजरः दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजरः विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजरः राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजरः पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

खंड: 37; अंक: 02; 8-14 दिसंबर, 2022; इस्पेक्ट मंगलवार को प्रकाशित

- संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालयः लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोनः 0120-4807100;
- ग्राहकी चंदा भेजेंः इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- ग्राहक सेवाः कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोनः दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्सः (0120) 4078080. ई-मेलः wecare@intoday.com
- सर्कुलेशन कार्यालयः लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- इंपैक्ट कार्यालयः 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोनः 022-66063355 फैक्सः 022-66063226
- क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालयः ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोनः 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोनः 2212448, 226233, टेलेक्सः 0845-2217 INTO IN. फैक्सः 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालयः एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादकः राज चेंगप्पा

सुर्खियां

कर्नाटक/महाराष्ट्रः बेलगावी की जंग
पेज 5

राजस्थानः साधु नहीं सुरक्षित
पेज 12

भीतर

सवाल+जवाब/अनुष्का शंकरः 'लौटने को बेताब हूं मैं'
पेज 68

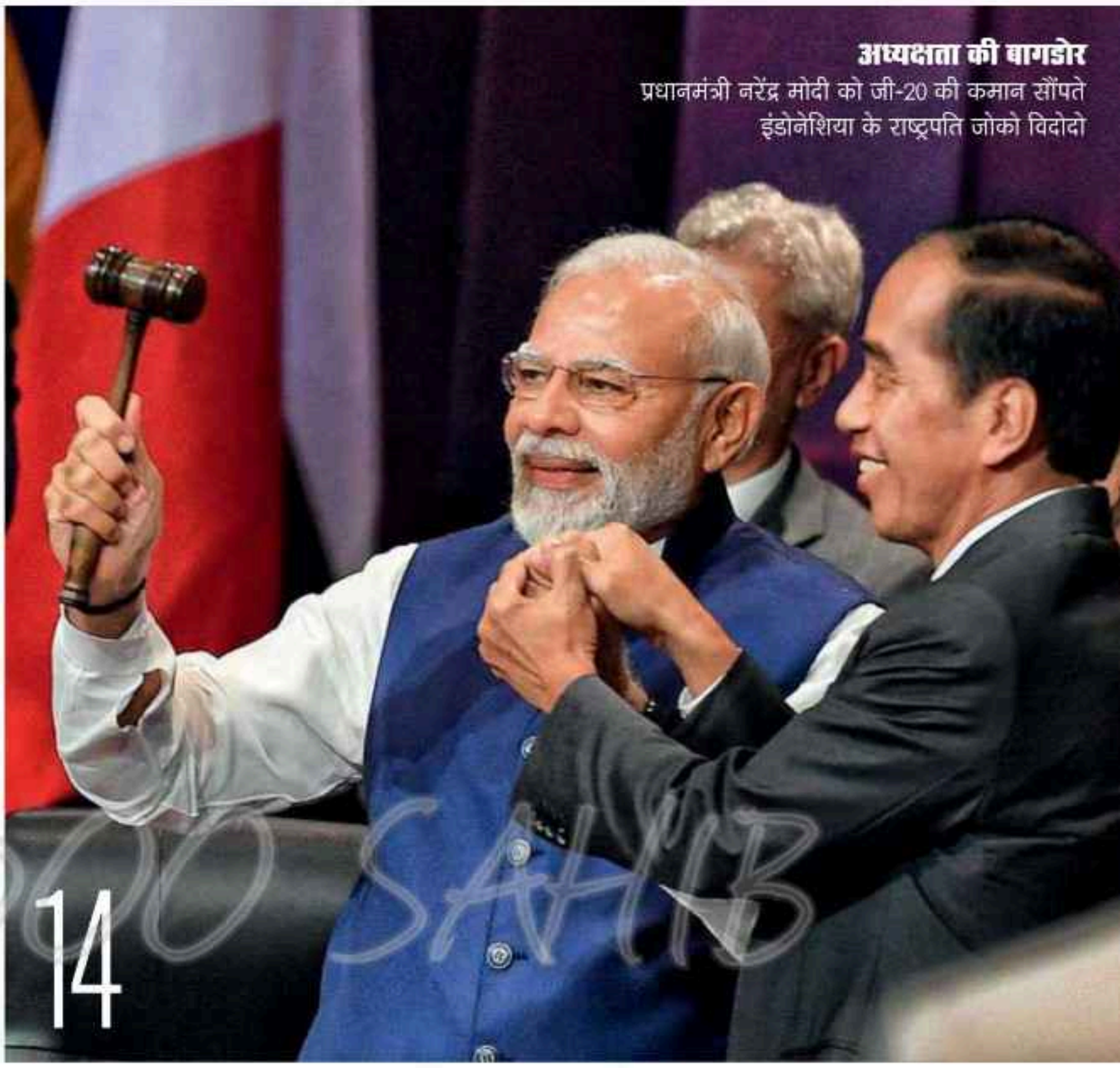

आवरण कथा

भारत का वक्त

जी-20 के अध्यक्ष के नाते भारत मुख्य वैश्विक सवालों पर सर्वानुमति बनाने की पहल कर सकता है, और दुनिया के अगुआ के तौर पर उभर सकता है.

उत्तर प्रदेश

32 विधानसभा में नया विधान

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पेपरलेस कामकाज सरीखी कई अनोखी पहल शुरू की हैं.

बिहार

44 ये धुआं कहां से उठता है

नवंबर में बिहार के कई जिले वायु प्रदूषण के बड़े हॉट स्पॉट बनकर उभरे.

आवरणः **नीलांजन दास**

पाठकों के लिए सूचनाः कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आते होंगे. ये विज्ञापन हैं और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

अर्थव्यवस्था: क्यों ठिठक गई आर्थिक वृद्धि
पेज 7

समाचार सार: बदल गए रिश्ते
पेज 10

सुर्खियां

राजस्थान: साधु नहीं सुरक्षित
पेज 12

मध्य प्रदेश: भोपाल में सुधरती चाल
पेज 13

कर्नाटक/महाराष्ट्र

बेलगावी की जंग

अजय सुकुमारन

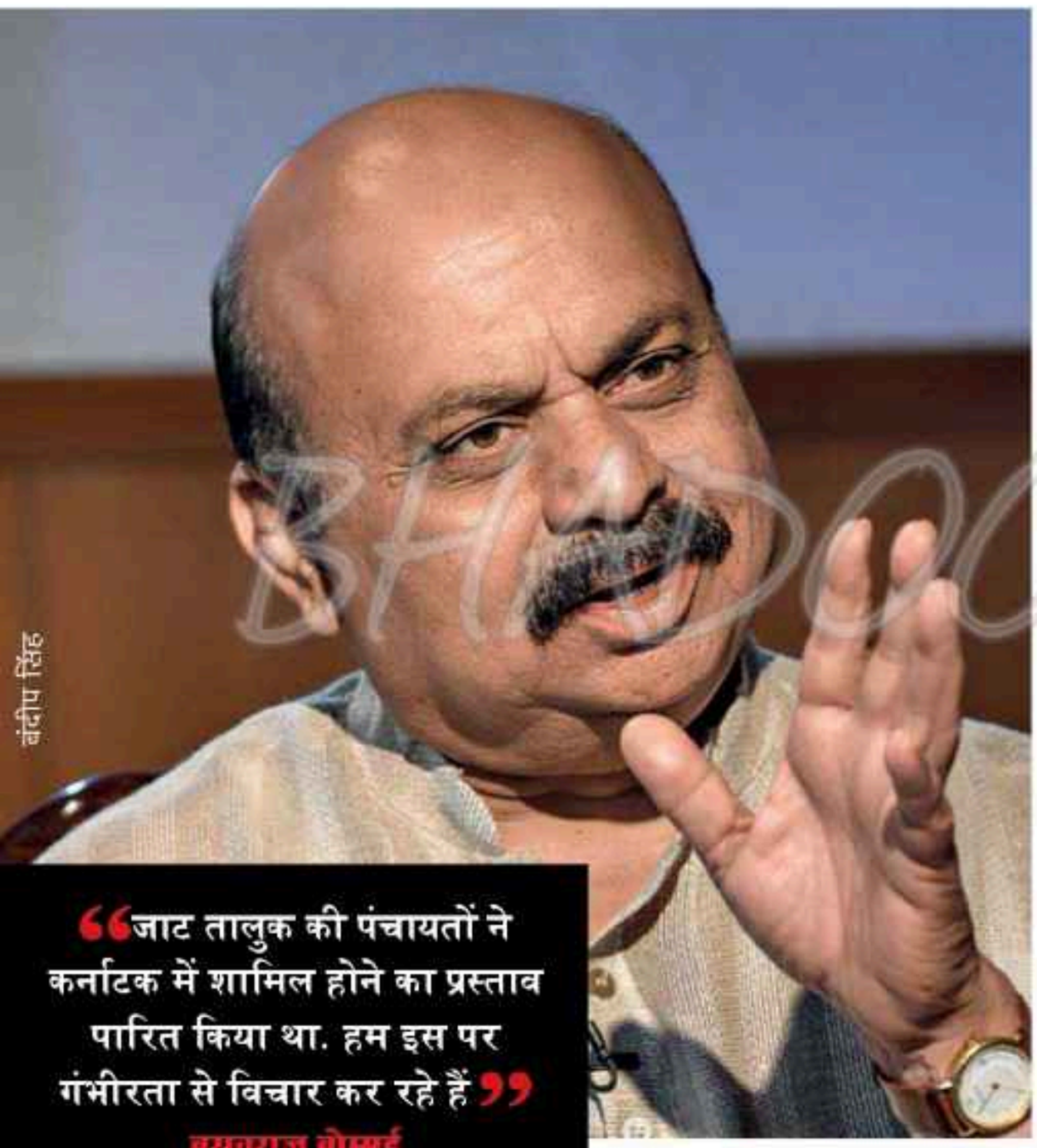

बंदीप सिंह

“जाट तालुक की पंचायतों ने कर्नाटक में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया था. हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं”

बसवराज बोम्मई
मुख्यमंत्री, कर्नाटक

“सीमावर्ती इलाकों के हर भाई को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है”

एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

राज्यों के बीच के विवादों में जैसा होता है, बेलगावी (पूर्व में बेलगाम) के दशकों से खदबदाते मुद्दे में भी समय-समय पर उबाल आ जाता है. पिछले दिसंबर और उससे एक साल पहले भी ऐसा हुआ था. 1950 के दशक के मध्य में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के बंटवारे के वक्त की कई चीजें दोहराई गईं. सभी मौकों पर इस सीमावर्ती जिले में तनाव बढ़ गया था. यह जिला कर्नाटक में है, पर महाराष्ट्र दशकों से इस पर दावा जताता रहा है, इस भावनात्मक आधार पर कि वहां मराठी बोलने वालों की काफी आबादी है. इस साल यह विवाद फिर उभर आया है. सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक मुकदमे की 30 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले दोनों पक्ष जोर आजमाइश के लिए तैयार थे.

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीमा के इस विवाद पर सभी दलों के नेताओं के पैनल से मुलाकात की और इस जिले को महाराष्ट्र में मिलाने के संघर्ष में शामिल परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने का वादा किया. बेलगावी को पाने के लिए इस 'उकसावे' पर तीखी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि कन्नड़ बोलने वालों के लिए यह इतना ही भावनात्मक मुद्दा है. कर्नाटक में शिंदे के समकक्ष बसवराज बोम्मई ने पलटवार किया कि सभी सीमा विवाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के साथ समाप्त हो गए थे. लेकिन, अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, इसलिए कर्नाटक की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने पक्ष में अच्छी तरह से बहस करना है. उन्होंने यह भी कहा, ''हमारा

पक्ष मजबूत है.'' कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी सीमा पार से कर्नाटक में शामिल होने के लिए संघर्षरत लोगों के लिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और वहां के कन्नड़-माध्यम के स्कूलों के लिए धन उपलब्ध कराने की बात कही. बोम्मई ने कर्नाटक सीमा और नदी संरक्षण आयोग के खाली पड़े पद पर नया अध्यक्ष नियुक्त करते हुए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव पेश किया है.

असल में बेलगावी को लेकर यह लड़ाई तभी से चली आ रही है जब भारत ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का फैसला लिया था. पूर्व में निजाम के राज्य हैदराबाद और सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन रहे मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसीडेंसी के अधीन रहे जिलों को मिलाकर 1956 में नया मैसूर राज्य (कर्नाटक का 1973 से पहले का नाम) बनाया गया था. इस प्रक्रिया में बेलगाम (चांदगढ़ तालुक को छोड़कर), बीजापुर, धारवाड़ और कनारा जिलों को बंबई से हटाकर नए राज्य में स्थानांतरित किया गया. लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवाद के खत्म न होने के कारण केंद्र सरकार ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए अक्तूबर 1966 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन को लेकर एक-सदस्यीय आयोग का गठन किया.

अगस्त 1967 में आई महाजन आयोग की रिपोर्ट में संस्तुति की गई कि 264 गांवों को मैसूर से महाराष्ट्र में और 247 गांवों को मराठा पक्ष से मैसूर में स्थानांतरित किया जाए. रिपोर्ट के अनुसार, निप्पानी, खानापुर और नंगड़ जैसे शहरों को महाराष्ट्र में जाना था, जबकि मैसूर को दक्षिण शोलापुर, अक्कलकोट और जाट के तालुका मिलने थे. बेलगावी शहर के लिए उन्होंने सिफारिश की थी कि इसे दक्षिणी राज्य में रहने दिया जाए. इससे क्षुब्ध महाराष्ट्र ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज करने की मांग की तो कर्नाटक ने इसे लागू करने की मांग की. तभी से उलझा यह मामला 1986 में सीमा आंदोलन के रूप में ऐसे भड़का कि नौ लोगों की जान चली गई.

बेलगावी एक कृषि प्रधान जिला है, जो चीनी उद्योग के लिए मशहूर होने के साथ ही ढलाई कारखानों का बड़ा केंद्र है. इस जिले में 24 चीनी कारखाने हैं. बेंगलूरू से मुंबई के रास्ते में लगभग बीचोंबीच बसे बेलगावी शहर में मराठियों की काफी बड़ी आबादी है और यह महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) नामक सियासी संगठन का केंद्र रहा है. मराठी भाषी क्षेत्रों को एकजुट करने के एजेंडे के साथ 1948 में गठित एमईएस इस क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर जीतता रहा. 1980 के दशक में बेलगावी नगर निगम पर भी एमईएस का नियंत्रण था और उस दौरान नगर परिषद ने महाराष्ट्र के साथ विलय के प्रस्ताव भी पारित किए थे. 2005 में जब एमईएस के नेतृत्व वाली नगर परिषद ने ऐसा एक और प्रस्ताव पारित किया, तो बेंगलूरू में कन्नड़ आंदोलनकारियों ने बेलगावी के तत्कालीन महापौर विजय मोरे के साथ मारपीट करके उनके चेहरे पर स्याही पोत दी. एक साल पहले भी कन्नड़ आंदोलनकारियों ने एमईएस के एक अन्य नेता, दीपक दलवी पर भी इसी तरह काली स्याही फेंकी थी क्योंकि उन्होंने बेलगावी में कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आयोजन किए जाने के विरोध में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था.

बेलगावी विधानमंडल सत्र का आयोजन भी विवाद का नतीजा था. बेलगावी शहर समेत कर्नाटक के 865 गांवों की मांग करने वाले महाराष्ट्र ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया. इसके जवाब में कर्नाटक ने बेलगावी को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित कर दिया था. 2006 के बाद से दिसंबर में होने वाले विधायी सत्र इस शहर में होते रहे हैं. बेंगलूरू के विधान सौध की प्रतिकृति के तौर पर यहां राज्य का दूसरा सचिवालय भी बनाया गया. 2014 में राज्य के मुख्य शहरों के कन्नड़ नामों को पुनर्स्थापित करने के लंबित प्रस्ताव को केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद बेंगलोर बेंगलूरू, मैसूर मैसूरु और बेलगाम बेलगावी बन गया. बेलगाम को बेलगावी किया जाना महाराष्ट्र को काफी अखरा.

उस दौर में ऊंचे सुरों में उछला यह मुद्दा पिछले एक दशक में थोड़ा शांत हुआ था. बेलगावी जिला कन्नड़ संगठन ऐक्शन कमेटी के अध्यक्ष अशोक चंदरगी बताते हैं कि 1990 के दशक से एमईएस बेलगावी में भाजपा और कांग्रेस की तुलना में पिछड़ता रहा है. वे कहते हैं, ''यह एक भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन आम लोग इसमें राजनीतिक एजेंडा देखते हैं. हमने कई बार स्पष्ट किया है कि सीमा के मसले पर जनता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए.''

दिसंबर 2019 में तब महाराष्ट्र के नए-नए मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे ने 'कर्नाटक के कब्जे वाले' मराठी भाषी क्षेत्रों को एकजुट करने की अपनी प्रतिज्ञा के साथ यह वाक्युद्ध फिर छेड़ दिया. चुनावों में एमईएस का समर्थन करने वाली शिवसेना के लिए सीमा

"महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक में नहीं जाएगा. बेलगाम, करवार, निप्पानी समेत मराठी बोलने वाले इलाकों को हासिल करने के लिए राज्य सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी"

देवेंद्र फड़नवीस
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

"कर्नाटक भाजपा को अब तो जाग जाना चाहिए और आगे की राह पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए"

सिद्दारमैया
पूर्व-मुख्यमंत्री, कर्नाटक (कांग्रेस)

"अगर कर्नाटक बेलगाम, करवार और निप्पानी छोड़ने को तैयार है तो हम चर्चा कर सकते हैं कि उन्हें क्या दिया जा सकता है"

शरद पवार
एनसीपी प्रमुख

का मुद्दा उसके मराठी गौरव के मूल मुद्दे से निकटता से जुड़ा हुआ है (इसीलिए दिवंगत बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करते हुए शिवसेना के एक धड़े का नेतृत्व कर रहे मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे की भी इसे आगे बढ़ाने की सियासी बाध्यता है). यह स्थिति दोनों राज्यों में सत्ता पर काबिज भाजपा को मुश्किल में डालने वाली है. इसलिए जब 22 नवंबर को बोम्मई ने कहा कि वे जाट तालुक में ग्राम पंचायतों से कर्नाटक में विलय के लिए पारित प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने जवाब दिया कि वह प्रस्ताव एक दशक पुराना है और ''महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक में नहीं जाएगा.''

सुप्रीम कोर्ट ने अब तक केवल बुनियादी सवालों पर विचार किया गया है. एक वरिष्ठ वकील का कहना है कि कर्नाटक का तर्क इस बात पर आधारित है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के माध्यम से नए राज्य बनाने या सीमाओं को बदलने की संसद की शक्ति के दृष्टिगत यह वाद मेंटेनेबल नहीं है. वहीं, महाराष्ट्र संविधान के अनुच्छेद 131 का उल्लेख कर रहा है, जिसमें राज्यों के बीच विवादों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है.

इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल (भाजपा) और शंभुराज देसाई (शिवसेना-शिंदे गुट) ने एमईएस कार्यकर्ताओं के निमंत्रण पर 3 दिसंबर को बेलगावी जाने की योजना बनाई है. इसके जवाब में, अशोक चंदरगी जैसे कन्नड़ आंदोलनकारी बोम्मई से आग्रह कर रहे हैं कि जैसे को तैसा जवाब देते हुए वे ऐसा ही प्रतिनिधिमंडल जाट इलाके में भेजें. जाहिर है, सीमा का यह मुद्दा अभी उलझा रहेगा. ■

अर्थव्यवस्था

क्यों ठिठक गई आर्थिक वृद्धि

एम.जी. अरुण

कई वैश्विक एजेंसियों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने भी 2022-23 के वित्तीय साल तथा आगे के लिए भारत की वृद्धि के अनुमानों में फेरबदल किया है. सभी ने इस हकीकत की तरफ ध्यान दिलाया कि अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के साथ-साथ, ऊंची मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है और इससे घरेलू मोर्चे पर मांग में और नरमी आएगी. अब जब 1 फरवरी को केंद्र का सालाना बजट पेश करने की तारीख नजदीक आ रही है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाते हुए बेहतर रोजगार सृजन के जरिए मांग को बढ़ावा देने की तत्काल जरूरत है.

मसलन, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक भारत की आर्थिक वृद्धि को अगले साल धीमी पड़ते देख रहा है. इसके पीछे उसने उधारी की ऊंची लागत और महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने से हुए फायदों के कम होने का असर उपभोक्ता मांग पर पड़ने का हवाला दिया है. वृद्धि का पूर्वानुमान घटाते हुए एक रिपोर्ट में उसने कहा कि 2023 के कैलेंडर साल में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अब केवल 5.9 फीसद बढ़ने की उम्मीद है, जबकि उसने पहले 6.9 फीसद वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था. इस बीच रेटिंग फर्म क्रिसिल ने भी 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.3 फीसद से घटाकर 7 फीसद कर दिया. क्रिसिल ने 2024 के वित्तीय साल में भी भारत की जीडीपी वृद्धि पहले के अनुमान 6.5 फीसद से धीमी पड़कर 6 फीसद पर आने की आशंका जाहिर की है, खासकर तब जब वैश्विक

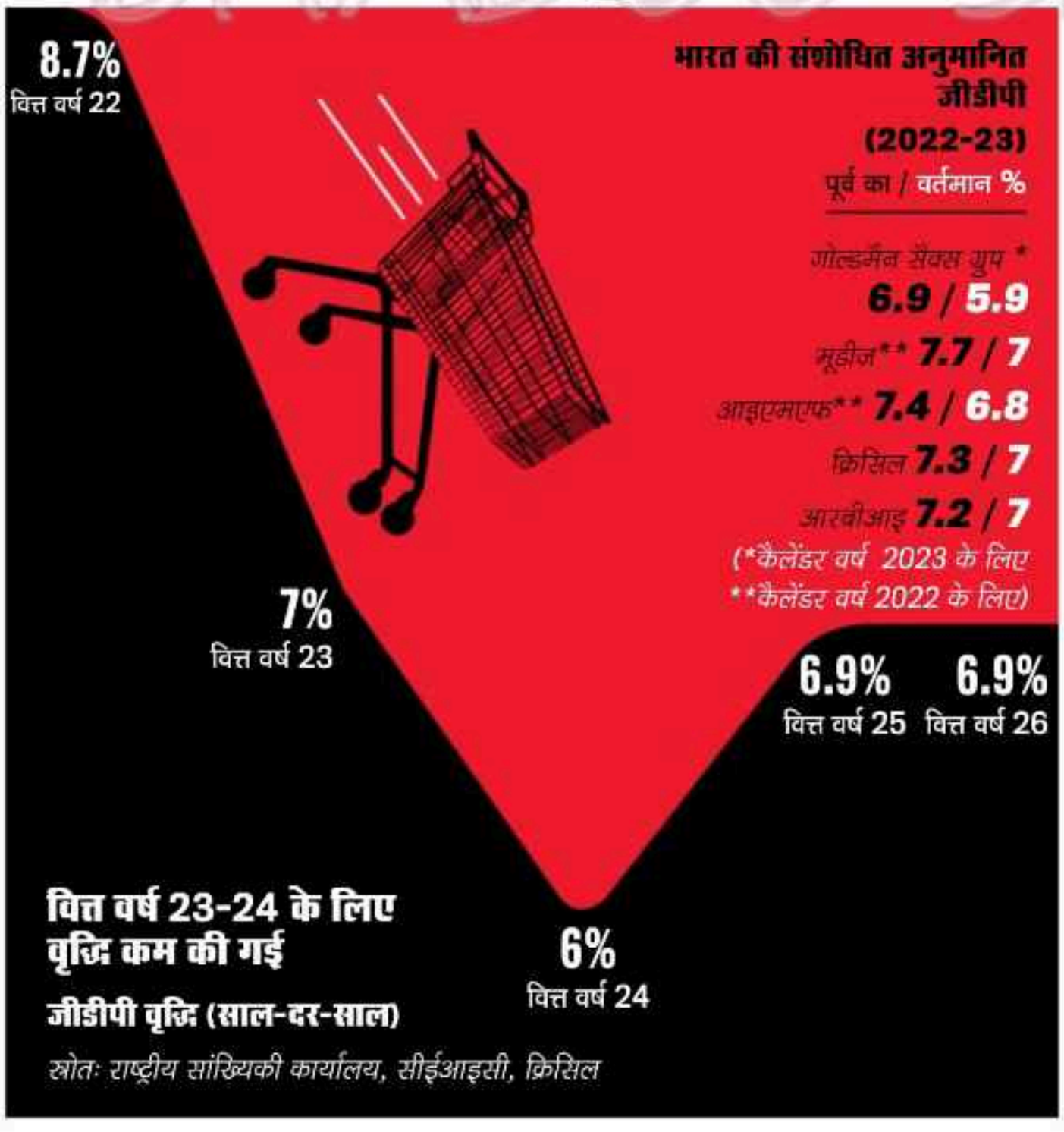

वृद्धि अगले वित्तीय साल और भी तेजी से गिरने के आसार हैं. इसके अलावा, उसने कहा कि घरेलू मांग पर भी दबाव आ सकता है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ज्यादा बोझ उपभोक्ता पर आ जाएगा और रिटेल तथा हॉस्पिटैलिटी सरीखी अनुबंध-आधारित सेवाओं की बहाली के फायदे फीके पड़ते जाएंगे. नवबंर में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान पहले के 7.7 फीसद से घटाकर 7 फीसद कर दिया. आरबीआइ ने भी 2022-23 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए इसे 7.2 फीसद से घटाकर 7 फीसद कर दिया. इस बीच मौजूदा वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के महज 6.5 फीसद की दर से बढ़ने के संकेत हैं.

भारत के बारे में सामान्य स्थिति यही है कि चारों ओर के अंधेरे के बीच वह अब भी एक उजला सितारा है. खासकर तब जब अमेरिका सहित विकसित दुनिया के कई देशों पर मंदी की छाया मंडरा रही है. मगर ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है. गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था के दोबारा खुलने के प्रभाव फीके पड़ने और उसके साथ उधारी की ज्यादा ऊंची लागत से देश की वृद्धि की रफ्तार पर असर पड़ेगा. रिपोर्ट कहती है, ''वृद्धि शायद दो आधे-आधे हिस्सों की कहानी होगी. जिसमें अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के प्रभाव के धीमे पड़ने और मौद्रिक सख्ती का असर घरेलू मांग पर पड़ने के कारण पहली छमाही धीमी रहेगी. दूसरी छमाही में वैश्विक वृद्धि की बहाली, शुद्ध निर्यात में अड़चनों के कम होने और निवेश चक्र में तेजी आने के साथ वृद्धि के रफ्तार पकड़ने की संभावना है.''

क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी पूरे साल की जीडीपी में गिरावट की तीन वजहें बताते हैं. वे कहते हैं कि इस साल के अनुमान घटाने की एक बड़ी वजह यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर भारत के निर्यात पर पड़ने ही लगा है. पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में निर्यात 24.8 फीसद बढ़ा था, जो दूसरी तिमाही में घटकर महज 2.8 फीसद की बढ़ोतरी पर आ गया. अक्तूबर में निर्यात एक साल पहले के मुकाबले 16.7 फीसद कम था. दूसरी बात यह है कि आरबीआइ ब्याज दरें बढ़ाता रहा है, जिसके नतीजे अगले साल महसूस किए जाएंगे. जोशी कहते हैं, ''इनका असर वृद्धि पर पड़ेगा और प्रभाव आगे तक जाएंगे. इसका असर सरकारी निवेश पर नहीं पड़ेगा.'' तीसरी बात यह है कि निजी निवेश की व्यापक बहाली के कोई संकेत नहीं हैं. बुनियादी ढांचे से जुड़े, स्टील और सीमेंट सरीखे कुछ क्षेत्रों में निवेश देखा जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं में नहीं. जोशी ने *इंडिया टुडे* को बताया, ''उस मोर्चे पर निवेश अभी देखने और इंतजार करने की मुद्रा में है. जब तक अनिश्चितता कम नहीं होती, खासकर वैश्विक मोर्चे पर, निजी क्षेत्र निवेश के लिए पर्याप्त उत्साहित नहीं होगा.''

अहम कारक

- सुस्त पड़ता वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, संभावित मंदी
- यूक्रेन में युद्ध का लंबा चलना; आने वाले महीनों में और तीव्र होने की संभावना
- अत्यधिक महंगाई, जिससे उपभोक्ता खर्च में कटौती हो रही है
- भारत से घटते निर्यात, जिससे व्यापार घाटा बढ़ेगा
- महंगाई की ज्वाला शांत करने के लिए आरबीआइ की तरफ से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी, जिससे मांग चौपट हो रही है
- क्षमता का कम इस्तेमाल, जिससे निजी निवेश ढीला पड़ा

जोशी कहते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने अभी दो जोखिम हैं. पहला यह कि रूस-यूक्रेन टकराव और तकलीफदेह होता जा रहा है, और दूसरा, उन्नत देशों में महंगाई में कमी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे. वे कहते हैं, ''इसलिए केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें उस निशान से ज्यादा बढ़ानी होंगी जितनी उन्हें बढ़ानी चाहिए.'' अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने अक्तूबर में भविष्यवाणी की थी कि एक तिहाई दुनिया इस साल या अगले साल मंदी की चपेट में होगी. आइएमएफ के इकोनॉमिक काउंसलर पियर-ओलिविए ग्रुंचैस ने कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के साथ एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, ''इस साल के झटके उन आर्थिक जख्मों को उधेड़ देंगे जो महामारी के बाद अभी आधे-अधूरे ही भरे थे.'' उन्होंने आगाह किया कि तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं—अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन—ठप ही रहेंगी. ग्रुंचैस ने लिखा, ''सबसे खराब स्थिति आना अभी बाकी है और 2023 में बहुत से लोग मंदी की महसूस करेंगे.''

घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए बेशक कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, जो कोविड-19 महामारी के बाद बहाली की तरफ इशारा करती हैं. मासिक वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगातार आठ महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जमा हुआ. सितंबर में 8.3 करोड़ ई-वे बिल बनाए गए, जबकि अगस्त में यह संख्या 7.7 करोड़ थी. यह व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर हलचल का संकेत है. औद्योगिक उत्पादन भी सितंबर में उम्मीद से ज्यादा 3.1 फीसद बढ़ा. बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस कहते हैं, ''सवाल यह है कि साल के बाकी छह महीने खपत कायम रह पाएगी या नहीं, इसका असर वृद्धि की कुल संभावनाओं पर पड़ेगा.''

केंद्र की तरफ से किए गए खर्चों के मुकाबले राज्य स्तर पर खर्चों में भी ढील आई है. वे कहते हैं, ''केंद्र सरकार जो खर्च कर रही है, उसे देखिए, और देखिए कि पहले महीने में बजट का कितना हिस्सा खत्म कर दिया गया. केंद्र ने काफी अच्छा काम किया है, तकरीबन 40-45 फीसद. मगर राज्यों ने महज 20-25 फीसद ही किया.'' वे यह भी कहते हैं कि राज्य खर्चों को इसलिए टाल रहे हैं ताकि राजकोषीय घाटे के अपने आंकड़ों से न चूक जाएं और वे शायद साल के आखिर में ही निवेश करना शुरू करेंगे.

इतना ही नहीं, निर्यात में गिरावट की वजह से व्यापार घाटा (हमारे निर्यात और आयात के मूल्य का अंतर) बढ़ रहा है और इसके बदले में इसका असर भी वृद्धि के आंकड़ों पर पड़ेगा. बेहतर वृद्धि हासिल करने का एक निश्चित तरीका रोजगार सृजन पर ज्यादा एकाग्रता से ध्यान देना है. यह उपभोग या खपत में लगातार बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने का एक तरीका है मैन्युफैक्चरिंग में नई जान फूंकना, जिससे ज्यादा आमदनी वाली नौकरियां पैदा होंगी, और मांग बढ़ाने के लिए यह जरूरी हैं. वे कहते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अगला केंद्रीय बजट पेश करेंगी, तो यही वह क्षेत्र है जिस पर उन्हें पूरा ध्यान देना होगा. ■

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

समाचार सार

बदल गए रिश्ते

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** और उपमुख्यमंत्री **केशव प्रसाद मौर्य** के बीच तल्खी की खबरें सुर्खियां बनी थीं. लेकिन योगी-2.0 में रिश्ते कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे हैं. प्रयागराज में 24 नवंबर को आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने में कोई कोताही नहीं बरती. मुख्यमंत्री योगी ने सम्मेलन के मंच से केशव मौर्य को प्रयागराज की धरती का पुत्र बताया. वहीं पहले की सभाओं में केवल प्रदेश सरकार का नाम लेने वाले केशव मौर्य ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार न कहकर हर बार योगी सरकार कहा. इतना ही नहीं, उपमुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी को गोरखपुर की तरह प्रयागराज की चिंता करने वाला भी बताया.

एएनआइ

अविराम मोदी

नवंबर में भाजपा के बड़े नेताओं ने गुजरात चुनाव में इतने जोर-शोर से प्रचार किया कि इसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है. पार्टी मामलों में अक्सर खामोश माने जाने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की आवाज बैठ गई, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कड़ी मेहनत के चलते सेहत बिगड़ने से वीकेंड में वडोदरा की जनसभा छोड़नी पड़ी. अकेले अपवाद पीएम **नरेंद्र मोदी** हैं. भाजपा के कर्ताधर्ता हैरान हैं कि 72 की उम्र में भी पीएम इतना व्यस्त कार्यक्रम कैसे पूरा कर लेते हैं. जीतने की अथक इच्छाशक्ति इसे ही कहा जाता है.

गुलाम-ए-मुस्तफा..

राजस्थान में बीते दिनों दो मंत्रियों के एक दूसरे को गुलाम ठहराने वाले बयानों ने सुर्खियां बटोरी थीं. अब इन दोनों मुस्तफाओं की दोस्ती चर्चा में है. यह दोस्ती बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की भूमिका सरीखी है. कांग्रेस के बहुमत वाले जयपुर हेरिटेज नगर निगम में समितियों के गठन में कहीं दूसरे विधायक बाजी न मार जाएं इसलिए दोनों मंत्री साथ आ गए हैं. जलदाय मंत्री **महेश जोशी** और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री **प्रताप सिंह खाचरियावास** निगम की समितियों में अपना दबदबा चाहते हैं तो विधायक अमीन कागजी और रफीक खान अपनी पसंद की समितियां बनाना चाहते हैं. ऐसे में दोनों मंत्री 'बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले' वाली मुद्रा में आ गए हैं.

अंग्रेजी का चक्कर

अदालतें प्रशासन के लिए आदेश जारी करती हैं, प्रशासन वाले इतने बिजी होते हैं कि इन आदेशों को लागू कराना ही भूल जाते हैं. फिर जब अदालतों को याद आता है कि उनके आदेशों का पालन नहीं हुआ तो प्रशासन को बुलाया जाता है. ऐसे में प्रशासन के लोग या तो चुपचाप फटकार सुनते हैं, या कोई बहाना बना देते हैं. हाल में पटना के एसएसपी ने अदालत के सामने अजीबोगरीब बहाना पेश कर दिया: माइ लॉर्ड, थानेदार को अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है. अदालती आदेश अंग्रेजी में होते हैं, इसलिए थानेदार उनका पालन नहीं करा पाते.

विदेशी हाथ

उत्तराखंड नवीनतम भाजपा-शासित राज्य है जिसने वृद्धि की राह प्रशस्त करने के लिए ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म की मदद ली है. मुख्यमंत्री **पुष्कर सिंह धामी** ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को अगले पांच साल में दोगुना करने का खाका तैयार करने के लिए मैकिंसी को चुना है. आरएसएस रोड़े अटका सकता है, पर आगे का रास्ता तो यही लग रहा है. अगस्त में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने यही काम डेलॉइट को सौंपा. आरएसएस के एक विचारक ने कहा कि अर्थव्यवस्थाओं को 'आत्मनिर्भर' बनाने का जतन करने से पहले विचार विकसित करने में 'आत्मनिर्भर' होने की जरूरत है.

—आशीष मिश्र, जुमाना शाह, पुष्यमित्र, अनिलेश महाजन और आनंद चौधरी

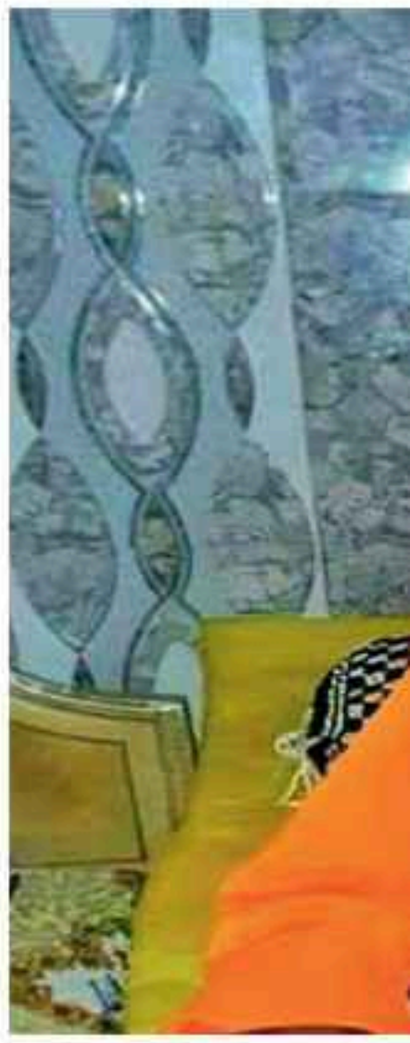

राजस्थान

साधु नहीं सुरक्षित

राजस्थान में पांच साल के भीतर 30 से ज्यादा साधुओं व पुजारियों की मौत

आनंद चौधरी

राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे का हीरा की बस्सी क्षेत्र. 20 नवंबर की रात 8:30 बजे का वक्त. एक पुजारी दंपती अपनी दुकान के पीछे बैठकर खाना खा रहे थे. उसी समय कुछ लोगों ने पुजारी नवरत्न प्रजापत व उनकी पत्नी जमना देवी को पेट्रोल बम फेंककर जिंदा जला दिया. 80 फीसद जल चुके नवरत्न की छह दिन बाद 26 नवंबर को उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में मौत हो गई. जमना की हालत अब भी गंभीर है. पुजारी के पुत्र मुकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि हत्याकांड के पीछे क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह और सरपंच हरदेव भाट का हाथ है. मुकेश ने बताया कि विधायक व सरपंच नेशनल हाइवे-8 पर कामली घाट स्थित पेट्रोल पंप के सामने मंदिर की जमीन पर दुकानें बनाना चाहते हैं. नवरत्न इसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई. ऐसी ही एक घटना करीब दो साल पहले करौली जिले के बूकना गांव में हुई, जहां पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जमीन विवाद के चलते पेट्रोल डालकर जला दिया गया. 20 जुलाई, 2022 को भरतपुर के पसोपा गांव में साधु विजयदास ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली. ब्रज चौरासी परिक्रमा क्षेत्र में अवैध खनन के विरोध में आग की लपटों में घिरकर राधे-राधे बोलते हुए, दौड़ लगाते विजयदास को पूरी दुनिया ने देखा था.

राजस्थान में दबंगों के साथ विवाद के चलते पिछले चार साल में 30 से ज्यादा साधु-संत और पुजारी अपनी जान गंवा चुके हैं. इस साल अब तक 12 साधुओं और पुजारियों की हत्या, आत्महत्या और मौत के मामले सामने आ चुके हैं. राजस्थान में इन मौतों के पीछे सबसे बड़ा कारण जमीनी विवाद है. ऐसे कई मामलों में प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए हैं.

जालोर जिले के राजपुरा गांव में 6 अगस्त, 2022 को संत रविनाथ महाराज ने फांसी लगाकर जान दे दी. भीनमाल से भाजपा विधायक पूराराम चौधरी पर संत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा. बताया जा रहा है कि विधायक का रविनाथ के साथ जमीन को लेकर विवाद था. इस मामले

राजस्थान में इन मौतों के पीछे सबसे बड़ा कारण जमीनी विवाद हैं. ऐसे कई मामलों में प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए हैं

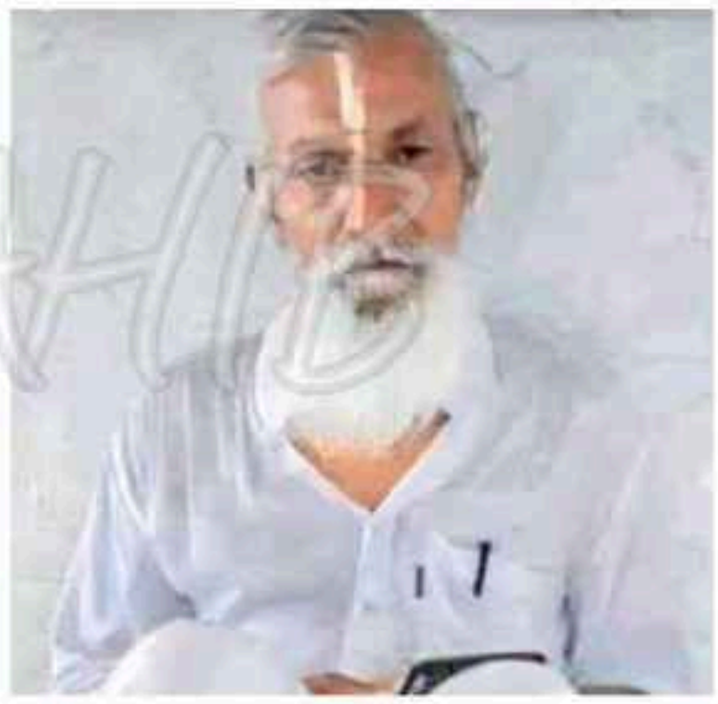

अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह

ब्रज के परिक्रमा क्षेत्र में सालों से चल रहे अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन करते हुए बाबा विजयदास ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल कर आत्मदाह कर लिया

की जांच राज्य की सीआइडी (सीबी) कर रही है. राजस्थान पुलिस के एडीजी (क्राइम) रवि प्रकाश मेहरड़ा कहते हैं, ''हत्या के ज्यादातर मामलों में बड़ा कारण जमीन विवाद ही रहता है. हाल में सामने आए पुजारियों की हत्या के मामलों में भी जमीन और मंदिर पर कब्जे का ही विवाद रहा है. अपराध के मामलों में तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जमीन के मामले राजस्व विभाग के अधीन आते हैं, इनमें पुलिस कुछ नहीं कर पाती.''

राजस्थान में ये मौतें सियासी मुद्दा बनती जा रही हैं. प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अभी साल भर बाकी है, लेकिन प्रतिपक्षी भाजपा इस मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार पर अभी से हमलावर नजर आ रही है. राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी भाजपा की चार्जशीट में अशोक गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी कहते हुए आरोप लगाया गया है कि पिछले चार साल के दौरान प्रदेश में 24 साधु-संतों की हत्या हुई है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सतीश पूनियां का कहना है, ''राजस्थान में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि यहां देवी-देवताओं के उपासक भी सुरक्षित नहीं हैं. मंदिरों के पुजारियों और संतों को या तो जला दिया जाता है या उन्हें खुद जलने पर मजबूर कर दिया जाता है.''

भाजपा के इन हमलों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पलटवार करते हैं, ''भाजपा केवल दिखावे के लिए हिंदुओं और संतों के नाम इस्तेमाल करती है. उसके लिए सनातन धर्म सिर्फ सियासी शोर-शराबे से ज्यादा कुछ नहीं.'' ■

मध्य प्रदेश जोड़ो यात्रा >
मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ, राहुल गांधी के साथ

मध्य प्रदेश

भोपाल में सुधरती चाल

राहुल नरोन्हा

मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने के साथ ही कांग्रेस की राज्य इकाई को अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू करने का मौका मिल गया है. ये चुनाव अगले साल करीब-करीब इन्हीं दिनों होने हैं. 23 नवंबर को बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में यात्रा का प्रवेश हुआ था. राज्य में इस यात्रा के 12 दिवसीय कार्यक्रम के मार्ग में मालवा और निमाड़ क्षेत्रों के छह जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्र पड़ रहे हैं. यहां की आदिवासी बहुल सीटों को छोड़कर, जहां कांग्रेस अब भी मजबूत है, दोनों ही क्षेत्रों को भाजपा का गढ़ माना जाता है. 2018 में कांग्रेस ने इंदौर और उज्जैन संभागों (दोनों मालवा में) की 66 सीटों में से 34 पर जीत हासिल की थी. ऐसे में यह यात्रा यहां कांग्रेस की छवि को चमकाने की कोशिश का अच्छा मौका है.

राहुल गाधी के शब्दों में यात्रा के घोषित उद्देश्यों में से एक है ''घृणा, हिंसा और भय के खिलाफ'' खड़े होना. इस साल अप्रैल में सांप्रदायिक दंगे का शिकार रहे खरगोन से जब यात्रा गुजरी तो पार्टी को यह बात वास्तविक संदर्भों में स्थापित करने का मौका मिला. इस दौरान गत 25 नवंबर को कथित रूप से पाकिस्तान-समर्थक नारे से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के साथ एक और विवाद खड़ा हो गया. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत इस मुद्दे को उछाला, जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर ''छेड़छाड़ वाला वीडियो'' डालने का आरोप लगाया. हालांकि, यात्रा के केंद्र में मुख्यत: आदिवासी रहे. 2018 में कांग्रेस को आदिवासी समुदायों का लगभग एकतरफा समर्थन मिलने के बाद से भाजपा प्रतीकवाद और नीतियों के तालमेल से उन्हें लुभाने की कोशिश में लगी है. पिछले 26 वर्षों से लंबित रही पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा) नियमावली का कार्यान्वयन भी इन प्रयासों में मुख्य रूप से शामिल है.

खंडवा में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों से लड़ने वाले आदिवासी प्रतीक पुरुष टांटिया भील के घर की यात्रा के दौरान राहुल ने 24 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ''अंग्रेजों का समर्थन'' करने का आरोप लगाया था. संयोगवश, टांटिया उन आदिवासी नायकों में शामिल हैं जिनके बारे में भाजपा का आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने उनकी उपेक्षा की है. आदिवासी समुदायों के बीच कांग्रेस को होने वाले संभावित लाभ का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने अपनी ओर से 'पेसा जागरूकता यात्रा' की घोषणा की है.

भारत जोड़ो यात्रा से राज्य कांग्रेस को अंदरूनी कलह पर काबू पाने की उम्मीद है. कमलनाथ ने यात्रा के बुरहानपुर चरण की जिम्मेदारी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह को दी और खरगोन के लिए अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अरुण यादव को नियुक्त किया. राहुल की मौजूदगी से पार्टी के विभिन्न नेताओं के बीच मतभेद दूर होने की उम्मीद है. कमलनाथ का कहना है कि ''इस यात्रा से आदिवासी समुदायों के साथ कांग्रेस का पुराना जुड़ाव और मजबूत होगा और भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का प्रभाव भी घटेगा.''

यात्रा के शेष हिस्सों से अन्य अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है. इनमें ओंकारेश्वर में नर्मदा आरती करने, महाकाल मंदिर, एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे और दरगाह-ए-हकीमी की यात्रा के साथ-साथ, बुरहानपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय के एक धार्मिक स्थल और महू में डॉ. बी.आर. आंबेडकर के जन्मस्थान की यात्रा भी शामिल है. ■

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस
इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी
मेक्सिको के प्रधानमंत्री मैन्युेल लोपेज ओब्राडोर
जर्मनी के चांसलर ओलफ शोलज
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
BHADOO SAHIB

आवरण कथा

G20

भारत व

दुनिया के देशों के सबसे ताकतवर गुट जी-20 के अध्यक्ष के नाते भारत मुख्य वैश्विक सवालों पर सर्वानुमति बनाने की पहल कर सकता है, और दुनिया में अगुआ के तौर पर उभर सकता है

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन
ब्राजील के निर्वाचित-राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येल
तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैय्यप एर्दोगान
सऊदी अरब के गद्दीनशीन राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोशा
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

BHADOO SAHIB

...ा लम्हा

राज चेंगप्पा

फोटो इमेजिंगः अमरजीत सिंह नागी

कमान सुपुर्दगी
बाली में 12 नवंबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्षीय हथौड़ा सौंपा

एएनआइ

मध्य नवंबर में बाली शिखर सम्मेलन के अंत में जी20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) की अध्यक्षता का जो लकड़ी का हथौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया, वह भले बहुत छोटा दिखाई दे, मगर उसके साथ आने वाली जबरदस्त जिम्मेदारियां इसकी कदकाठी के मुकाबले बहुत बड़ी हैं. 1 दिसंबर को भारत ने औपचारिक रूप से जिस जी20 की जिम्मेदारी संभाली, उसके सदस्य देश दुनिया की 60 फीसद आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, वैश्विक जीडीपी में उनका 85 फीसद और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75 फीसद हिस्सा है. 1999 में शुरुआत से ही जी20 प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर और हाल में भू-राजनैतिक सरोकारों पर भी दुनिया के सबसे ताकतवर अंतरराष्ट्रीय मंच के तौर पर उभरा. संयोग से दिसंबर में भारत एक महीने के लिए सर्वशक्तिमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण करेगा. सितंबर, 2023 तक वह दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय मंच शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता भी करेगा. विश्व मंच पर यह वाकई भारत का लम्हा है.

मगर भारत ऐसे वक्त इन मंचों की कमान संभाल रहा है जब विश्व मामलों में सरगर्मी तेज है और वे, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के शब्दों में, अंग्रेजी के तीन 'सी'—यानी कोविड, कॉन्फ्लिक्ट (टकराव) और क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन)—के कृशकाय कर देने वाले नतीजों से घिरे हैं. कोविड-19 महामारी ने अमीर देशों सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को रसातल में पहुंचा दिया. दुनिया अभी महामारी के भयावह प्रभावों

> "कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है. मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि **जी-20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी.** एकसाथ मिलकर हम जी-20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे"
>
> **नरेंद्र मोदी**
> *प्रधानमंत्री, भारत*

G20 की बुनियाद

एशियाई वित्तीय संकट के दौरान 1999 में गठित जी20 के समूह में विकसित और विकासशील देश शामिल थे. शुरू में यह वित्त मंत्रियों का मंच था, 2008 में इसे शिखर सम्मेलन का रूप दिया गया और देश-प्रमुखों का प्रतिनिधित्व होने लगा

जी-20 का दायरा

85% वैश्विक जीडीपी

4.6 अरब लोग

या

75% विश्व व्यापार

60% आबादी दुनिया की

नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में 43 देशों/सरकारों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सेदारी करेंगे. जी-20 में यह सबसे बड़ा जमावड़ा होगा

विकसित सदस्य देश

अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया

जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, जापान

विकासशील सदस्य देश

भारत, चीन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना

तुर्की, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ब्राजील, रूस

दिल्ली सम्मेलन में विशेष आमंत्रित

बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

अंतरराष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आइएलओ, एफएसबी, ओईसीडी

पिछले पांच जी-20 सम्मेलनः खास नतीजे

2018: ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना
बतौर वैश्विक सुरक्षा नेट आइएमएफ को नए संसाधनों की मंजूरी के लिए समझौते पर दस्तखत

2019: ओसाका, जापान
जी-20 के नेताओं ने डब्ल्यूटीओ की कार्यप्रणाली में सुधार को समर्थन दोबारा पुष्टि की

2020: रियाद, सऊदी अरब
दुनिया के गरीब देशों की मदद के लिए सरकारी कर्ज के भुगतान को रोकने की पहल शुरू हुई

2021: रोम, इटली
बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वैश्विक न्यूनतम कराधान के समझौते पर दस्तखत

2022: बाली, इंडोनेशिया
नेताओं की घोषणा में यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का आह्वान, जो मोदी के बयान जैसा कि "आज का युग युद्ध के लिए नहीं."

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

समूचे देश में आयोजन

उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में कोहिमा तक में आयोजन स्थलों को नया रूपरंग दिया जा रहा है, पर्याप्त होटल कमरों और यातायात की व्यवस्था की गई है

भारत के जिम्मे काम

देश के पास खुद को वैश्विक नेता के रूप में पेश करने का मौका होगा, जिससे विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनाने में मदद मिल सकती है

वैश्विक

विभाजित दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाना

दीर्घकालिक छाप छोड़ना

विकासशील देशों के सरोकारों को आगे बढ़ाना

घरेलू

घरेलू माहौल में भारत की दुनिया में बढ़ती हैसियत की पुष्टि करना

क्षेत्रीय

दक्षिण एशिया के अगुआ के नाते क्षेत्रीय हितों को आगे बढ़ाना

40 वित्त ट्रैक बैठकें

से उबरने के लिए जूझ ही रही थी कि फरवरी में यूक्रेन युद्ध ने भू-राजनैतिक तनावों को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया और खाद्य तथा ऊर्जा का जबरदस्त संकट पैदा कर दिया. नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में 20 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे और 10 करोड़ से ज्यादा लोग भारी गरीबी के शिकंजे में धकेल दिए गए. संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पाने की रफ्तार भी चिंताजनक ढंग से सुस्त हुई है और विकासशील देशों के सामने वजूद बचाए रखने के सवाल खड़े हो गए हैं. पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान सहित 70 से ज्यादा देश कर्ज के तीव्र संकट से जूझ रहे हैं और 2023 में खौफनाक वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका समूची दुनिया के आगे मुंह बाए खड़ी है. कोविड के बाद की इस विखंडित और कुछ-कुछ विशृंखल दुनिया में भारत को यह मौका मिला है कि वह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुआई करे और साथ ही विकासशील देशों के एजेंडे का चैंपियन बनकर उभरे. संक्षेप में, सच्चा वैश्विक नेता बने.

जबानी जमाखर्च की वैश्विक दुकान नहीं

कौशल दिखाने का जी20 से बेहतर मंच नहीं हो सकता. इसकी स्थापना 1999 में इस मकसद से हुई थी कि विकसित और प्रमुख विकासशील देशों के वित्त मंत्री साथ बैठकर एशियाई वित्तीय संकट को सुलझाएं. 2008 में जब वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हुआ, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जी20 को विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन का दर्जा दिया

हर मुद्दे पर जोरदार पहल

जी-20 के नेता

वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर
8 कार्य-धाराएं

1. फ्रेमवर्क डब्ल्यूजी
2. इन्फ्रास्ट्रक्चर डब्ल्यूजी
3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर डब्ल्यूजी
4. टिकाऊ वित्त डब्ल्यूजी
5. वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक साझेदारी
6. साझा वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल
7. अंतरराष्ट्रीय कराधान
8. वित्त क्षेत्र के मुद्दे

शेरपा ट्रैक
शेरपा की अगुआई में
13 कार्य-दल (डब्ल्यूजी)

1. भ्रष्टाचार विरोध
2. कृषि
3. संस्कृति
4. विकास
5. डिजिटल अर्थव्यवस्था
6. आपदा जोखिम घटाना
7. रोजगार
8. पर्यावरण और जलवायु
9. शिक्षा
10. ऊर्जा संप्रेषण
11. स्वास्थ्य
12. व्यापार और निवेश
13. पर्यटन

12 एंगेजमेंट समूह (ईजी)
सिविल सोसाइटी ग्रुपों की अगुआई में

1. कारोबार 20
2. सिविल 20
3. श्रम 20
4. संसद 20
5. विज्ञान 20
6. एसएआइ 20
7. अंतरिक्ष 20
8. स्टार्ट-अप 20
9. विचार 20
10. शहरी 20
11. महिला 20
12. युवा 20

विदेश मंत्रियों की बैठक
बाकी मंत्रियों की बैठकें

जी-20 सम्मेलन के लिए प्रगति मैदान में जारी तैयारी

चंद्रदीप कुमार

60 शेरपा ट्रैक बैठकें

50 ईजी बैठकें

15 मंत्री-स्तरीय बैठकें

25 सेमिनार/ वर्कशॉप

“हम अनोखे भारतीय अनुभव का माहौल तैयार करेंगे, जो आध्यात्मिक बल, उत्साह, शारीरिक फुर्ती और समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगा ”

अमिताभ कांत
भारत के जी-20 शेरपा

और इसकी कार्यसूची का आधार बढ़ाते हुए इसमें भू-आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों को भी शामिल कर लिया. हालांकि सारे फैसले आम राय से लिए जाते हैं और बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी यह समूह इस धारणा से उबर सका कि यह महज जबानी जमाखर्च की एक और वैश्विक दुकान भर है. उसने कई प्रमुख मुद्दों पर एजेंडा तय किया और उसकी सक्रियताओं के सार्थक नतीजे मिले. इनमें अप्रैल 2009 में वैश्विक वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और जुलाई 2009 में बासेल III पैकेज की स्थापना शामिल हैं, जिसमें एक और वित्तीय गिरावट को रोकने की खातिर बैंकों के लिए पूंजी और तरलता की ज्यादा सख्त आवश्यकताएं तय की गईं. बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति

जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कामयाब द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसने तनाव खासा कम किया. इसके अलावा घोषणापत्र में यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की भर्त्सना करने और युद्ध खत्म करने तथा बातचीत और कूटनीति की ओर लौटने को लेकर सर्वसम्मति कायम हुई, जिसे कामयाबी के तौर पर देखा गया.

बाली में वह सर्वसम्मति बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोदी ने यह ठान लिया लगता है कि भारत इस चुनौती पर खरा उतरे और अपनी अध्यक्षता के दौरान अमिट छाप छोड़े. बाली शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में मोदी ने विश्व नेताओं के जमावड़े से कहा, ''कोविड के बाद के दौर के लिए नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है. मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत की जी20 की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख होगी. साथ मिलकर हम जी20 को वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बनाएंगे.'' इंडोनेशिया की अध्यक्षता 'रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर' को लेकर थी, तो भारत की थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है, जो, एक अधिकारी के शब्दों में, दर्शाती है कि किस तरह देशों को एकजुट होने और उन बहुत-से संकटों से मिलकर निबटने की जरूरत है, जो दुनिया के आगे मुंह बाए खड़े हैं.

भारत सरकार अपनी अध्यक्षता को सबसे कामयाब अध्यक्षताओं में से एक बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है. इसी महीने से शुरू होकर दिसंबर, 2023 में ब्राजील को अध्यक्षता सौंपने तक भारत देश भर में फैली 56 जगहों पर जी20 की 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित करेगा. ये जगहें उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक और पश्चिम में कच्छ के रण से पूरब में कोहिमा तक फैली हैं. इन बैठकों के आयोजन के लिए सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का साथ लिया गया है. इसमें आयोजन स्थल की साज-सज्जा, होटलों में पर्याप्त कमरों और आने-जाने के साधनों का इंतजाम शामिल है. जी20 की बैठकें दो मुख्य ट्रैक (पटरियों) पर आयोजित की जाती हैं. एक, फाइनेंस ट्रैक, जिसमें आठ कार्य धाराएं हैं जिनकी 40 बैठकें होंगी. दूसरे ट्रैक की अगुआई शेरपा करते हैं, जो 13 कार्य समूहों से मिलकर बना है और जिनकी 60 बैठकें होंगी. 15 मंत्री स्तर की उच्चस्तरीय बैठकें होंगी, जिनमें दो विदेश और वित्त मंत्री स्तर की बैठकें शामिल हैं. इसके अलावा, कारोबार, विज्ञान, लैंगिक मुद्दों और स्टार्ट-अप—जो भारत ने जोड़ा है—के क्षेत्र में गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडलों के लिए 12 एंगेजमेंट समूह हैं. उनकी 50 बैठकें होंगी और इसके अलावा 25 सेमिनार व कार्यशालाएं भी होंगी (देखें, *हर मुद्दे पर जोरदार पहल*).

इसे 'अतुलनीय जी20' बनाना

भारत का इरादा इन आयोजनों का फायदा उठाकर घरेलू मैदान में अपनी वैश्विक अहमियत और वजन साबित करने का है. सितंबर, 2023 में मुख्य नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में सम्मेलन केंद्र को सजाया-संवारा जा रहा है. पारंपरिक रूप से शिखर सम्मेलन नवंबर में आयोजित किया जाता है, क्योंकि अगला देश 1 दिसंबर को अध्यक्षता संभालता है. मगर उस महीने राजधानी में प्रदूषण बहुत अधिक होने के कारण

क्या है एजेंडे में

भारत को अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान इन 10 मसलों पर बातचीत को आगे बढ़ाना होगा

इंडिया टुडे

1 यूक्रेन युद्ध

यूक्रेन में रूस के हमले से ऊर्जा और खाद्य संकट पैदा हो गया है. बाली में 2022 के जी-20 सम्मेलन में वह संदेश देने में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की इस युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव के हवाले से निंदा की गई. अब जी-20 के अध्यक्ष पद से भारत को शांति संबंधी सुलह-वार्ता के लिए बड़ी कोशिश करनी होगी. इस मामले में औसत कामयाबी भी बड़ी उपलब्धि होगी.

2 कर्ज दुश्चक्र

आइएमएफ और विश्व बैंक के मुताबिक, कम और मध्यम आयवर्ग के करीब 80 देशों के सामने गहरा कर्ज संकट खड़ा है. इसमें भारत के पड़ोस में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश हैं. वैश्विक मंदी के हालात इसे और बदतर कर सकते हैं. भारत जी-20 के जरिए ऐसे देशों को फंड आसानी से मुहैया कराने के लिए आइएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से उधारी/कर्ज के कायदों में फेरबदल की पेशबंदी कर रहा है.

"यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर हमें **फुटबॉल के रेफरी जैसे दमखम** की जरूरत है, ताकि एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रह सकें"

बाल वेंकटेश वर्मा
रूस में भारत पूर्व राजदूत

3 जलवायु संकट

शरम अल शेख में सीओपी27 सम्मेलन से एक बड़ी खबर यह है कि जलवायु संकट का सबसे बुरा असर झेल रहे देशों को मुआवजे के लिए 'घाटा और नुक्सान' फंड की स्थापना पर समझौता हुआ है. इसके तौर-तरीकों को तैयार करने के लिए इस मसले पर जी-20 कार्यदल बात आगे बढ़ा सकता है. दूसरी चुनौती निजी कंपनियों को जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर संक्रमण वाले परियोजनाओं में निवेश के लिए आकर्षित करना है.

4 वैश्विक मंदी

विश्व बैंक ने 2023 में वैश्विक मंदी के खतरे से आगाह किया है. महंगाई से निबटने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, मगर इसके साथ वित्तीय बाजारों में दबाव बनता है तो वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत तक धीमी हो

गेट्टी इमेजेज

सकती है. आगामी सम्मेलन इस पर एक वैश्विक नजरिया हासिल कर सकता है.

5 खाद्य सुरक्षा

वैश्विक खाद्य कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, इसका अधिक संबंध रूस और यूक्रेन से हैं क्योंकि दोनों बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं. भारत मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, और जी-20 में वह देशों से इस कम कार्बन उत्सर्जन वाली फसलों की ओर बढ़ने के विचार को जोरशोर से आगे बढ़ाएगा.

गेट्टी इमेजेज

6 ऊर्जा सुरक्षा

यूक्रेन युद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है. अपनी अध्यक्षता के कार्यकाल में भारत इसे आसान बनाने की कोशिश कर सकता है.

7 डिजिटल फासले को पाटना

दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं. भारत जेएएम (जन धन-आधार-मोबाइल)के जरिए अपने समावेशी डिजिटल क्रांति की विशेषज्ञता का लाभ दूसरे देशों को दे सकता है.

8 वैश्विक मूल्य शृंखला

महामारी ने चीन पर निर्भर वैश्विक मूल्य शृंखला की कमियों को उजागर कर दिया है. हालात जस के तस बने हुए हैं, ऐसे में चाइना प्लस वन सप्लाई लाईन का विचार आगे बढ़ाया गया है. भारत खुद को वैकल्पिक देश के रूप में पेश करने की पेशकश को जी-20 के जरिए आगे बढ़ा सकता है.

9 मैदान में उतरकर

भारत उम्मीद करेगा कि कॉर्पोरेट कराधान पर शुल्क जड़ने और मुनाफे के मुनासिब बंटवारे पर आगे बढ़ा जाए, और उन देशों को कर लगाने का अधिकार मिले, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारोबार करती हैं.

10 विकासशील देशों की आवाज

बतौर जी-20 अध्यक्ष, भारत के पास दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों की आवाज बनने का भी भरपूर मौका है और वह इस तरफ की दुनिया के देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करे.

चंद्रदीप कुमार

सरकार को इसे कुछ महीने पहले आयोजित करने में समझदारी नजर आई. नए केंद्र में 7,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के बैठने की जगह होगी और जी20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए विशेष तल होगा. भारत अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी पर जोर दे रहा है. उसे इसमें 43 शासन प्रमुखों के भाग लेने की उम्मीद है, जिनमें विशेष आंमत्रित के तौर पर शामिल नौ देशों के नेता भी होंगे. उनमें बांग्लादेश, यूएई और नाइजीरिया हैं. जी20 के लिए भारत के शेरपा और प्रधानमंत्री की तरफ से सभी बैठकों की देख-रेख करने वाले अमिताभ कांत ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''अच्छी अध्यक्षताएं तीन मूल स्तंभों पर काम करके दिखाती हैं. एक राजनैतिक संचालन जो हम सर्वसम्मति और सम्मेलन से उभरने वाला व्यापक नैरेटिव बनाने के लिए प्रदर्शित करते हैं. दूसरा कंटेट या कथ्य, ताकि एजेंडे में निरंतरता और बदलाव दोनों हो सके, जिसमें नए और अभिनव विचार जोड़ना भी शामिल है. तीसरा प्रशासनिक लॉजिस्टिक जो पक्का करे कि वैश्विक मानव गतिवधियों के हरेक क्षेत्र से शीर्ष नेताओं का यह जमावड़ा ध्यान रखने वाला और दक्ष दोनों है. अपने प्रधानमंत्री की अगुआई में हमें इन तीनों उद्देश्यों पर खरा उतरने का पूरा यकीन है.''

नीति आयोग के पूर्व सीईओ कांत भारत को प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर पेश करने की अपनी काबिलियत के लिए भी जाने जाते हैं. उन्हें 'इनक्रेडिबल इंडिया' या अतुल्य भारत और केरल के लिए 'गॉड्स ओन कंट्री' सरीखे अभियानों का श्रेय हासिल है. जैसा कि एक अफसर

जी-20 में अतुल्य भारत

भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के प्रदर्शन की कोशिश में जी-20 के आयोजनों को सांस्कृतिक उत्सवों के साथ जोड़ा गया है

भारत के उत्सव

गेट्टी इमेजेज

हॉर्नबिल संगीत उत्सव

कोहिमा, नगालैंड
1-10 दिसंबर, 2022

संगई उत्सव

इंफाल, मणिपुर
1-10 दिसंबर, 2022

खजुराहो नृत्य महोत्सव

खजुराहो, मध्य प्रदेश
20-26 फरवरी 2023

TATA MUMBAI MARATHON

टाटा मुंबई मैराथन

मुंबई, महाराष्ट्र
15 जनवरी, 2023

रोशनी में नहाए स्मारक

रामअप्पा मंदिर, तेलंगाना
(यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)

क्विज, लेखन, नारे लिखने की स्पर्धा

- एनसीईआरटी और एनबीटी के साथ
- साल भर पूरे देश में

अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव

कोणार्क, ओडिशा, 1 दिसंबर, 2023

अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव

अहमदाबाद, गुजरात
14 जनवरी, 2023

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला

सूरजकुंड, हरियाणा
1-19 फरवरी, 2023

समुद्र तटों की सफाई

प्रवासी भारतीय दिवस

इंदौर, मध्य प्रदेश
9 जनवरी, 2023

विश्वविद्यालय पहुंच

- जी-20 सार्वजनिक आयोजन में 75 विश्वविद्यालय
- साल भर पूरे देश में

ने मुस्कराते हुए कहा, अब वे भारत की अध्यक्षता को ''इनक्रेडिबल जी20'' या ''अतुल्य जी20'' के तौर पर पेश करना चाहते हैं. कांत और उनकी टीम ऐसी चीज का ताना-बाना बुनने में लगी है, जिसे वे आने वाले प्रतिनिधियों के लिए ''आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने वाला, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने वाला, मानसिक रूप से तरोताजा करने वाला और शारीरिक रूप से बलवान बनाने वाला अनूठा भारतीय अनुभव'' कहते हैं. वे भारत के बड़े उत्सवों में भाग लेंगे, चाहे वह अहमदाबाद का पतंग उत्सव हो, या कोणार्क का रेत कला उत्सव, सूरजकुंड का शिल्प मेला, कोहिमा का हॉर्नबिल संगीत उत्सव और खजुराहो का नृत्य उत्सव. इन सभी को भारत की सांस्कृतिक शक्ति को पेश करने के लिए जी20 के आयोजन के साथ पिरोया गया है. वैश्विक जलवायु संकट के समाधान के लिए भारत के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के हिस्से के रूप में समुद्रतटों की सफाई मुहिम चलाई जाएंगी. 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में प्रस्तुत भारत की महिलाओं की अगुआई में हो रहे विकास की कोशिशों को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा, तो डिजिटल हैकेथन के माध्यम से डिजिटल समावेशन और कायापलट में देश की ऊंची छलांगों को भी. यही स्वर प्रतिनिधियों के किट तक जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों की कलाओं और शिल्पों का शुमार होगा, चाहे वह चाय के प्यालों पर बिहार की मधुबनी कला हो, बोतलों पर कश्मीर का कनी काम या कांजीवरम या प्रतिनिधियों के झोलों पर गोंड डिजाइन.

अब मुश्किल हिस्सा

उम्मीद यही है कि यह सब जी20 की आम तौर पर धीर-गंभीर बैठकों को वैश्विक तमाशे में बदल देगा, जो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और जानदार होगा. पर भारत की अध्यक्षता की कामयाबी की कुंजी मुट्ठी भर पेचीदा मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ बातचीत करते हुए ऐसी रचनात्मक सर्वसम्मति बना पाने में है जो सार्थक नतीजे दे सके. इनमें सबसे अव्वल यूक्रेन में चल रही लड़ाई है, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में ऐसा खलल डाला कि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के रुझान के अलावा खाद्य और ऊर्जा का संकट भी पैदा हो गया है. इस मुद्दे पर भारत नाजुक संतुलन साध रहा है क्योंकि रूस उसका करीबी दोस्त है और पूरे संकट के दौरान उसने भारत को यथोचित कीमत पर ईंधन और उर्वरक दोनों की आपूर्ति की. हालांकि अमेरिका और यूरोप ने भारत की मजबूरी को माना, पर कई मौकों पर वे भारत के महत्वाकांक्षी रुख को लेकर हताशा में दांत भी पीसते रहे. मगर सितंबर में समरकंद में हुए एससीओ के शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में मोदी के बहुत नफासत के साथ दिए गए बयान ने उनकी धारणा बदली. मोदी ने पुतिन को दोनों देशों के बीच ''अटूट दोस्ती'' के बारे आश्वस्त करते हुए कहा कि ''आज का युग युद्ध का नहीं है.'' भारत के रुख में इस बारीक बदलाव की पश्चिम ने प्रशंसा की. एक वरिष्ठ अफसर कहते हैं, ''हमने साफ कर दिया कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं और कूटनीति तथा संवाद के जरिए शांति की दिशा में कोई भी योगदान देकर हमें खुशी होगी.''

जी20 के बाली घोषणापत्र में भारत ने चतुराई से गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, जिसमें यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की भर्त्सना करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को उद्घृत किया गया, बजाए इसके कि जी20 सीधे ऐसा करता. नतीजा यह हुआ कि रूस तक ने घोषणापत्र पर दस्तखत किए और भारत की ऐसे देश के रूप में धाक जम गई जो सर्वसम्मति बना सकता है. रूस में भारत के पूर्व राजदूत बाल वेंकटेश वर्मा कहते हैं, ''भारतीय

कूटनीति ने उच्च कोटि की व्यवहारिकता का प्रदर्शन किया. बाली में भारत ने इस विषय पर अहमियत रखने वाली हरेक हस्ती के लिए अपने दरवाजे खुले रखे. फिर रूस के साथ-साथ हमने पश्चिम के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ भी अलग-बगल के दरवाजे खुले रखे. यहां तक कि इंडोनेशिया ने भी, जो अध्यक्षता कर रहा था, इसकी तारीफ की. अगर बाली में जी20 संयुक्त बयान जारी किए बिना खत्म हो जाता, तो हमारी अध्यक्षता के दौरान काम दोगुना बढ़ गया होता.'' अब जी20 के अध्यक्ष के नाते भारत ऐसी स्थिति से हटकर, जिसमें उसे कोई न कोई रुख लेना पड़ता, ऐसी स्थिति में आ गया है जहां वह शांति समझौते पर पहुंचने का जतन करने की ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने की तरफ बढ़ रहा है. रूस हालांकि यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर जान-बूझकर हमले करके उसे घुटनों पर लाने को आमादा दिखाई देता है. ऐसे में स्थिति की गंभीरत को कम करने के तरीके खोज पाना मुश्किल काम होगा. मगर भारत जी20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान थोड़ी-सी भी शांति और संवाद की स्थिति बना सका, तो यह बड़ी उपलब्धि होगी. वर्मा सलाह देते हैं, ''हमें फुटबॉल के रेफरी सरीखे दमखम और रफ्तार की जरूरत है ताकि हम बिना थके मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रह सकें. कोई नहीं जानता कि युद्ध का ऊंट किस करवट बैठेगा, पर भारत के लिए खेल में होना जरूरी है.''

कर्ज बम को बेमानी करना

भारत को जिस एक और बड़े मुद्दे की अगुआई करनी होगी, वह है वैश्विक कर्ज के बम को फटने से रोकना. विश्व बैंक की 2022 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, 70 से ज्यादा निम्न आय वाले देश और कोई दर्जन भर मध्यम आय वाले देश गंभीर कर्ज के संकट से घिरे हैं. भारत को ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है. उसके पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान जीते-जागते सबूत हैं कि किस तरह यह वित्तीय गिरावट और राजनैतिक अस्थिरता की तरफ ले जा सकता है. जब दुनिया भर में मंदी का खतरा मंडरा रहा है, विश्व बैंक को हालात के और बदतर होने की आशंका है. भारत जी20 पर जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और पलायन सरीखे विदेशी मुद्दों के सामूहिक प्रभाव से निपटने के लिए वित्तीय टूलकिट विकसित करने पर जोर डाल रहा है. इसका एक प्रमुख हिस्सा यह होगा कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से उधार लेने और देने के नियमों को नए सिरे से तय करने का जतन किया जाए, ताकि देशों को उनकी वित्तीय मुश्किलों से उबरने के लिए पर्याप्त धन सुलभ हो.

दूसरा हिस्सा विकासशील देशों के लिए वैश्विक सार्वजनिक हित की परियोजनाओं में धन लगाने के लिए निजी निवेश लाना है. इनमें उनका जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाना भी शामिल है. निजी निवेशक तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक वे अच्छे रिटर्न मिलते नहीं देखते. इसलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये संस्थाएं निजी खिलाड़ियों को उसी तरह कर्ज की गारंटी देने सरीखे वित्तपोषण का तंत्र स्थापित करें जैसे विश्व बैंक की तरफ से स्थापित मल्टीलेटरल इनवेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (एमआइजीए) करती है. हाल ही में मिस्र के शर्म-अल-शेख में हुए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन सीओपी 27 में हानि और क्षति कोष बनाने का जो समझौता हुआ है, उसे धरती के तापमान में वृद्धि से हो रहे नुक्सानों के लिए विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों को भरपाई की दिशा में बड़े कदम की तरह देखा जा रहा है. ऐसे नुक्सान हाल में पाकिस्तान में आई बाढ़ और अफ्रीका के कई हिस्सों में बड़े सूखों में देखे गए. सहभागी देश कोष बनाने के लिए सिद्धांततः राजी हो गए हैं, पर नियम और तौर-तरीके जी20 के जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास कार्य समूह में विकसित किए जा सकते हैं, जिसकी बैठक भारत में होगी.

टैक्स हैवन का खात्मा

जिन्हें ग्लोबल ऐंटी-बेस इरोजन मॉडल रूल्स के तहत टू-पिलर (दो-स्तंभ) अंतरराष्ट्रीय कर समझौते कहा जाता है और जो आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ने अक्तूबर 2021 में तय किए थे, उन्हें लागू करना एक और अहम मुद्दा है जिस पर भारत को आगे बढ़ने की उम्मीद है. पिलर वन या पहले स्तंभ का मकसद भारत सहित कई देशों के लिए—जहां अमेजन और वालमार्ट सरीखे विशालकाय बहुराष्ट्रीय उद्यम हैं, फिर चाहे उनकी उस अधिकार क्षेत्र में मौजूदगी हो या न हो जहां वे कारोबार कर रहे हैं—मुनाफों और कर लगाने के अधिकारों का ज्यादा न्यायसंगत वितरण तय करना है. एक जटिल फॉर्मूले के तहत 20 अरब यूरो (20.7 अरब डॉलर) से ज्यादा की वैश्विक बिक्री वाले बहुराष्ट्रीय उद्यमों को 10 फीसद की सीमारेखा से ऊपर अपने कुल मुनाफों का 25 फीसद फिर उन्हीं बाजार क्षेत्रों में आवंटित करना होगा जहां वे काम करते हैं. इससे साल में 125 अरब डॉलर से ज्यादा धनराशि आवंटित की जा सकेगी, जिसमें विकासशील देशों को उन्नत देशों के मुकाबले ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है.

पिलर टू का वास्ता आयरलैंड, सिंगापुर, केमैन आइलैंड और ऐसे ही दर्जन भर दूसरे देशों से है जो ज्यादातर देशों के मुकाबले बहुत कम कर दरों की पेशकश करते हैं. ओईसीडी देश सहमत हो गए हैं कि 75 करोड़ यूरो (77.7 करोड़ डॉलर) से ज्यादा राजस्व वाले बहुराष्ट्रीय उद्यमों को 15 फीसद की कर दर से वैश्विक न्यूनतम कर चुकाना होगा. वैश्विक न्यूनतम कर समझौता करों के मामले में प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सीमाएं तय करता है. इससे भारत सहित कई देशों को साल में करीब 150 अरब डॉलर का नया राजस्व मिलेगा. जी20 इन फैसलों पर मोहर लगा चुका है. अध्यक्षता के दौरान भारत को उनसे जुड़े बाकी मुद्दे सुलझाने के लिए काम करना होगा. इसमें उन पर अमल

कला के स्वर

कॉफी मग पर मधुबनी पेंटिंग से लेकर पानी की बोतलों पर कनी चित्रांकन तक पारंपरिक भारतीय हस्तकला के नमूने जी-20 में यादगार बनेंगे

पाटन पटोला
गुजरात

कनी
जम्मू-कश्मीर

चिकनकारी
लखनऊ

मधुबनी
बिहार

"जी-20 का काम सर्वानुमति से चलता है, इसलिए हमें अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए **सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर चलना होगा**"

हर्ष श्रृंगला
जी-20 के मुख्य संयोजक

के लिए बहुपक्षीय दस्तावेज पर दस्तखत करना भी शामिल है. एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी कहते हैं, ''शुरुआत में भारत को करीब 4,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन यह अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ेगा.'' हालांकि अमेरिका और दूसरे देशों के लिए अपनी-अपनी विधायिका से उन्हें मंजूरी दिलवाने में शायद मुश्किल हो, जिससे देरी हो सकती है.

जहां तक व्यापार की बात है, महामारी ने मौजूदा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं और खासकर चीन पर निर्भर मूल्य शृंखलाओं की कमजोरियों को उघाड़कर रख दिया. चीन इन दिनों एक और संकट से घिरा है, जिसमें शंघाई सहित कई बड़े शहरों में प्रचंड लॉकडाउन का स्वागत ब्लैंक पेपर या खाली कागज विरोध प्रदर्शनों से किया जा रहा है. बड़े मैन्युफैक्चरर और निवेशक इतनी आसानी से चीन से नाता नहीं तोड़ सकते, इसलिए इसे चाइना प्लस मूल्य शृंखला के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें वैश्विक लचीलापन बनाने के लिए वैकल्पिक देशों की पहचान की जा सकती है. इन विकल्पों में से एक बनने के लिए भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है और वह अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए जी20 का इस्तेमाल करेगा. हालांकि उसे खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सरीखे मुद्दों पर फूंक-फूंककर कदम रखना होगा. रूस हाल में उर्वरकों के अलावा तेल का उसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है. अमेरिका और यूरोप रूसी तेल की बिक्री पर ऊपरी मूल्य सीमा तय करने पर जोर दे रहे हैं.

जहां तक खाद्य सुरक्षा की बात है, बड़े गेहूं उत्पादक देशों—रूस और यूक्रेन—के युद्ध में उलझे होने के कारण गेहूं की जहाजों पर लदाई में भारी खलल पड़ा है, इसलिए भारत दुनिया भर में मोटे अनाजों के पैदावार में नई जान फूंकने पर जोर दे रहा है. गेहूं की फसल के लिए जहां बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, मोटे अनाज पानी की कमी वाले इलाकों में उग आते हैं और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों का मुख्य आहार हुआ करते थे, जब तक कि गेहूं की व्यावसायिक पैदावार ने उन्हें जड़ से उखाड़ नहीं फेंका. अलबत्ता करीब 130 देश मोटे अनाज उगाते हैं, जिसमें भारत सबसे बड़ा है. 2019 में दुनिया भर में कुल 8.9 करोड़ टन मोटे अनाज उगाए गए, जिनमें भारत का योगदान 20 फीसद था. इसके मुकाबले गेहूं की वैश्विक उपज इस साल 80 करोड़ टन थी. भारत ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने के अभियान की अगुआई की, जिसे 72 देशों के समर्थन से पारित किया गया. जी20 में वह मोटे अनाजों की तरफ जाने के लिए देशों पर पूरा जोर डालेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि गेहूं से इसके कार्बन उत्सर्जन और पानी की खपत बहुत कम है.

विकास के तौर पर डेटा

जिस एक और क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है, वह है डिजिटल खाई को पाटना. तकरीबन चार अरब लोगों या दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधा नहीं है. करोड़ों लोग बैंक से जुड़े नहीं हैं. इसके अलावा दुनिया के कुल 195 में से 130 से ज्यादा देशों के पास अब भी डिजिटल भुगतान प्रणाली नहीं है. भारत खुद अपना उदाहरण सामने रखकर समावेशी डिजिटल क्रांति लाने की अगुआई कर सकता है. अपनी जेएएम—जन धन बैंक खाते, आधार कार्ड और मोबाइल नेटवर्क—के माध्यम से सरकार जनकल्याण योजनाओं के तहत नकद सहायता के लिए शायद दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अंजाम दे पा रही है. मोदी सरकार के काल में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नए बैंक खाते खोले, जिससे भारत की बैंकों से कटी आबादी आधी कम हो गई. सार्वजनिक क्षेत्र के यूपीआइ (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिए पिछले साल 46.8 अरब लेन-देन किए गए, जो दुनिया के रियल-टाइम लेन-देन का 40 फीसद हैं. कांत कहते हैं, ''हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और इसे विकासशील देशों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है. अपनी अध्यक्षता के दौरान हम इन समाधानों की वकालत करेंगे.''

इन तमाम एजेंडों पर जोर देने में भारत किस हद तक कामयाब होगा, यह देखना बाकी है. मसलन, डिजिटल भुगतान के मामले में मास्टरकार्ड और वीजा सरीखी कार्ड भुगतान से जुड़ी विशालकाय कॉर्पोरेट कंपनियां वैश्विक कारोबार में बड़ा हिस्सा चाहेंगी और इस क्षेत्र में काबिज होने की भारत की कोशिशों का विरोध करेंगी. भारत इस सारी खींचतान और जी20 के मंच की सीमाओं से अच्छी तरह वाकिफ है. जी20 के मुख्य संयोजक और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला कहते हैं, ''जी20 सर्वसम्मति से चलता है, इसलिए हमें अपनी पहलों को आगे ले जाने के लिए अपने सभी सहभागी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा.'' भारत यह पक्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि उसकी साल भर लंबी अध्यक्षता से विश्व की उभरती शक्ति के रूप में उसका कद और रुतबा बढ़े और उसे विकासशील देशों की आवाज बनने में मदद मिले. ■

खास रपट

कांग्रेस

सोशल मीडिया पर आक्रामक रुख

कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया सरअंजाम को जोड़कर भारत जोड़ो यात्रा का सुघड़ कंटेंट परोसने की व्यवस्था बनाई और सभी प्लेटफॉर्म पर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज की

कौशिक डेका

नेता का स्वागत
भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र के श्रीगांव पहुंचने पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए लाइन में खड़े कांग्रेस नेता

रा

हुल गांधी की अगुआई में भारत जोड़ो यात्रा (बीजेवाइ) जब तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही थी, 7-8 नवंबर की उस दरम्यानी रात को कांग्रेस सोशल मीडिया शाखा की मुखिया सुप्रिया श्रीनेत आधी रात के काफी बाद तक जगी हुई थीं. तब वे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश में थीं. पत्रकार रह चुकीं श्रीनेत के लिए देर रात तक काम में जुटे रहना तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन दिल्ली के 15, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड (जीआरबी) पर मौजूद उनकी टीम के लिए वह रात काफी गहमागहमी भरी थी. उन्हें तेलंगाना-महाराष्ट्र सीमा से कुछ बेहद दिलचस्प दृश्यों की आमद के लिए सतर्क कर दिया गया था. आखिर, उस रात हाथों में मशाल लिए अंधेरे को चीरते हुए राहुल गांधी की अगुआई में भारत जोड़ो यात्रियों के नाटकीय वीडियो उनके वर्क स्टेशन पर नमूदार हुए.

फटाफट थोड़े-बहुत संपादन के बाद, श्रीनेत और राहुल गांधी के सोशल मीडिया एकाउंट्स संभालने वाले श्रीवत्स वाइबी के बीच कुछ व्हाट्सऐप मैसेज का आदान-प्रदान हुआ, और फिर पार्टी के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश की हां होते ही, विभिन्न डिजिटल

एएनआइ

पार्टी के सोशल मीडिया रणबांकुरे

जयराम रमेश,
68 वर्ष
राज्यसभा सांसद, संचार प्रभारी और एआइसीसी महासचिव

पिछले संचार प्रमुखों के विपरीत रमेश सोशल मीडिया शाखा भी देखते हैं. वे इसमें कंटेंट की व्यापक रूपरेखा तय करते हैं. उनका सिद्धांत हैः एसीटी या ऐक्ट (एग्रेशन (आक्रामकता), कोहेजन या तालमेल, टाइमली या समय पर). वे आठ लोगों की टीम के प्रमुख हैं

सुप्रिया श्रीनेत,
45 वर्ष
एआइसीसी चेयरपर्सन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म

खबरनवीस से सियासतदां बनी श्रीनेत करीब 60 लोगों की टीम की अगुआई करती हैं, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पार्टी का सोशल मीडिया अभियान चलाने के कामों में लगे हैं. टीम की औसत उम्र 27 साल है. ये दिल्ली में 15, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड से काम करते हैं

श्रीवत्स वाइ.बी.,
39 वर्ष
राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख

गांधी परिवार के वंशज का सोशल मीडिया अभियान 10 लोगों की टीम संभालती है, जिसके प्रमुख एमएनसी के पूर्व एग्जीक्यूटिव श्रीवत्स वाइ.बी. हैं. पहले वे कर्नाटक कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख थे. श्रीवत्स की टीम रमेश और श्रीनेत की टीमों से तालमेल बनाकर काम करती है

तीन बंदर

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की मदद के लिए मुबंई की इस डिजिटल आउटरीच कंपनी की सेवाएं ली गईं. इसने लोगो डिजाइन किया, यात्रा का गीत तैयार किया और उसकी वेबसाइट संभालती है. तीन बंदर प्रशांत चारी और सैवियो जोसफ चलाते हैं

प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर राहुल गांधी के रात्रि मार्च की छवियों से जगमगा उठे. जब गुरुद्वारा रकाबगंज वॉर रूम के सदस्य घर के लिए निकले, तो रात के 3.30 बज चुके थे. अगला बैच सुबह 6 बजे काम संभालने के लिए आ पहुंचा.

यह, खासकर 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद, कांग्रेस के सोशल मीडिया योद्धाओं के जीवन में बीता बस एक और दिन था. आजाद भारत के इतिहास में यह कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3,500 किमी की करीब छह महीने चलने वाली पदयात्रा अभूतपूर्व है. इसका आकार और इसमें लोगों की दिलचस्पी बेमिसाल है. हर दिन इसमें ऐसी छवियां उभरती हैं, जो चुनाव रैलियों जैसे राजनैतिक मजमों में नहीं देखी गई हैं. समाज के हर तबके और आयुवर्ग के पुरुष-महिलाएं, लड़के-लड़कियां कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी का हाथ पकड़कर, उनसे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उनके गले लगते हैं और कई बार तो उनके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ते हैं.

फिर पुराने दिग्गज नेताओं के साथ राहुल का दौड़ना, डांस ग्रुप के साथ थिरकना, दांतों से गन्ना छीलकर चूसना या भरी बारिश में भीड़ को संबोधित करने जैसे नजारे खूब खिल रहे हैं. फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों, युद्ध नायकों और सामाजिक कार्यकर्ता अपने गैर-दलीय रुख के साथ स्वेच्छा से यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि बकौल उनके, वे एकता और प्रेम का संदेश देने में यकीन करते हैं. भारत जोड़ो यात्रा के आयोजन से जुड़े एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहते हैं, ''सेलेब्रिटी इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्हें देश में नफरत और सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ बोलने की जरूरत महसूस हुई. राहुल गांधी असरदार सामाजिक आवाजों को अपने साथ पैदल चलने का न्योता देकर एक बड़े जनाधार तक पहुंचेंगे.''

यात्रा जिस राज्य से गुजरती है, वहां भारी दिलचस्पी जगा रही है और अपने भारी जमावड़े तथा अनोखेपन की वजह से सुर्खियों में छाई हुई है. लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की 'खासियत और उद्देश्य' को देश भर में लाखों मोबाइल हैंडसेट, डेस्कटॉप और लैपटॉप तक पहुंचाने का जिम्मा सोशल मीडिया टीम पर है. और इस जिम्मेदारी को तीन केंद्रीय टीमें, एक बाहरी एजेंसी की मदद से, 7 सितंबर से लगातार अंजाम दे रही हैं. इन टीमों का नेतृत्व रमेश कर रहे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया विंग के लिए नया नारा बनाया है-ऐक्ट या एसीटी (आक्रामक, सामंजस्यपूर्ण और समयबद्ध). पहले यह शाखा कांग्रेस के संचार विभाग से अलग थी, पर अब यह रमेश की देखरेख में है, जिन्होंने जून में संचार प्रभारी का पदभार संभाला था. रमेश कहते हैं, ''इससे सोशल मीडिया शाखा में बेहतर तालमेल और समयबद्धता आ गई है. हमारी शैली जब से आक्रामक हुई है, हमें शानदार नतीजे मिल रहे हैं.'' एक आठ सदस्यीय टीम उन्हें सीधे रिपोर्ट करती है. इसके अलावा, श्रीनेत के नेतृत्व में काम कर रही 60 सदस्यीय टीम भी उन्हें रिपोर्ट करती है.

नई आक्रामक शैली का नतीजा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस अपने विरोधियों से पोस्ट दर पोस्ट, ट्रोल दर ट्रोल, दो-दो हाथ करती दिखाई दे रही है. कई बार तो विरोधियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है. जब पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कुछ भाजपा नेताओं ने कथित तौर पर राहुल का एक नकली वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे कथित तौर पर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले दो मुस्लिम हमलावरों को माफ करने की बात करते दिखते हैं तो कांग्रेस ने उन पर खुलकर हमला बोला और उन्हें शर्मिंदा किया. आखिरकार वे वीडियो डिलीट करने पर मजबूर हो गए. पेशे से दर्जी हिंदू कन्हैया लाल ने भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, जिन्हें पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था.

सोशल मीडिया पर जवाबी हमला पर्याप्त नहीं लगा, तो पार्टी ने फौरन आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया. भाजपा ने यात्रा में बच्चों के साथ राहुल की तस्वीरें पोस्ट करके बच्चों के राजनैतिक उपयोग का

ट्वीट का उस्ताद कौन?

राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार गुना अधिक फॉलोअर हैं. फिर भी कांग्रेस नेता को अपने ट्वीट पर पीएम के ट्वीट के मुकाबले ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है

नरेंद्र मोदी
8.45 करोड़

▶ 1 नवंबर, 2022 - 21 नवंबर, 2022
214 591 4,419 19,051

▶ 1, जनवरी 2019 - 31 जनवरी, 2021
9,477 33,801*

राहुल गांधी
2.21 करोड़

▶ 1 नवंबर, 2022 - 21 नवंबर, 2022
55 1,149 8,364 26,788

▶ 1 जनवरी, 2019 - 31 जनवरी, 2021
1,835 57,618*

फॉलोअर्स पोस्ट किए ट्वीट्स की संख्या
औसत कमेंट औसत रिट्वीट्स
औसत लाइक्स एंगेजमेंट्स*

नोट : केवल हिंदी और अंग्रेजी के ट्वीट्स पर विचार किया गया है. दोनों नेताओं के रीट्वीट्स को शामिल नहीं किया गया है.
*संख्या रीट्वीट्स, लाइक्स और कोट्स की है. इसमें उनके पोस्ट किए ट्वीट्स ही शामिल हैं, रीट्वीट्स (या दूसरों की तरफ से आए ट्वीट) नहीं. स्रोतः सोशल मीडिया ऐंड पॉलिटिकल लीडर्स: एन एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस बाइ शमिका रवि ऐंड मुदित कपूर

राहुल गांधी बनाम अन्य

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चार भाजपा नेताओं और अरविंद केजरीवाल के राहुल गांधी से ज्यादा फॉलोअर हैं. यूट्यूब पर मोदी के बाद राहुल का नंबर है

नरेंद्र मोदी
84.5 47
71.1 13.3

अमित शाह
31.3 15
4.8 0.07

अरविंद केजरीवाल
26.7 9.2
1.6 0.4

राजनाथ सिंह
23.1 7
1.2 0.04

योगी आदित्यनाथ
22.7 7.3
3.7 --

राहुल गांधी
22.1 5.9
2.2 0.9

नोटः इन नेताओं की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि भारत की सभी राजनैतिक पार्टियों में इनके फॉलोअर्स सर्वाधिक हैं. संख्या मिलियन में

सोशल मीडिया पर कांग्रेस की दुनिया

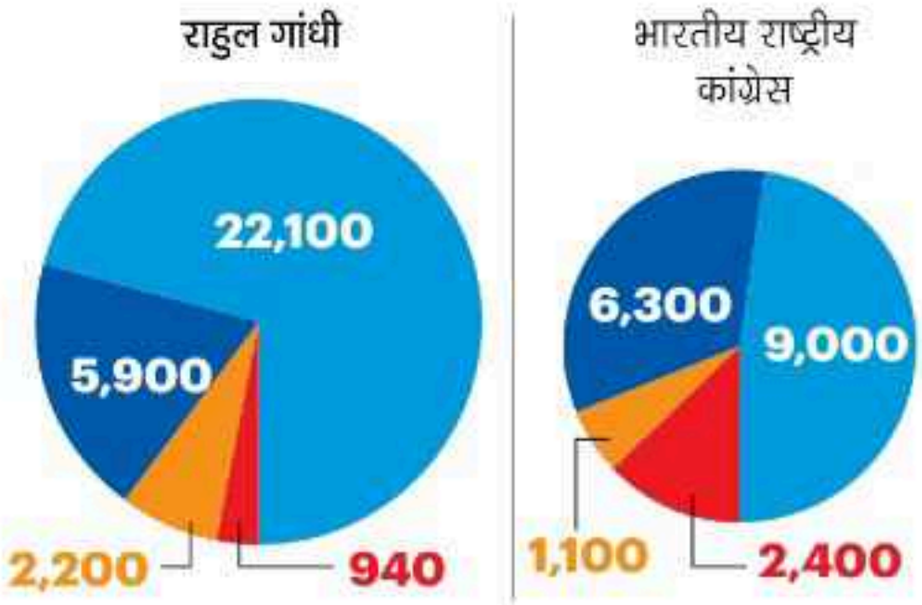

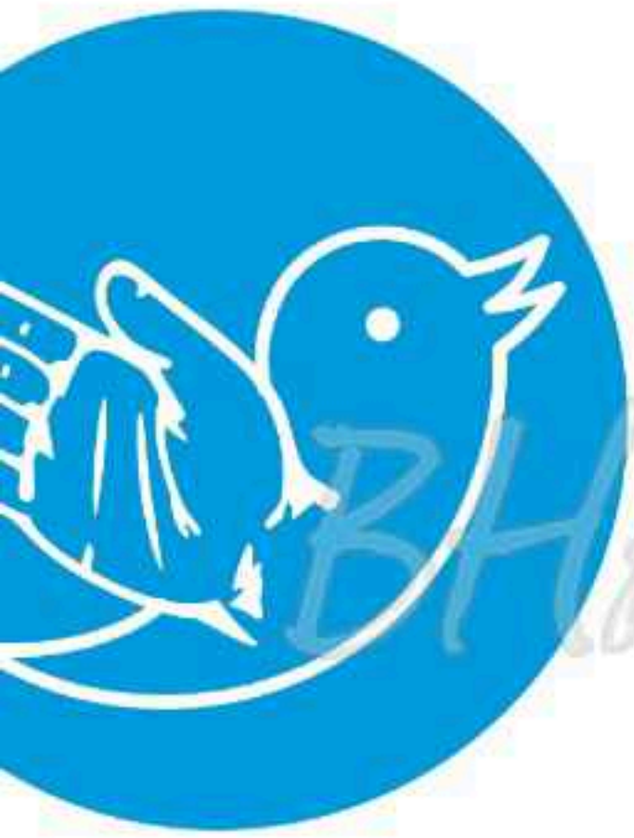

कांग्रेस बनाम अन्य पार्टियां

नोटः इन तीन पार्टियों की सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोइंग है

ग्राफिक्स : तन्मय चक्रवर्ती

आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने जवाब में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का कथित इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने अपने साथ बैठी एक लड़की का वीडियो साझा किया था, जो भाजपा के राज के बारे में गुजराती में बात कर रही थी. श्रीनेत कहती हैं, ''हम हमेशा कुचक्री ट्रोल अभियान झेलते नहीं रह सकते. हम तथ्यों पर टिके रहेंगे... हम गाली-गलौज पर नहीं उतरेंगे. लेकिन वे अगर यह सब करते रहे, तो उन्हें वैसे ही जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर वे फेक न्यूज फैलाना और गाली-गलौज बंद कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा न करे. हम अब इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं.''

राहुल गांधी की व्यक्तिगत दिलचस्पी की वजह से भी उनकी पार्टी के सोशल मीडिया अभियान को मजबूती मिली है. श्रीवत्स की अगुआई वाली 10 सदस्यीय टीम की मदद से, राहुल खुद अपने सोशल मीडिया एकाउंट संभालते हैं. उनके एक करीबी सहयोगी का दावा है कि इसी वजह से उनके पोस्ट संख्या में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले काफी कम हैं. मसलन, 1 नवंबर से 21 नवंबर के बीच, राहुल ने 55 ट्वीट किए, जबकि मोदी के ट्वीट की संख्या 214 थी. वे बताते हैं, ''वे भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, और सिर्फ विश्राम के दौरान ही पोस्ट कर सकते हैं. इसलिए उनके ट्वीट कम हैं.'' वे यह भी खुलासा करते हैं कि राहुल कंटेंट को विजुअलाइज और क्यूरेट करने में सक्रिय दिलचस्पी लेते हैं. दरअसल, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत के वीडियो या यात्रा की ड्रोन से खींची गई तस्वीरें पोस्ट करने का आइडिया खुद राहुल का था. वे कहते हैं, ''वे लोगों की भागीदारी और दिलचस्पी पर फोकस चाहते हैं.''

कांग्रेस सोशल मीडिया पर विरोधियों से आक्रामक ढंग से निबट रही है, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही है और यहां तक कि उन्हें अदालत तक भी ले जा रही है

राहुल के सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों का जुड़ाव और उन पर प्रतिक्रिया की दर वाकई बढ़ी है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले. *इंडिया टुडे* की पड़ताल में पता चला कि 1 नवंबर से 21 नवंबर के बीच, उनके ट्वीट में रुचि लेने वालों की संख्या मोदी के मुकाबले लगभग दोगुनी थी (देखें बॉक्स), जबकि मोदी के फॉलोअर की संख्या राहुल के मुकाबले लगभग चार गुनी है. 1 जनवरी, 2019 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि राहुल के ट्वीट पर लोग मोदी के मुकाबले अधिक प्रतिक्रिया दे रहे थे. राहुल के एक सहयोगी कहते हैं, ''हमने नए आंकड़ों की पड़ताल नहीं की है, लेकिन खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे वीडियो केंद्रित प्लेटफॉर्म पर लोगों की दिलचस्पी में अभूतपूर्व उछाल देखा गया है.''

भारत जोड़ो यात्रा के कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, वरिष्ठ नेताओं को ''विनम्र निर्देश'' भेजे गए कि ऐसे कंटेंट का प्रसार करें. संचार टीम के एक सदस्य कहते हैं, ''हमने 33 नेताओं की साल भर की सोशल मीडिया गतिविधियों पर एक रिपोर्ट तैयार की और उन्हें दिखाई. उन्होंने शायद ही कभी राहुल गांधी या कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट की गई किसी बात को आगे बढ़ाया था. अब वे सभी सक्रिय और आक्रामक हो गए हैं.''

कंटेंट को तुरंत तैयार करने में पेशेवर मदद का जिम्मा पार्टी ने मुंबई स्थित डिजिटल मीडिया आउटरीच एजेंसी तीन बंदर को दिया है. एजेंसी भारत जोड़ो यात्रा का लोगो डिजाइन करने और गीत तैयार करने के अलावा, यात्रा की वेबसाइट का काम भी संभालती है. रमेश कहते हैं, ''हमारी पार्टी की स्थायी टीमें छोटी

हैं. भारत जोड़ो यात्रा जैसे बड़े अभियान के लिए हमें अतिरिक्त पेशेवर कार्यबल की जरूरत थी. तीन बंदर उस जरूरत को पूरा करती है. एजेंसी का कंटेंट में कोई संपादकीय हस्तक्षेप नहीं है.''

रमेश, श्रीनेत और श्रीवत्स के नेतृत्व वाली तीनों टीमों के साथ बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और पार्टी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो खुद कंटेंट तैयार कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा नौ बार के लोकसभा सदस्य कमलनाथ कहते हैं, ''मैंने अपने पूरे राजनैतिक जीवन में कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा. भारत जोड़ो यात्रा से संगठन में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है.'' एक कार्यकर्ता के मोबाइल फोन से यात्रा की सबसे अधिक वायरल छवियों में से एक इसी तरह निकली. 6 अक्तूबर को कर्नाटक में सोनिया गांधी यात्रा में चल रही थीं तो राहुल गांधी अपनी मां के जूते के फीते बांधने के लिए झुके. श्रीनेत कहती हैं, ''यह अचानक हुआ था और आस-पास कोई कैमरा भी नहीं था. हमें एक साधारण कार्यकर्ता से यह वीडियो मिला.'' उन्हें लगता है कि ऐसे सुनहरे पलों की योजना नहीं बनाई जा सकती. वे यह भी कहती हैं, ''राहुल गांधी कैमरे में आने के लिए कुछ नहीं करते. वे अचानक किसी बूढ़ी औरत को गले लगा लेते हैं या किसी किसान की बात पूरी ईमानदारी से सुनने लगते हैं. वहां मौजूद लोगों के लिए यह चुनौती होती है कि उस पल को कैमरे में कैद कर लें. ऐसा कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन यह सब सहज रूप से होता है, इसलिए हमें अधिक प्रेरणास्पद और भावनात्मक छवियां मिलती हैं.''

एएनआइ

लक्ष्य भेदने का अभ्यास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यात्रा के खंडवा, मध्य प्रदेश पहुंचने पर

राहुल के स्वाभाविक क्षण तो हैं ही, पर भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया प्रचार की योजना पहले से तैयार की जाती है, ताकि कहानी को सही स्वर दिया जा सके

लेकिन ऐसी सामग्री पाने के लिए श्रीनेत की टीम को हर दिन बड़ी संख्या में छवियों और वीडियो को छानना पड़ता है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरतों के मुताबिक उनका संपादन और पैकेजिंग करनी पड़ती है. यह टीम कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल के लिए यह काम करती है, जबकि श्रीवत्स की अगुआई वाली टीम राहुल के व्यक्तिगत सोशल मीडिया हैंडल के लिए कंटेंट क्यूरेट करती है. तीनों टीमों के बीच लगातार तालमेल बना रहता है कि क्या वायरल हो सकता है और क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ठीक है. यात्रा का सब कुछ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट नहीं किया जाता, जबकि भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल पर यात्रा से संबंधित सामग्री ही होती है.

यह तीन टीमों के लिए कोई आसान काम नहीं है, जिनमें कुल 80 लोग भी नहीं हैं. लगातार भारी मात्रा में वीडियो और विजुअल्स की बारिश होती रहती है और उन्हें अमूमन 30 मिनट से कम समय में मुनासिब रीपैकेजिंग करनी पड़ती है. कई बार, यात्रा खराब कनेक्टिविटी वाले स्थानों से होकर गुजरती है, तो वीडियो और फोटो की आमद ठप हो जाती है. यही नहीं, राहुल की सुरक्षा के लिए लगाए गए जैमर भी दिक्कत पैदा करते हैं. श्रीनेत कहती हैं, ''इन चुनौतियों के बीच हमारी टीमें लगातार सही सामग्री की तलाश में रहती हैं. सही कंटेंट चुनने का मेरा बैरोमीटर यह है कि टीम को विजुअल्स देखकर कैसा लग रहा है. मसलन, जब रोहित वेमुला की मां या गौरी लंकेश की मां और बहन राहुल गांधी के साथ चलीं, तो कमरे में सभी की आंखें नम हो गईं. वे बड़े मार्मिक पल थे. ऐसे ही मौके भारत जोड़ो यात्रा को इतना खास और मानवीय बना रहे हैं. इसका संदेश राजनीति से ऊपर उठ कर लोगों के दिलों को छू रहा है.''

लेकिन राहुल की सहज-स्वाभाविक छवियां ही यात्रा के सोशल मीडिया प्रचार लोकप्रियता की तरफ नहीं ले जा रहीं. पैकेजिंग की रूपरेखा को एक खास स्वर देने के लिए योजनाबद्ध ढंग से तैयार किया गया है. मसलन, राहुल ने विदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की आत्महत्या पर बात की. इसके पहले ही, दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में बैठी सोशल मीडिया टीम ने किसानों की आत्महत्याओं का डेटा ग्राफिक्स के साथ तैयार कर लिया था, ताकि उस पोस्ट से लोगों को यह समझ में आ सके कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है. जब राहुल ने तिरुवनंतपुरम में मनरेगा मजदूरों से बातचीत की, तो टीम योजना से संबंधित आंकड़ों के साथ तैयार थी, ताकि उनकी मांगों से देश की अगली पीढ़ी को वाकिफ कराया जा सके.

कई बार संदर्भ सामग्री की तलाश देर से भी की जाती है. मसलन, कर्नाटक में राहुल ने एक बूढ़ी औरत को अपने हाथ में दो खीरे लिए खड़े देखा और जिज्ञासावश उससे बातचीत की. उसके कंधे पर हाथ रखे राहुल की तस्वीर सोशल मीडिया टीम के पास आई. सोचा गया कि कोई बूढ़ी महिला नेहरू-गांधी खानदान के वारिस पर स्नेह बरसा रही है. बाद में, उन्हें पता चला कि बातचीत का एक ऐतिहासिक महत्व था—उस महिला ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 'ग्रोवर्स लैंड पॉलिसी' के तहत मिली जमीन पर दो खीरे उगाए थे. इसलिए, वे खीरों को इंदिरा के पोते को उपहार में देना चाहती थीं. भावनात्मक संदर्भ के साथ दृश्य को दोबारा तैयार करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया गया.

वाकई, कांग्रेस के सोशल मीडिया योद्धाओं के लिए घटनाओं के संदर्भ महत्वपूर्ण हैं. उनके मुताबिक, भारत जोड़ो यात्रा इतिहास बना रही है और वे पूरे जोश से उसकी याददाश्त को संजो रहे हैं. श्रीनेत कहती हैं, ''हमने इस तरह के बड़े असर का अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन अब यह देश के राजनैतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मौके की तरह खुल रही है.'' पार्टी की सोशल मीडिया टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं कि देश भारत जोड़ो यात्रा को उनके ऐतिहासिक चश्मे से देखे. ■

विधानसभा में नया विधान

देश में पहली बार किसी सदन की कार्यवाही को पेपरलेस बनाना हो या फिर महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ऐसी कई अनोखी पहल शुरू की हैं

आशीष मिश्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना 10 अगस्त को महिला विधायकों से भेंट कर रहे थे. इस दौरान उन्हें पता चला कि ज्यादातर महिला विधायक सदन में क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित लिखित सूचनाएं और प्रश्न तो लगाती हैं लेकिन किसी मुद्दे पर मुखरता से कभी नहीं बोलतीं. बैठक के बाद जब महाना ने विधानसभा की पिछली कार्यवाहियों के आंकड़े खंगाले तो पता चला

बदलावों के अगुआ
विधान प्रणाली युक्त यूपी विधानसभा सदन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

मनीष अग्निहोत्री

"मेरी विधानसभा में अब अपराधियों की गिनती नहीं होती बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए की गिनती होती है"

सतीश महाना,
स्पीकर, उत्तर प्रदेश विधानसभा

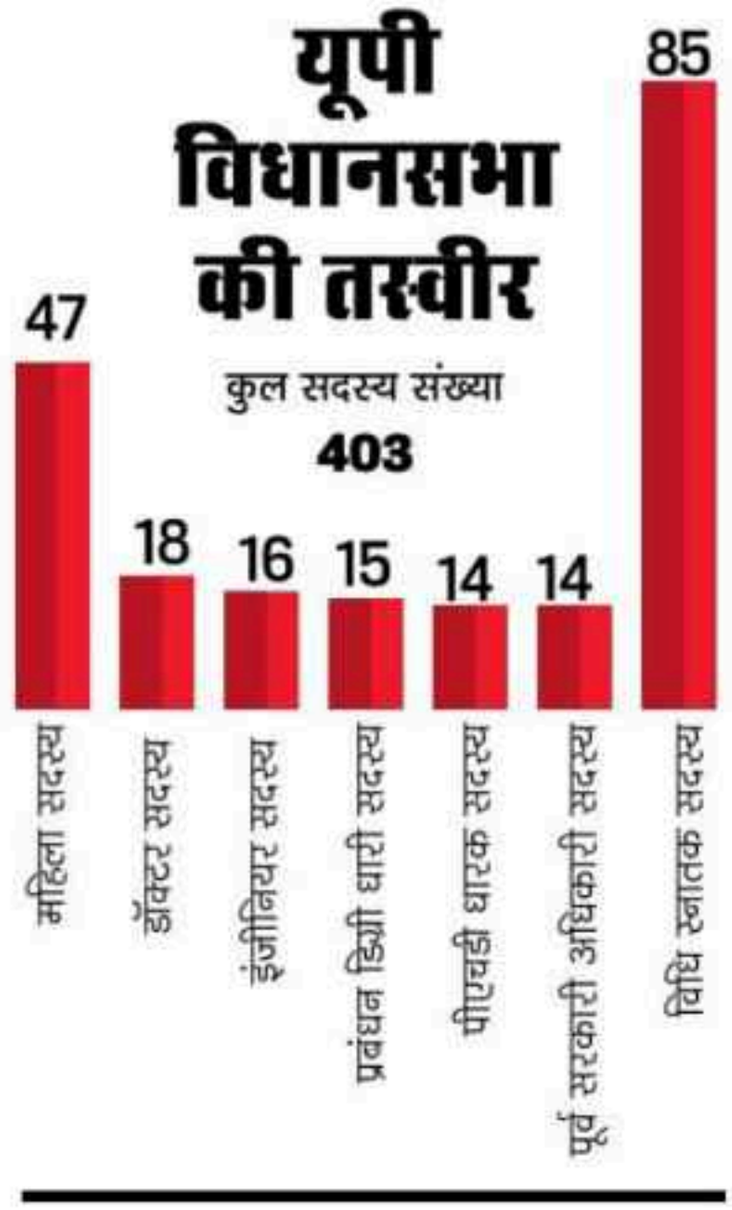

कि पांच फीसद से कम महिला विधायक सदन की बहस में हिस्सा लेती हैं. इसके बाद महाना की पहल से महिला विधायकों की सदन में हिचक और खामोशी तोड़ने के लिए एक अनोखे उपवेशन की नींव पड़ी.

विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान 22 सितंबर को आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें सदन की कार्यवाही में केवल महिला सदस्यों ने ही भागीदारी की. वैसे तो हर सदस्य के बोलने के लिए पहले न्यूनतम तीन और अधिकतम आठ मिनट तय किए गए थे लेकिन नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि महिला सदस्यों के बोलने में कोई समय सीमा न रखी जाए. नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी की बात का समर्थन किया. फिर क्या था, 8 घंटे 12 मिनट तक चली सदन की कार्यवाही में एक-एक करके कुल 38 महिला विधायकों ने अपनी बात रखी. इसी दौरान सतीश महाना ने विधायक सैयदा खातून, मंजू सिवाच समेत कई महिला विधायकों को बुलाकर अपनी जगह अधिष्ठाता की सीट पर बिठाया. सदन में सत्ता पक्ष की दीर्घा में उपमुख्यमंत्री के लिए आवंटित सीट पर राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम को बिठाया गया. पटल पर प्रस्ताव और सूचनाएं विजय लक्ष्मी गौतम के माध्यम से ही प्रस्तुत कराई गईं.

यह पहला मौका था जब देश की किसी विधानसभा ने महिला सदस्यों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया हो. महिला विधायकों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आयोजित कर इतिहास रचने वाले यूपी विधानमंडल में एक और नई पहल होने जा रही है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ऐसे विधायकों के लिए विशेष सत्र बुलाने की योजना तैयार कर रहे हैं जिन्होंने 18वीं विधानसभा के बजट सत्र से लेकर मॉनसून सत्र तक चुप्पी साधे रखी है. ऐसे करीब 100 विधायक हैं जिन्हें सदन में या तो बोलने का मौका नहीं मिला या फिर उन्होंने प्रयास ही नहीं किया. इतना ही नहीं, युवा विधायकों के लिए भी विशेष सत्र बुलाने के मकसद से महाना इसके सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं. प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और आठ बार के विधायक 62 वर्षीय सतीश महाना 18 वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. उन्होंने अपने नाम से जाति को हटाकर पाकिस्तान में अपने पुश्तैनी गांव का नाम "महाना" जोड़ा और सतीश महाना कहलाए. वे भाजपा की पिछली सरकार में औद्योगिक विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री थे. 29 मार्च को स्पीकर का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सतीश महाना के नवाचारों ने यूपी विधानसभा को देश भर में एक नई पहचान दिलाई है. 5 दिसंबर से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा सत्र के दौरान स्पीकर गैलरी समेत विधानभवन की अन्य गैलरियों का रूप बदला हुआ दिखेगा. सभी गैलरियों को संवारा गया है. इनमें महापुरुषों के चित्र तो लगाए ही गए हैं, पहली बार यहां लगे 18वीं विधानसभा के विधायकों के चित्र भी सदस्यों की उत्सुकता बढ़ाएंगे.

विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यालय के अधिकारियों के साथ पहली बैठक में सतीश महाना ने ई-विधान व्यवस्था लागू करने की समयसीमा तय कर दी थी. बजट सत्र के रूप में विधानसभा की पहली बैठक से पहले विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह से डिजिटल करने का लक्ष्य तय हुआ. इसमें सबसे बड़ी अड़चन सदन के भीतर सभी विधायकों की मेज पर डिजिटल स्क्रीन की व्यवस्था करनी थी. इसके लिए 400 से अधिक टैबलेट की तुरंत जरूरत थी. महाना बताते हैं, "मैं पिछली सरकार में औद्योगिक विकास विभाग का कैबिनेट मंत्री था. इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के दौरान मेरा सैमसंग के अधिकारियों से परिचय हो गया था. मैंने उनसे संपर्क किया और नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन समेत सभी जरूरी साफ्टवेयर से लैस टैबलेट मुहैया कराने का निवेदन किया." एक महीने के भीतर टैबलेट की व्यवस्था हो गई और उन्हें सभी विधायकों की सीट पर लगा दिया गया. 20 मई को यूपी विधानसभा में एक नई शुरुआत हुई जब विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस करने की योजना साकार हुई. दो दिन बाद

सदन में शक्ति
विधानसभा के विशेष महिला सत्र में बोलतीं विधायक अंजुला सिंह माहौर और अधिष्ठाता सीट पर मौजूद डॉ. मंजू सिवाच

23 मई को पहली बार यूपी विधानसभा का बजट भी पेपरलेस ढंग से पेश हुआ. इस तरह विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना.

एक ओर विधानसभा डिजिटल हो रही थी तो दूसरी ओर सदन में विधायकों के बैठने की सीटें भी कम थीं. यूपी विधानसभा सदन में 403 विधायकों और एक महाधिवक्ता को मिलाकर कुल 404 सीटों की आवयश्कता होती है. इसके अलावा विधान परिषद सदस्य के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री भी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित होते हैं. इनके लिए भी अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता थी. विधायकों के बैठने के बारे में जानकारी हासिल करने पर महाना को पता चला कि सदन में केवल 379 सदस्यों के ही बैठने की व्यवस्था है. दलीय व्यवस्था के तहत निर्धारित सीटों में जो भी सदस्य जहां स्थान पाता था, बैठ जाता था. बैठकों के दौरान कई सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण यह व्यवस्था चली आ रही थी. पहली बार विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों की संख्या के आधार पर विधानसभा सदन में सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया. महाना बताते हैं, ''सदन में सदस्यों के बैठने के लिए गैलरी में सीटें लगवाई गईं. इसके अलावा पीछे की ओर की सीटें काफी चौड़ी थीं, यहां पर अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की गई. इस प्रकार बजट सत्र से पहले सदन में कुल 417 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई.'' सदन की कार्यवाही के दौरान कोई सदस्य जैसे ही बोलने के लिए खड़ा होता है उसका पूरा प्रोफाइल सदन में लगी दो टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगता है. साथ ही बोलने के लिए तय समय का काउंटडाउन भी मॉनिटर पर शुरू हो जाता है.

विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही महाना ने विधायकों की इमेज बदलने के लिए खास प्रयास शुरू किए. महाना ने डाक्टर, इंजीनियर, एमबीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री धारक विधायकों की सूची बनवाई और इनके साथ अलग-अलग बैठकें की. पहली बैठक डॉक्टर डिग्री धारक 18 विधायकों के साथ की. महाना बताते हैं ''मैंने सभी प्रोफेशनल डिग्री धारक विधायकों को प्रेरित किया कि वे अपनी योग्यता का इस्तेमाल जनता के हित के कार्यों में करें.'' इसके बाद महाना ने 40 वर्ष से कम उम्र वाले 52 युवा विधायकों के एक समूह के साथ बैठक की. महाना बताते हैं, ''मैंने युवा विधायकों से पूछा कि मैं आठ बार का विधायक हूं, आप लोगों के पास आठ बार चुनाव जीतने और भविष्य में बड़े नेता बनने का क्या रोडमैप है.'' इसके बाद ऐसे वरिष्ठ विधायकों के साथ महाना ने बैठक की जो पांच या इससे अधिक बार विधायक बने हैं. महाना ने इनसे विधानसभा में आ रही गिरावट को रोकने और आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के बारे में सुझाव मांगे.

विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सतीश महाना की कार्यप्रणाली ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का विश्वास जीता है. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद जब 23 मई को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो सदन में जोरदार हंगामा होने की अटकलें लगाई जा रही थीं. समाजवादी पार्टी अपनी सीटों में काफी इजाफा करते हुए गठबंधन दलों के साथ 125 विधायक लेकर सदन में मौजूद थी. सत्र के पहले दिन 23 मई को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों के विधायकों ने संसदीय गरिमा का पूरा ध्यान रखते हुए सदन के वेल में आकर प्रदर्शन किया. बजट सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी झड़प हुई. कई मौके ऐसे भी आए जब सपा और भाजपा के सदस्य सदन में एक दूसरे के सामने आ गए लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी वाक्पटुता और नेतृत्व कौशल से विधानसभा की कार्यवाही बाधित नहीं होने दी. यह पहली बार था कि नौ दिन तक चला बजट सत्र एक बार भी स्थगित नहीं हुआ. इसके बाद मानसून सत्र में भी यही परंपरा जारी रही.

सदन की कार्यवाही के दौरान आए इस बदलाव की वजह महाना यह बताते हैं, ''पहले सदन में विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टियों को बोलने का समय निर्धारित होता था मैंने यह परंपरा बंद कर सत्ता और विपक्ष के विधायकों को सदन में बोलने के लिए बराबर समय दिया. साथ ही सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले अनुपूरक प्रश्नों की संख्या दो निर्धारित कर दी. इससे अधिक से अधिक सदस्यों के प्रश्नों के जवाब मिलने लगे. इससे विपक्ष के सदस्यों का सदन के प्रति विश्वास बढ़ा.'' इसका असर यह हुआ कि सदन की कार्यवाही के दौरान जितने भी तारांकित प्रश्न निर्धारित होते हैं, उनके सबके जवाब सदस्यों को मिलने लगे. नतीजा विधानसभा की कार्यवाही में सदस्यों की उपस्थिति पर भी दिखा है जो अब चार गुना तक बढ़ गई है.

विधानसभा की कार्यवाही में अगले सुधार के क्रम में वर्ष 1958 में बनी विधानसभा संचालन की नियमावली में बदलाव की रूपरेखा बनी है. नियमावली के गैर जरूरी नियमों को बदलने के लिए समीक्षा की जा रही है. इसके बाद विधानसभा की नियम समिति यह निर्णय करेगी कि कौन-कौन से नियम बदले जाएं और ई-विधान से जुड़े कौन से नए नियम शामिल किए जाएं. समिति के निर्णय के बाद सदन उसपर अंतिम मुहर लगाएगा. ■

नजीर पेश कर रहा सदन

- विधानभवन को रंगबिरंगी फसाड लाइटों से सजाया गया है जो गीतों की धुन के अनुसार बदलती हैं
- विधानसभा सदन के भीतर पहली बार विधायकों का जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू की गई
- संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद की तर्ज पर ''सर्वश्रेष्ठ विधायक'' चुने जाने की योजना तैयार की जा रही है
- कार्यवाही छोड़कर विधायकों को बार-बार कैंटीन नही जाना पड़े इसके लिए कॉफी लॉबी बनवाई गई
- समाज के अलग-अलग वर्गों और स्कूली बच्चों का विधानभवन का टूर कराने की योजना बन रही है

‘मैंने किसी का टिकट नहीं काटा’

पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सियासत में **सी.आर. पाटिल** की शुरुआती योजना सूरत नगर निगम में पार्षद बनने की थी लेकिन वे कई उतार-चढ़ाव देखते हुए 2009 में पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा पहुंचे. 2019 में नवसारी से रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के एक साल बाद उन्हें गुजरात प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया. गुजरात चुनाव से जुड़े मुद्दों पर संपादक **सौरभ द्विवेदी** से उनकी बातचीत के मुख्य अंशः

रजत सैन

● लोग आपको बाहरी कहते हैं? इस पर आपका क्या कहना है?

मैं जन्म से गुजरात में हूं. तीन बार यहां के लोगों ने मुझे अपना समझकर लोकसभा भेजा. विरोधियों को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वे यह मुद्दा उठाते हैं जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के नहीं हैं.

● ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद पर आपके नाम पर लगभग मुहर लग गई थी. लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए.

जब नए मुख्यमंत्री का चयन होता है तो आठ-दस नाम उछलते ही हैं. मैं पार्टी अध्यक्ष था. मेरा नाम भी उछला था. हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में जाते हैं. वहां हमें सीख दी जाती है कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है, हम उसके योग्य बनें, यह नहीं सिखाया जाता कि मैं योग्य हूं तो इसलिए मुझे यह जिम्मेदारी मिलनी चहिए. मैंने यह बात अपने जीवन में ढाल रखी है.

● आप पर कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटने के आरोप लगे हैं. इसके चलते हुई बगावत को शांत करने के लिए खुद अमित शाह को अहमदाबाद आना पड़ा?

न तो मैंने किसी का टिकट काटा और न ही किसी के लिए सिफारिश की. मेरे पास जितने भी लोग टिकट की दावेदारी लेकर आए थे, मैंने सबका नाम ऊपर भेज दिया. टिकट बांटने पर आखिरी फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड ने लिया था.

● कहा जाता है कि आपके और विजय रुपाणी के बीच सब-कुछ ठीक नहीं है.

वे मुझ से सीनियर लीडर हैं. उनका लंबा राजनैतिक जीवन है. वे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में रहे और विधानसभा में भी रहे. वे कॉर्पोरेशन के चैयरमेन भी थे. उनके सामने मैं बच्चा हूं. मैं उनके साथ कोई अदावत नहीं पाल सकता और यह मेरे स्वभाव में भी नहीं है.

● भाजपा आम आदमी पार्टी पर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है लेकिन आपने भी इस चुनाव में मुफ्त सिलेंडर, वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए बस में मुफ्त यात्रा जैसी घोषणाएं की हैं.

आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही उसका समाज पर गलत असर होगा. अगर आप युवाओं को 3,000 रुपए महीना देना शुरू कर दोगे तो वे काम नहीं करना चाहेंगे लेकिन अगर कोई जरूरतमंद है, जैसे सीनियर सिटिजन, महिला वगैरह, उनकी मदद की जानी चाहिए. केजरीवाल ने जो वादे किए हैं उसके लिए सालाना साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए चाहिए लेकिन गुजरात का बजट ही ढाई लाख करोड़ का है. केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं, वे पूरे कैसे करेंगे?

● गुजरात में बार-बार पर्चे लीक हो रहे हैं. कई मामलों में भाजपा कार्यकर्ताओं की मिलीभगत सामने आई है. इस बारे में क्या कहेंगे?

अगर कोई आपके घर में चोरी करे तो इसमें आपका क्या दोष. मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम लोग ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि कोई चाहकर भी पेपर लीक न कर सके. इस मामले में अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा गया है तो यह दिखाता है कि सरकार कितनी सख्त है.

● मुख्यमंत्री इस चुनाव में एक भी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं. पार्टी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है क्या?

इस बात से मैं सहमत नहीं हूं. क्या सिर्फ इंटरव्यू देकर ही चुनाव लड़ा जाता है? मैंने ने भी बहुत इंटरव्यू नहीं दिए. पिछले दस दिन से कहीं जनसभा करने नहीं गया. इसका क्या मतलब है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं?

● इस बार भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे कहा कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए. हम उनकी बात को सच करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं. इस बार भाजपा अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है. ■

एएनआइ

वादों की बहार
अपने-अपने घोषणापत्र जारी करते हुए भाजपा (बाएं), कांग्रेस (ऊपर, दाएं) और आम आदमी पार्टी के नेता

गुजरात /चुनावी वादे

'शहरी' गुजरात को रिझाने की कवायद

जुमाना शाह

गांव के गरीब-गुर्बों को बेदखल करके मध्य वर्ग का मतदाता गुजरात में राजनैतिक संदेशों का मुख्य लक्ष्य बन गया है. राज्य के करीब 45 फीसद मतदाता 40 साल से कम उम्र के हैं. यह भारत का दूसरा सबसे ज्यादा शहरी राज्य भी है. इसकी 182 में से 58 सीटें अब शहरी हैं, जिनमें से भाजपा ने 2017 में 44 जीती थीं. इसके अलावा और 35-40 सीटों ने अर्धशहरी दर्जा हासिल कर लिया है. यह सब राजनैतिक बहस-मुबाहिसों में भी दिखाई दे रहा है. लिहाजा मध्य वर्ग को रिझाना भाजपा और आप दोनों की मजबूरी है (कांग्रेस अपने पुराने जाति गठजोड़ 'खाम' यानी कोली क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम की तरफ लौट गई है और इसका मतलब है उसका इस चुनावी अफसाने में ज्यादा योगदान नहीं है). 'रेवड़ी संस्कृति' का मखौल उड़ाते जबानी जमा-खर्च के बावजूद इस बार मुफ्त रियायतें विभिन्न वर्गों के युवाओं और बेरोजगारों पर न्योछावर हैं. यह झुकाव उस चीज से बेहतर कहीं और दिखाई नहीं देता जिसकी गैरमौजूदगी भाजपा के वादों की फेहरिस्त में साफ नजर आती है, जैसे कि यहां किसानों के मसले पर कोई बात नहीं हो रही है.

भाजपा के वादे

- गुजरात को पांच साल में 1 खरब या ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना–जिसके लिए 19.4 लाख करोड़ रुपए के मौजूदा आकार से चार गुना छलांग लगानी होगी
- 2036 के ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में करना
- आइआइटी की तर्ज पर चार गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान
- एम्स के स्तर के दो संस्थान
- 5 लाख करोड़ रुपए के विदेशी निवेश आकर्षित करना, गुजरात को भारत का रक्षा और विमानन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना
- दो सीफूड पार्क की स्थापना करना (एक दक्षिण गुजरात में और एक सौराष्ट्र में), भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना

वादों की बहार

शिक्षा
भाजपा: केजी से पीजी तक सभी छात्राओं को मुफ्त और अच्छी शिक्षा
कांग्रेस: वंचित समुदायों के लिए सरकारी स्कूलों में केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा
आप: सरकारी स्कूलों में सभी के लिए मुफ्त शिक्षा

स्वास्थ्य
भाजपा: आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए से 10 लाख करना और साथ ही ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए सरकारी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त जांच
कांग्रेस: 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा
आप: सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा

रसोई गैस
भाजपा: ईडब्ल्यूएस परिवारों को साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर
कांग्रेस: सब्सिडी देकर 500 रुपए में सिलिंडर
आप: खामोश

आवास
भाजपा: गुजरात में हर नागरिक को पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 100 फीसद अमल
कांग्रेस: सभी भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को प्राथमिकता से आवास

खाद्य पदार्थ
भाजपा: पीडीएस के जरिए साल में चार बार 1 लीटर खाद्य तेल, हर माह 1 किलो सस्ता चना

बिजली
भाजपा: (घोषणापत्र में नहीं, मोदी के भाषण में): बिजली बनाकर कमाओ, न कि मुफ्त पाओ
कांग्रेस/आप: मुफ्त 300 यूनिट

‘कांग्रेस और भाजपा में फिक्सिंग होती थी’

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री **शंकर सिंह वाघेला** से उनकी राजनैतिक यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधों और राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर संपादक **सौरभ द्विवेदी** की बातचीत के मुख्य अंशः

● क्या आप एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं?

यह मैंने मीडिया के माध्यम से जाना कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद आने वाले हैं और मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं. न मैंने किसी को ऐसा बताया और न ही मुझसे ऐसा किसी ने कहा. यह मीडिया क्रिएशन के अलावा कुछ नहीं है.

● आपके बेटे महेंद्र सिंह ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है.

महेंद्र भाई को भाजपा और आप से ऑफर थे. लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आप भाजपा ज्वाइन करते हैं तो मैं आपके प्रचार में नहीं आ पाऊंगा. मैं सौ फीसद भाजपा विरोधी हूं. मैंने कांग्रेस वालों से कहा कि अगर आप महेंद्र भाई का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाइए.

● आपकी नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात कब हुई?

संघ के कार्यक्रमों में मेरी नरेंद्र मोदी से शुरुआती जान-पहचान हुई. एक और बात मैं आपको बताऊं जो लोग उनकी शिक्षा के बारे में कहते हैं, मेरी जानकारी में उन्होंने पत्राचार से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया था. आगे की पढ़ाई का मुझे पता नहीं. इसी तरह उनकी शादी के बारे में काफी बातें होती हैं. मैं ऑन रिकॉर्ड यह बात कहता हूं कि उनकी शादी हुई लेकिन वे वैवाहिक जीवन में नहीं रहे.

● कहा जाता है कि अगर शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के साथ बने रहते तो 2017 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ बना माहौल अपनी नियति तक पहुंच जाता.

मैं आपकी इस बात से सहमत हूं. लेकिन अगर आपको हमारी जरूरत ही नहीं तो हम क्या करेंगे. 2017 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो किसको तकलीफ होती? भाजपा को होती. 2012 में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, क्यों नहीं बनने दी. यही मैच फिक्सिंग थी. मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कांग्रेस के नेता भाजपा के साथ डील कर रहे थे. जो नाम हम सोनिया गांधी के पास टिकट के लिए भेजते उसके खिलाफ लोग हो जाते. अगर मैं ज्यादा बहस करता तो कहा जाता कि मैडम पर छोड़ दो. 15-17 ऐसी सीटें मैडम पर छोड़ी जाती थीं. फिर मैं उन्हें पत्र लिखता लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता.

● 2009 में आप गोधरा से तीन हजार से कम वोटों से लोकसभा चुनाव हारे. लेकिन कहा गया कि कांग्रेस के लोगों ने ही आपको हरा दिया. क्या था मामला?

गोधरा के साथ हमेशा से मेरे ऐसे ही अनुभव रहे. मैं वहां दो बार चुनाव लड़ने गया. दोनों बार हाइकमान के

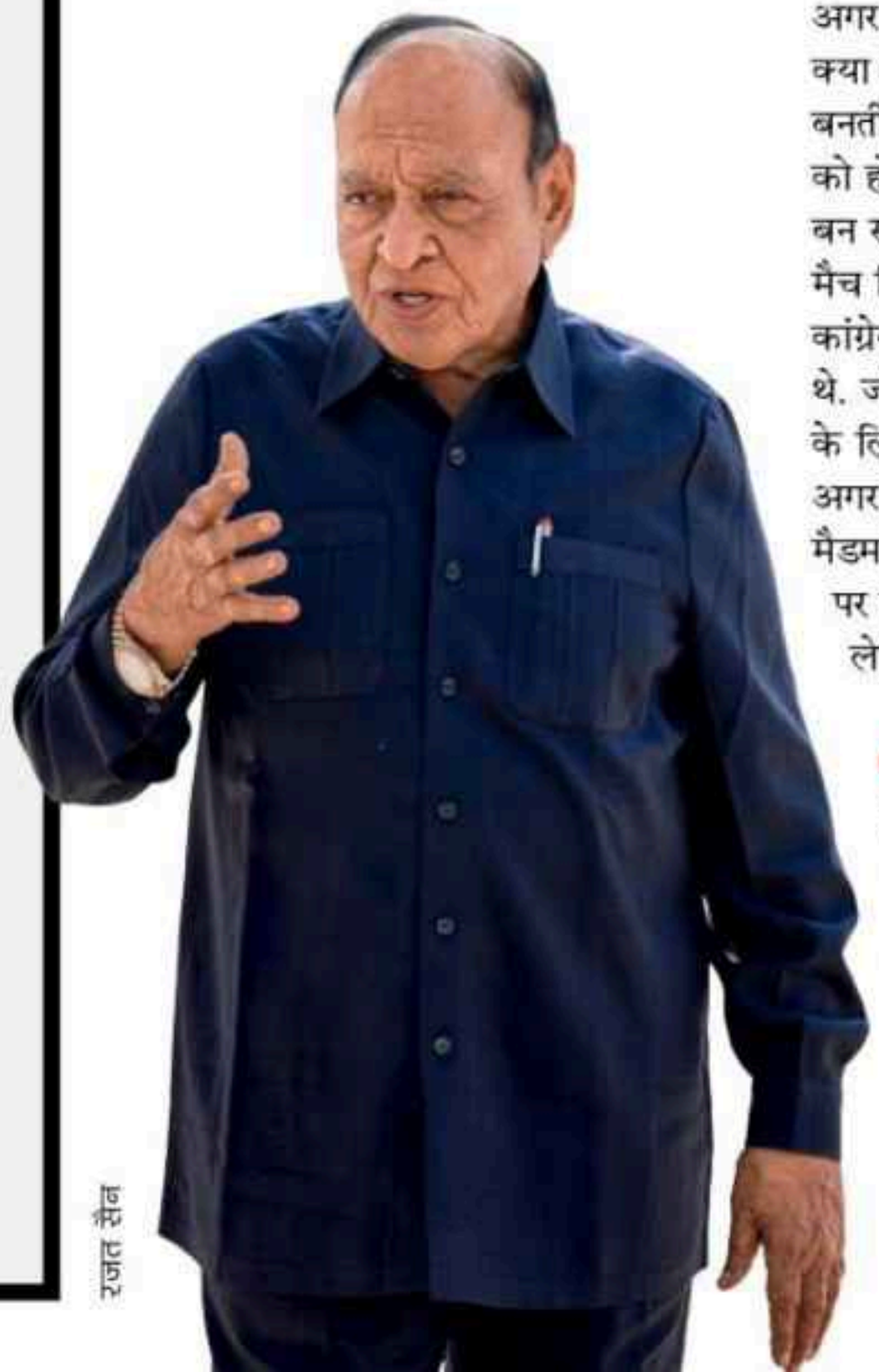

रजत सैन

इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप

↘ शहरी बुनियादी ढांचा

भाजपाः सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाइवे ग्रिड का निर्माण. सभी महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को जोड़ा जाएगा. सैटेलाइट टाउनशिप का विकास. नदी के तटों, पार्कों और शहरी वनों का विकास. ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करना. गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा में मेट्रो परियोजना

कांग्रेसः सूरत, राजकोट, वडोदरा में मेट्रो परियोजना शुरू की जाएगी

↘ नौकरियां

भाजपाः पांच साल में 20 लाख नौकरियां, महिलाओं को 1,00,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी

आप/कांग्रेसः 10 लाख नई सरकारी नौकरियां. कांग्रेस ने इसके अलावा 5,00,000 लाख सरकारी नौकरियों के साथ महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण का वादा किया

↘ बेरोजगारी

भाजपाः खामोश

आप / कांग्रेसः युवाओं को 3,000 रुपए महीने का भत्ता. आप ने इसके अलावा 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना भत्ते का वादा किया है

↘ धर्म

भाजपाः पश्चिमी भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देवभूमि द्वारका गलियारे की स्थापना, विश्व की सबसे ऊंची कृष्ण प्रतिमा

कांग्रेसः तीर्थस्थलों तक सीधे बस कनेक्टिविटी

आपः अयोध्या की मुफ्त यात्रा

↘ अन्य रेवड़ियां

भाजपाः रुपए-पैसे से कमजोर परिवारों की कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर, वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा, कक्षा 9 से 12 की सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल

कांग्रेसः एमवीए,

किसानों के कर्ज

भाजपाः खामोश

कांग्रेसः किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ

आपः किसानों के 2 लाख रुपए तक के बकाया कर्ज माफ

‘बेरोजगारी नहीं, महंगाई बड़ा मुद्दा’

गुजरात की वडगाम सीट से 2017 में निर्दलीय विधायक चुने गए **जिग्नेश मेवाणी** इस बार इसी सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. इस चुनाव में पार्टी की तैयारी और दूसरे मुद्दों पर संपादक **सौरभ द्विवेदी** से उनकी बातचीत के मुख्य अंश :

● विधायक रहते हुए पांच साल के दौरान आपने वडगाम में क्या काम करवाए?

इस इलाके में पहले पानी की बहुत समस्या थी. मैं जब चुनाव लड़ने आया था तो लोगों से वादा किया था कि पानी की समस्या हल करूंगा. अब मुझे सुकून है कि नर्मदा केनाल का 190 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है. आने वाले समय में मुक्तेश्वर बांध और कर्मावत तालाब के अलावा 24 और तालाब भरे जाएंगे. वहीं कोरोना संकट के दौरान मेरी एक अपील पर माननीय हाइकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि हर विधायक को 50 लाख रुपए कोरोना बचाव कार्य के लिया खर्च करने हैं. आज वडगाम में गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है. इसके अलावा पिछले पांच साल में जगह-जगह मोर्चा लगाकर हमने पूरे गुजरात में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की भूमि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को दिलवाई है.

रजत सैन

● 2017 में आप हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर के साथ भाजपा को उखाड़ फेंकने की कसमें खाते थे. अब आपके दोनों साथी भाजपा में हैं. ऐसा क्यों?

पाटीदार आंदोलन के वक्त हार्दिक पर 30-35 मुकदमे दर्ज किए गए थे. उनमें से कुछ गंभीर किस्म के थे, जिनमें 10 से 15 साल के कारावास जैसी सजा थी. पता नहीं हार्दिक को यह अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन मुकदमों में सजा करवाने का दबाव बनाकर उसे भाजपा में शामिल करवाया गया. जहां तक अल्पेश का मामला है तो हो सकता है कि उसने खुद को भाजपा की विचारधारा के ज्यादा करीब पाया हो या फिर वह कुछ प्रयोग कर रहा है या उसे वहां ज्यादा अवसर दिखे हों.

● आपका जुड़ाव आम आदमी पार्टी के साथ भी रहा. उनकी तरफ से बुलावा नहीं आया क्या? क्या आपका अरविंद केजरीवाल से कोई साबका हुआ?

पहले एक-दो बार मुलाकात हुई है. उना आंदोलन के वक्त भी बात हुई थी. जब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के लिए गया था तब भी हुई थी. मैंने उनसे कहा कि मैं अभी किसी राजनैतिक पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हूं. इसके अलावा कुछ खास नहीं.

● आपने कांग्रेस में जाने का फैसला क्यों किया?

मेरी राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई उसके बाद मैं तीन बातों को लेकर आश्वस्त था. पहली कि यह आदमी व्यक्तिगत तौर पर या फिर सार्वजानिक मंच से कभी झूठ नहीं बोलेगा. मुझे ऐसा भरोसा इस देश की मुख्यधारा की राजनीति में मौजूद किसी भी

कहने पर लड़ने गया. 1991 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने मेरे खिलाफ प्रचार किया. दूसरी बार कांग्रेस में था. तब मेरे खिलाफ कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के कहने पर कई मुस्लिम निर्दलीय प्रत्याशी उतार दिए गए. इसके चलते मैं बहुत कम वोट से चुनाव हार गया.

● आप शराबबंदी को अव्यवहारिक क्यों मानते हैं?

गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल का गुजरात है. यहां शराबबंदी रही. लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं है. शराब का हजारों करोड़ रुपए का कारोबार है जो गैर-कानूनी तरीके से चल रहा है. आप गुजरात से एक कदम बाहर रखिए आपको शराब मिल जाएगी. इससे राज्य के राजस्व का हजारों करोड़ रुपए का नुक्सान होता है. मैं कहता हूं कि जैसे सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी होती है वैसे ही शराब की बोतल पर लिखी जाए. शराब से आने वाले राजस्व से बच्चों को मुफ्त शिक्षा और जनता को मुफ्त स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा दी जा सकती है. हमारे आदिवासी अंचल में बहुत से लोग देसी शराब बनाते हैं, उनको भी रोजगार मिलने लगेगा.

● क्या आपका राजनैतिक करियर अब खत्म हो गया है?

मैं राजनीति में करियर बनाने नहीं आया था. हिंदू महासभा और जनसंघ से राजनीति की शुरुआत की. उस समय वहां कौन सा करियर था. लेकिन अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा. हालांकि लोगों के बीच अभी भी जा रहा रहा हूं. हाल ही में तीन सभाएं कीं. भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को वोट देने की अपील की. मैं भाजपा के खिलाफ हूं.

● पांच दशक लंबे राजनैतिक जीवन में कोई ऐसा फैसला है जिसका मलाल रहा हो?

कई ऐसे फैसले रहे जिनका मलाल रहा. मैं ज्योतिष में भरोसा नहीं करता, नियति में करता हूं. पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि यह कदम नहीं उठाया होता तो ठीक रहता. जैसे कि मैं हर कार्यकर्ता को कहता हूं कि पार्टी मत छोड़ो, मुख्यधारा की राजनीति से दूर मत होना. लेकिन मैं खुद अलग हो गया. अपनी पार्टी बनाई. जिस काम के लिए दूसरों को रोकता रहा वही खुद किया. ■

नेता से मिलने के बाद नहीं आया. दूसरा, यह आदमी व्यक्तिगत तौर पर आपको या फिर इस मुल्क की जनता को कभी डिच नहीं करेगा. तीसरा, राहुल गांधी सच्चे मायनों में लोकतांत्रिक और उदार आदमी हैं. मेरे लिए कांग्रेस के दायरे में रहते हुए दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों के पक्ष में कुछ भी बोलने की आजादी हमेशा बनी रहेगी.

● राहुल गांधी ने बंद कमरे में क्या वादे किए?

कोई वादा नहीं किया. मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूं जो पद मिलने की शर्त पर पार्टी ज्वाइन करे. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लड़ने वाले आदमी हो, जनता की लड़ाई लड़ो, मेरा तहेदिल से समर्थन रहेगा.

● आपकी राहुल गांधी के साथ करीबी पार्टी के सीनियर नेताओं को असहज नहीं करती?

पार्टी के जितने भी सीनियर नेता हैं उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमारे जैसे युवाओं से वे असहज महसूस नहीं करते हैं. पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने ही मुझे गुजरात में पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है.

● क्या काम होता है वर्किंग प्रेसिडेंट का?

सुरक्षित सीटों के अलावा हमने 40 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं जहां पर दलित वोटर अच्छी तादाद में हैं. मुझे पार्टी की तरफ से इन 40 सीटों पर दलित वोटरों को लामबंद करने का काम दिया गया है. इसके अलावा नॉर्थ गुजरात में पाटन और बनासकांठा जिले की विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है.

● इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?

युवा साथियों को बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा लग सकता है. लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है. पेट्रोल, भाड़ा, किराना सब महंगा हुआ है. इसके अलावा बेरोजगारी, ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी, पेपर लीक, मुंद्रा पोर्ट से दो लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स का पकड़ा जाना भी बड़े मुद्दे हैं.

● गुजरात के गालिब कहे जाने वाले मरीज आपके पसंदीदा शायर हैं. इस इंटरव्यू को उन्हीं के किसी शेर के साथ खत्म करते हैं.

आ एक गुण खुदा नो अमारा जीवन मां छे, वर्तन नथी सामान अमारू बधानी साथे. इसका हिंदी अर्थ है कि खुदा का एक गुण हमारे जीवन में भी है. हमारा भी बर्ताव सब के साथ एक जैसा नहीं है. ■

रजत सैब

'आप नई सोच के साथ मैदान में है'

गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुखिया **गोपाल इटालिया** अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं बन पाए, इस मामले के साथ चुनाव से जुड़े और दूसरे मुद्दों पर संपादक **सौरभ द्विवेदी** की उनसे बातचीत के मुख्य अंश :

● गुजरात में आम आदमी पार्टी को आपने खड़ा किया लेकिन एक सर्वे का हवाला देकर मुख्यमंत्री का चेहरा इसुदान गढ़वी को बना दिया गया. क्या कहेंगे?

पार्टी का फैसला एकदम सही है. इसुदान भाई आज की तारीख में पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. पत्रकार रहते हुए उन्होंने जिस तरह जनता के मुद्दे उठाए, उन्हें जनता भरपूर प्यार मिला. उनके आने से पार्टी बहुत मजबूत हुई. मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर वे सही चुनाव हैं.

● कहा जा रहा है कि इसुदान गढ़वी को मुश्किल सीट मिली है. आपने रणनीति के तहत उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार किया है.

जो जहां से चुनाव जीत सकता है उसे वहां से टिकट दिया गया. यह सबने मिलकर तय किया. इसुदान और मैं पार्टी में वह जगह रखते हैं जिन्हें जबरदस्ती कहीं से चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता. लोग अपने मन से बातें गढ़ लेते हैं. उसका मैं क्या जवाब दूं.

● भाजपा ने चुनाव से एक-सवा साल पहले भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया. इसे किस तरह से देखते हैं.

मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री बदलकर भाजपा ने खुद मान लिया कि गुजरात में उनकी सरकार फेल है. आपने न सिर्फ मुख्यमंत्री बदला, बल्कि सारा मंत्रिमंडल बदल दिया. विजय रुपाणी का इस्तीफा ठीक उस समय हुआ जिस समय उनके बतौर मुख्यमंत्री पांच साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा था. एक तरफ टीवी पर ऐड चल रहा था कि रुपाणी ने गुजरात में इतना काम किया, दूसरी तरफ उनका इस्तीफा हो रहा था. अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो इस्तीफा क्यों लिया.

● गुजरात में केशुभाई पटेल या फिर शंकर सिंह वाघेला ने भी तीसरी ताकत बनने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहे. आम आदमी पार्टी कैसे सफल होगी?

यह कांग्रेस और भाजपा का बनाया हुआ भ्रम है. आप बताइए कि इससे पहले गुजरात में नए विचार और नए चेहरों के साथ तीसरा मोर्चा कब आया? इससे पहले जो भी लोग तीसरी ताकत की तरह आए वे अपनी पार्टी से असंतुष्ट लोग थे. लेकिन आम आदमी पार्टी नई सोच और नए चेहरों के साथ मैदान में उतरी है.

● असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि आपकी पार्टी बिलकिस बानो केस पर चुप्पी साध गई. आपका इस मामले में क्या स्टैंड है?

हमने तो उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं. बलात्कार को किसी भी समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए. यह तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है. बिलकिस बानो केस के आरोपियों को छोड़ना गलत है. उनको सजा मिलनी चाहिए.

● आम आदमी पार्टी का गुजरात को लेकर क्या एजेंडा है?

हम चुनावी वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं. हम गुजरात में दिल्ली की तरह हर बच्चे को अच्छी मुफ्त शिक्षा देंगे. इलाज मुफ्त करेंगे. गुजरात के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे. यह गारंटी हमने गुजरात की जनता को दी है. ■

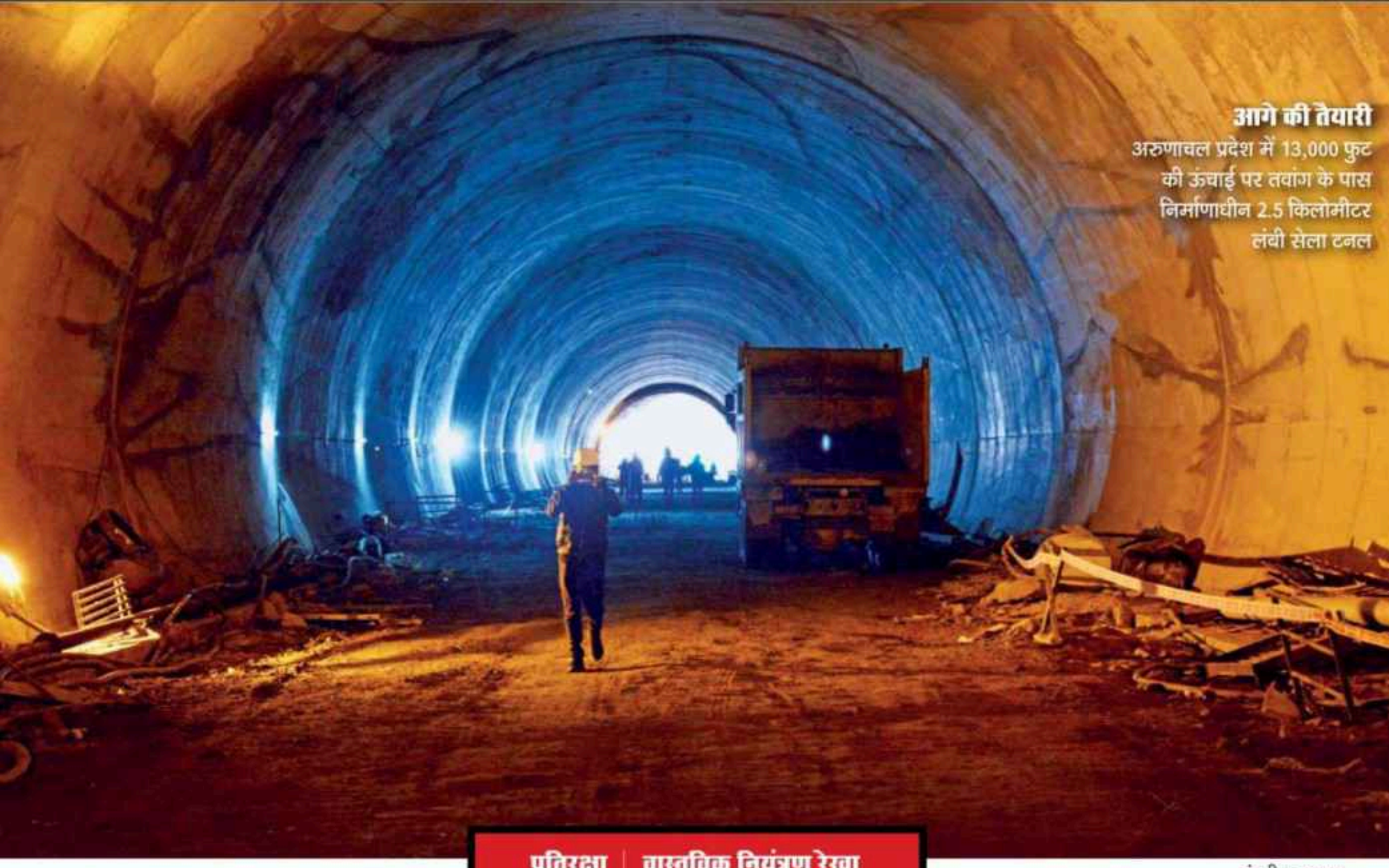

आगे की तैयारी
अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर तवांग के पास निर्माणाधीन 2.5 किलोमीटर लंबी सेला टनल

चंद्रदीप कुमार

सीमा पर बुनियादी ढांचे की किलेबंदी

हिमालय से लगती सीमा पर भारत ने रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफ्तार दोगुनी कर दी है ताकि इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे चीन की बराबरी की जा सके

प्रदीप आर. सागर

अप्रैल 2020 में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जब भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) लंबे समय तक एक-दूसरे के सामने डटे हुए थे, इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि चीनी इसलिए तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे थे, ताकि कम से कम समय में सीमाओं पर भारी संख्या में सैनिकों और साजो-सामान को तैनात कर सकें. एलएसी के साथ पूर्वोत्तर में मैकमोहन रेखा पर चीन की बढ़ती गतिविधि पर भारत की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन 2014 के बाद इसमें तेजी आई, जब एनडीए सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई उपाय किए. इस प्रकार, 2008 से 2014 तक जहां 7,270 मीटर पुलों का निर्माण किया गया था, वहीं 2014 और 2020 के बीच 14,450 मीटर निर्माण पूरा हुआ. इसी तरह, 2008 और 2014 के बीच 3,610 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि 2014 से 2020 के दौरान 4,764 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं. भारतीय सेना का मानना है कि इससे एलएसी के अग्रिम तैनाती क्षेत्रों में संपर्क बेहतर हुआ है और भारतीय सेना गश्त को और अधिक गहन बनाने में सक्षम हुई है. सेना की दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच और गश्त बढ़ने के परिणामस्वरूप ही हाल के वर्षों में पीएलए के साथ लगातार झड़पें हो रही हैं.

उत्तरी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी.एस. हुड्डा कहते हैं, ''एलएसी के भारतीय हिस्से में सड़क निर्माण हमेशा संकट पैदा करता है क्योंकि इससे भारतीय गश्ती दल की पहुंच बढ़ती है. और यह बात हमेशा चीनी सेना को परेशान करती है. ''दरअसल,

मई 2020 में, पीएलए के अचानक आक्रामक होने की बड़ी वजह भारत द्वारा 255 किलोमीटर की ऊंचाई वाली दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (डीएस-डीबीओ) सड़क का निर्माण तेज करना था. यह सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है जो चीन के लिए संवेदनशील है. इस पर गतिरोध अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर चीन के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में और तेजी लाई जा रही है. अतीत से कड़वा सबक सीखने के बाद, सेना का जोर अब चीनियों की टक्कर की सड़कें, आवास, पुल, हेलीपैड और हवाई पट्टी बनाने पर है. चीन भी अपनी उन्नत तैयारियों को और तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना होने से दो दिन पहले, 12 नवंबर को, नई दिल्ली ने अरुणाचल प्रदेश में 1,800 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे के निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की. राष्ट्रीय राजमार्ग 913 नाम वाली यह सड़क मैकमोहन लाइन के साथ-साथ बनेगी जो चीन-भूटान-भारत सीमा ट्राई-जंक्शन को तवांग, ऊपरी सुबनसरी, सियांग, दिबांग घाटी और किबिथू के जरिए विजयनगर से जोड़ेगी. मैकमोहन लाइन पूर्वोत्तर में भारत-चीन की स्वीकृत सीमा है जिसको लेकर चीन को ऐतराज है और विवाद खड़े करता है. सरकार ने कहा कि राजमार्ग सीमाओं को ज्यादा सुरक्षित करेगा, सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन नियंत्रित करेगा और पर्यटन के बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा. इसकी लागत 27,349 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसके पूरा होने में तीन साल लगने की उम्मीद है. सैन्य रूप से, इसका उद्देश्य क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को बेअसर करना और प्रतिक्रिया समय, पहुंच, रसद और पहुंच के मामले में भारतीय सेना को अभूतपूर्व लाभ देना है. इसके अलावा, फ्रंटियर हाईवे सभी नदी घाटियों को जोड़ेगा और सेना की यूनिट्स के लिए एक घाटी से दूसरी घाटी में पहुंचना सुगम बनाएगा.

एक अन्य सड़क भी निर्माणाधीन है, जो हिमाचल प्रदेश में मनाली धुरी से पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी को वैकल्पिक संपर्क प्रदान करेगी. 298 किमी लंबी दो लेन वाली सड़क का दो तिहाई काम पूरा हो चुका है. हिमाचल प्रदेश-लद्दाख मार्ग पर ही सभी मौसमों के लिए अनुकूल 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब शिंकुन ला सुरंग भी रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद पटरी पर है. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डीएस-डीबीओ सड़क, जो काफी ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्रों और सैन्य चौकियों तक पहुंच प्रदान करती है, को 35 'क्लास-70' उन्नत पुल भी मिल रहे हैं. ये स्थाई, अतिरिक्त-चौड़े बेली ब्रिज हैं जो 70 टन का भार सहन कर सकते हैं. इसके 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है. ये भारी टी-90 टैंक और थलसेना के भारी लड़ाकू वाहनों के लिए मुफीद होंगे. सेना ने पहली बार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध के लिए अनुकूल पुल (असॉल्ट ब्रिज) बनाने का सफल परीक्षण किया. असॉल्ट ब्रिज तेज गति से चलने वाले युद्धक वाहनों के लिए अनुकूल मल्टी-स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम वाले पुल होते हैं. इस तरह की परियोजनाओं के साथ, भारतीय सेना ने चीन के साथ सीमा पर अपनी युद्ध की तैयारियों में सुधार किया है, जहां सर्दियां शुरू होने और तापमान के शून्य पर पहुंचने से पहले ही उसे हथियार, गोला-बारूद और भोजन जैसी आवश्यक वस्तुओं को थोक में पहुंचाना पड़ता है. सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, हिमालय की सीमा पर स्थिति 'स्थिर' लेकिन 'अप्रत्याशित' हो जाती है और ऐसे में बढ़त हासिल करने के प्रयास के अलावा बहुत कम विकल्प शेष हैं. सैन्य योजनाकारों का दावा है कि तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास ने भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि की है-उदाहरण के लिए, सेना की कंपनी स्तर की अधिकांश चौकियां अब सड़कों से जुड़ी हुई हैं.

एलएसी पर कई गतिरोधों ने निश्चित रूप से सीमा के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उसे बढ़ाने की तात्कालिकता को बढ़ा दिया है. दिसंबर 2021 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन सड़कों और 24 पुलों का उद्घाटन किया, जो ज्यादातर एलएसी तक तेजी से पहुंच के लिए बनाए गए थे. लद्दाख की चिसुमले-डेमचोक रोड आज वाहन चलने लायक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है. 52 किमी लंबी सड़क 19,000 फीट की ऊंचाई पर उमलिंग ला दर्रे से गुजरती है. यह पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के चिसुमले और डेमचोक को सीधे लेह से जोड़ने के साथ-साथ न्योमा और कारू सैन्य स्टेशनों को भी जोड़ती है. क्षेत्र में नौ नई सुरंगें भी निर्माणाधीन हैं, जिसमें तवांग के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर 2.5 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सेला सुरंग भी शामिल है, जो बनकर तैयार हो जाने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची दो लेन की सुरंग होगी.

चीन सीमा पर काम का बड़ा हिस्सा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एजेंसी है. पिछले पांच वर्षों में, बीआरओ ने 20,767 करोड़ रुपए की कुल लागत से मुख्य रूप से एलएसी के साथ लगे अग्रिम क्षेत्रों तक हर मौसम में पहुंच सक्षम बनाने के लिए 3,595 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है. पिछले सत्र में संसद में एक प्रश्न के जवाब में, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 15,477 करोड़ रुपए की लागत से चीन सीमा के साथ 2,089 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया.

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चार हिंदू पवित्रस्थलों-गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ-को जोड़ने के उद्देश्य से 12,000 करोड़ रुपए की चार धाम राजमार्ग परियोजना भी एलएसी से संपर्क को मजबूत करेगी. रक्षा मंत्रालय एलएसी के लिए प्रस्तावित राजमार्ग पर जोशीमठ, उत्तरकाशी, रुड़की, रजवाला, देहरादून, टनकपुर, पिथौरागढ़ और अन्य स्थानों पर स्थित सेना और भारत-तिब्बत सीमा के पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़क बनाना चाहता है.

वर्षों तक भारत ने चीन सीमा की उपेक्षा की क्योंकि एक खराब रणनीति के तहत माना जाता था कि जर्जर बुनियादी ढांचा "दुश्मनों को हतोत्साहित करने वाला होगा"

22,000 सैनिकों को समायोजित करने के लिए पिछले दो वर्षों में आधुनिक आवास बनाने के अलावा, सेना ने कठोर सर्दी से निबटने के लिए 20 सोलर हीटेड इंसुलेटेड लद्दाखी शेल्टर (शिला) या रहने के लिए गर्म आवास बनाए हैं. इसके अलावा, बख्तरबंद वाहनों और हथियार प्रणालियों को रखने और उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए लगभग 450 तकनीकी भंडार बनाए गए थे.

चीनी बढ़त

एलएसी और पूर्वोत्तर में भारत की अधिकांश निर्माण गतिविधियां तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में चीन के अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों के जवाब में हैं जिसमें 60,000 किलोमीटर से अधिक का व्यापक रेल नेटवर्क और सड़कें शामिल हैं. पिछले साल, चीन ने ल्हासा को न्यिंगची से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन शुरू की. न्यिंगची अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में तूतिंग सेक्टर के सामने स्थित एक शहर है और भारत की सीमा से केवल 40 किलोमीटर दूर है. पीएलए की 52वीं और 53वीं माउंटेन इन्फैंट्री ब्रिगेड बड़े न्यिंगची प्रान्त में स्थित हैं. इसके बाद आगे उत्तर में, 1,600 किलोमीटर लंबी सिचुआन-तिब्बत रेल लाइन तिब्बती पठार पर स्थित ल्हासा को मध्य सिचुआन में चेंगदू से जोड़ेगी. सैन्य पर्यवेक्षकों का दावा है कि तिब्बत में कुल सड़क नेटवर्क 1959 में 7,300 किमी से बढ़कर 2021 में 118,800 किमी हो गया है यानी प्रति दिन औसतन 4.93 किमी का विस्तार हुआ जो हैरत में डालने वाला है.

ड्रैगन की चाल के साथ कदमताल

चीन पहले कदम उठाने की बढ़त के साथ सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है. भारत ने भी पिछले एक दशक में इस मामले में काफी प्रगति की है

आलेख: **प्रदीप आर. सागर** | *इलस्ट्रेशन:* **तन्मय चक्रवर्ती**

सिंधु और श्योक घाटी के बीच हनुथांग-हंदनब्रुक-जुंगपाल-तुरतुक रोड

भारतीय क्षेत्र

न्योमा एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया

दौलत बेग ओल्डी और फुक्चे एयरफील्ड अब चालू हो चुके हैं

चिसुमले-डेमचोक रोड : वाहन चलाने लायक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क

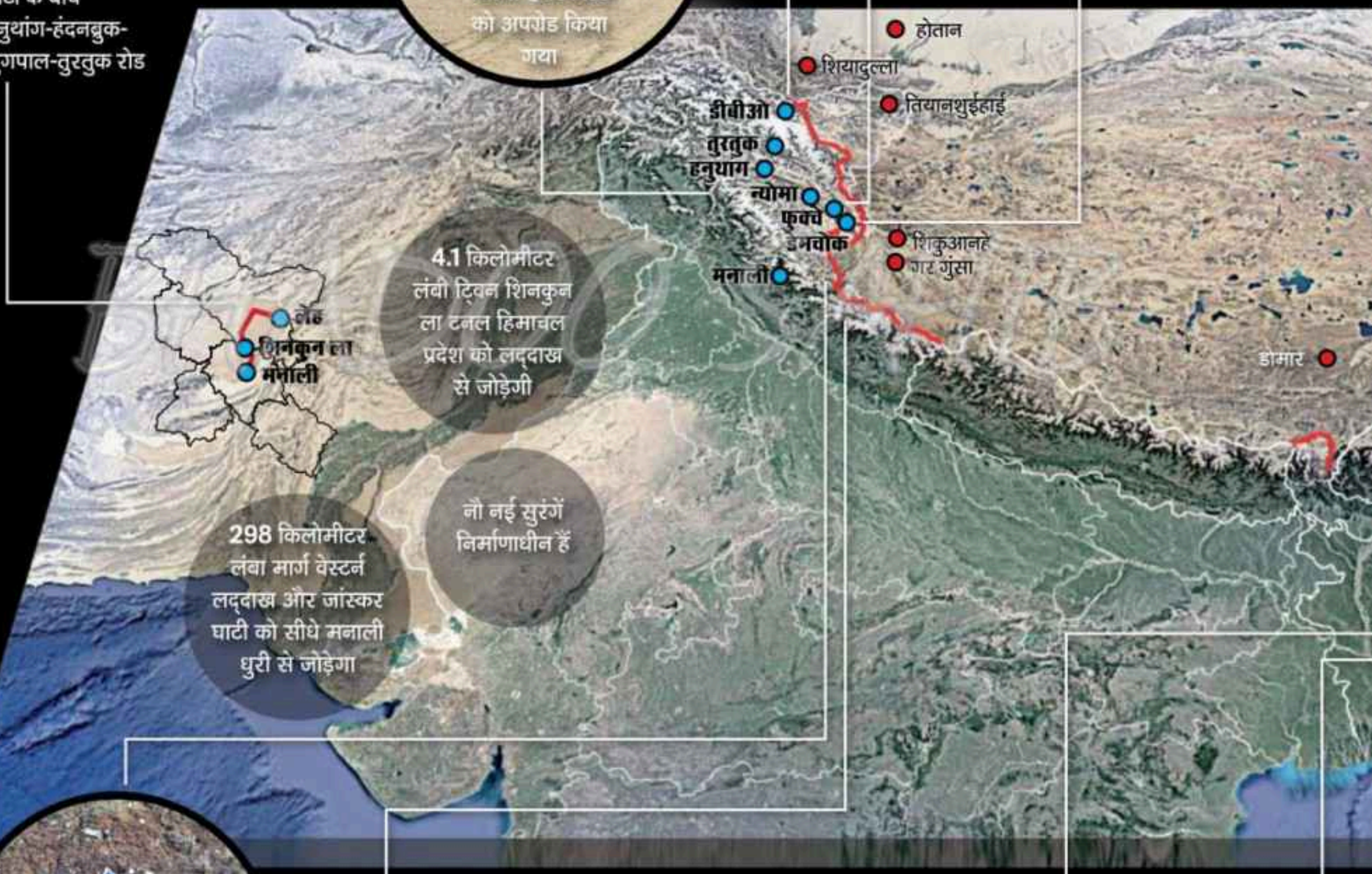

चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीआरओ ने प्राथमिक तौर पर 3,595 किलोमीटर सड़क बनाई है

12,000 करोड़ रुपए की चार धाम परियोजना से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, चारों धाम जुड़ेंगे और ये सड़क एलएसी तक होगी

13,000 फुट की ऊंचाई पर तवांग के पास 2.5 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सेला टनल

चीन-भूटान-भारत के ट्राइ जंक्शन को तवांग के जरिये विजयनगर, अपर सुबंसिरी, सियांग, दिबांग घाटी और किबिथू से जोड़ने के लिए अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाइवे

चीनी क्षेत्र
डीबीओ
डीबीओ रोड
अक्साई चिन
लद्दाख
लेह
श्योक
दुरबुक
पुशुल
चुमार
डेमचोक
शिकुआनहे
चाइना नेशनल हाइवे 219
ल्हासा
न्यिंगची
विजयनगर
तवांग
पीएलए ने चीन के जी-219 से एलएसी की ओर कम से कम आठ सड़कें बनाई हैं. इनमें जी-219 हाइवे को पेंगोंग त्सो लेक के उत्तरी तट पर फिंगर -8 के सीरीजाप से जोड़ने वाली सड़क भी शामिल है
तिब्बत की रुटोग काउंटी को पेंगोंग त्सो के दक्षिण में स्पांग्गुर लेक से जोड़ने वाली सड़क
शिकुआनहे के दक्षिण से लद्दाख में चुमार तक सड़क
कशगर, गार गुंसा और होतान में एयरबेस
शियादुल्ला, त्यानशुईहाई, शिकुआनहे और डोमार क्षेत्रों में हेलीपोर्ट
चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भीतर आकर कम से कम 60 बिल्डिंगों का एक क्लस्टर तैयार किया है
पीएलए की 52वीं और 53वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड बड़े न्यिंगची प्रांत में स्थित हैं. 1,600 किलोमीटर लंबी सिचुआन -तिब्बत रेल लाइन तिब्बत के पठार पर ल्हासा को सेंट्रल सिचुआन के चेंगदू से जोड़ेगी
चीनी बुलेट ट्रेन ल्हासा को न्यिंगची से जोड़ती है, जो कि अरुणाचल के सीमावर्ती शहर मेचुखा के ठीक सामने है

पीएलए ने चीन के जी-219 हाइवे से एलएसी की ओर कम से कम आठ सड़कें बनाई हैं, जिनमें से एक इसे पैंगोंग त्सो झील पर फिंगर 8 पर सिरिजाप से जोड़ती है. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की ओर से बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने के उसके इरादे का संकेत है. उनकी राय है कि सीमा पर तनाव और तैनाती घटाने की प्रक्रिया की अपनी सीमाएं हैं, खासकर तब जब चीन के रवैये में कोई खास बदलाव न दिखा हो. यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड के जनरल चार्ल्स ए. फ्लिन ने इस साल जून में अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान कहा कि ''वेस्टर्न थिएटर कमान में बनाए जा रहे कुछ बुनियादी ढांचे मुश्किल खड़ी कर सकते हैं.'' लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं कि अब जबकि सेना और केंद्र को चीन की गतिविधियों और मंशा का सही आभास है, तो सड़कों, हवाई क्षेत्रों और हेलीपैडों को विकसित करने के लिए बहुत तेज गति से धन आवंटित किया जा रहा है. वे कहते हैं, ''हम एलएसी पर बुनियादी ढांचे के विकास में हमेशा पिछड़ते गए हैं, इसलिए कम से कम अब कुछ खाइयां भरी जा रही हैं. हमारी कमजोरियों को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है.''

अतीत के त्रुटिपूर्ण रणनीतिक निर्णय भी भारतीय बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति के लिए जिम्मेदार हैं. वर्षों तक, भारतीय नीति निर्माताओं ने चीन की सीमा की उपेक्षा की क्योंकि उनकी खराब रणनीति यह मानकर चलती थी कि भारत के हिस्से में अगर सीमा पर बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं होगा तो इससे ''दुश्मन हतोत्साहित होगा.'' इस प्रकार, सड़क संपर्क की जानबूझकर उपेक्षा की गई थी. पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इसे एक ''गलत दृष्टिकोण'' माना था और बुनियादी ढांचे के निर्माण/उन्नयन के लिए ''सरकारी नीति में बदलाव'' की घोषणा की थी. हालांकि, इसमें वास्तविक तेजी मोदी सरकार के दौर में आई. बीआरओ के बजट में लगातार वृद्धि हुई. 2008 से 2016 तक यह बजट 3,300 करोड़ से 4,600 करोड़ रुपए के बीच ही रहा, लेकिन 2018-19 के बजट में 8,050 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. 2022-23 के बजट में बीआरओ के लिए पूंजीगत परिव्यय बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए किया गया था.

वरिष्ठ सैन्य विश्लेषक मेजर जनरल शशि अस्थाना (सेवानिवृत्त) बताते हैं कि एलएसी के इस तरफ पहाड़ियां और घाटियां आपस में जुड़ी नहीं हैं, जिससे आवाजाही और निर्माण में कठिनाई होती है. अस्थाना कहते हैं, ''भूभाग बेहतर होने से चीनी सेना हमसे आगे निकल गई. बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब भी उनकी गति ज्यादा है. हम बुनियादी ढांचे में चीनी सेना के बराबर नहीं हैं.''
भारत के उलट, चीनी सीमा रक्षा कानून ढांचा विकसित करने वाली एजेंसियों को खुला हाथ देता है. भारत में काम शुरू करने से पहले पर्यावरण आदि से जुड़ी मंजूरी जरूरी है.

सीमावर्ती क्षेत्रों में 624 गांवों के निर्माण की चीन की योजना का मुकाबला करने के लिए, भारत ने एलएसी से सटे इलाकों में 'वाइब्रेंट विलेज' की योजना तैयार की है. इसके तहत, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामरिक संपत्ति माना जाएगा और यह कार्यक्रम उन्हें शहरों के निकट स्थित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने से रोकेगा. बहरहाल, भारतीय सेना झूठ बोलने वाले इस अति-सक्रिय दुश्मन की बराबरी में खड़े होने के लिए, धीमी गति से सही लेकिन सधे कदम रख रही है. उम्मीद है, जल्द ही हम दुश्मन की बराबरी पर होंगे. ■

बिहार | वायु प्रदूषण

ये धुआं कहां से उठता है

बीते नवंबर में बिहार के कई जिले और छोटे शहर वायु प्रदूषण के बड़े हॉट स्पॉट बनकर उभरे. रोजाना जारी होने वाली देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में ज्यादातर नाम इसी राज्य के नजर आते हैं. उद्योगीकरण और पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की उपलब्धता में निचले पायदानों पर खड़े बिहार में आखिर इस गंभीर वायु प्रदूषण की वजह क्या है

पुष्यमित्र

सीवान बिहार का एक मझोले आकार का कस्बेनुमा शहर है. यह जिला देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है. हाल तक इस शहर की पहचान यहां के दबंग राजनेता मोहम्मद शहाबुद्दीन और यहां से खाड़ी देशों में जाकर काम करने वाले कुशल मजदूरों की वजह से रही है. मगर पिछले दिनों से इस शहर का नाम बार-बार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रोजाना के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआइ की सूची में सबसे ऊपर के शहरों में नजर आ रहा है.

330, 366, 401, 000 (अनुपलब्ध), 402, 385, 400, 401, 384, 432. ये पिछले दस दिनों (18-27 नवबंर, 2022) के सीवान शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़े हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों को देखा जाए तो इनमें से पांच दिन सीवान शहर की आबोहवा सीवियर यानी काफी गंभीर रही है और चार दिन बहुत खराब, एक दिन का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. ये आंकड़े तकरीबन वैसे ही हैं, जिनके आधार पर देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, ट्रकों की आवाजाही रोक दी जाती है, सभी निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑड-इवन स्कीम लागू कर दी जाती है. मगर सीवान शहर में स्थानीय प्रशासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है.

मुश्किल में सांस
पटना के आइजीआइएमएस अस्पताल परिसर के आसपास वायु प्रदूषण के चलते छाई धुंध

सभी फोटोः पुष्यमित्र

बिहार के छह शहरों का 29 नवंबर, 2022 का एक्यूआइ

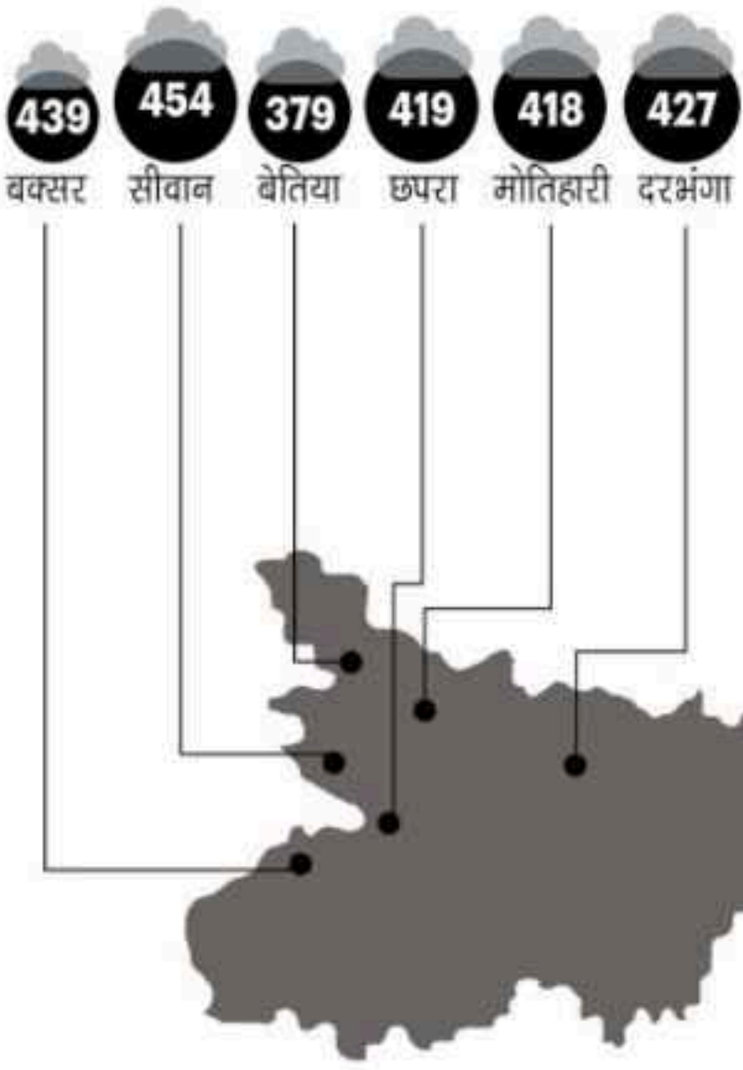

उत्तर भारत के प्रमुख शहरों का एक्यूआइ

आगरा	172
दिल्ली	369
कानपुर	215
लखनऊ	264
वाराणसी	216
लुधियाना	203

स्रोतः राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ये हालात सिर्फ सीवान शहर के नहीं हैं. बिहार में आठ शहर ऐसे हैं, जिनकी आबोहवा पिछले दस दिनों में गंभीर स्थिति में पहुंच गई है. बेतिया और मोतिहारी शहर का एक्यूआइ चार दफा 400 के पार चला गया है. पूर्णिया शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन और बेगूसराय-दरभंगा का दो और कटिहार-बक्सर का एक-एक दिन 400 की खतरनाक सीमा को लांघ चुका है. इतना ही नहीं, इन दस दिनों में कम से कम छह दफा ऐसा हुआ है जब देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में दस के दस बिहार के ही शहर रहे हैं. बाकी बचे चार दिनों में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. इनमें भी दस में से नौ शहर बिहार के नजर आते हैं. इन दस दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब सबसे प्रदूषित शीर्ष सात शहरों में बिहार के अलावा किसी और राज्य के शहर का नाम हो.

इस साल की सर्दियों में बिहार से आ रहे वायु प्रदूषण के इन चौकाने वाले आंकड़ों को देखकर ज्यादातर विशेषज्ञ हैरत में हैं. दरअसल बिहार के किसी शहर में न तो ऐसे उद्योग लगे हैं, जिनकी चिमनियों का धुआं यहां की आबोहवा खराब कर सके और न ही यहां इतनी गाड़ियां चलती हैं, जिनसे प्रदूषण फैले. बिहार में इस वक्त सिर्फ 3,420 रजिस्टर्ड औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं और इनमें बहुत कम ही ऐसी हैं जिनसे प्रदूषण फैलता हो. राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन भी बहुत अधिक नहीं हैं. प्रति एक हजार की आबादी पर बिहार में ऐसे वाहनों की संख्या सिर्फ 31 है, जो देश में सबसे कम है. मसलन, चंडीगढ़ में यह संख्या 702 है, जबकि देश के 24 राज्यों में प्रति एक हजार की आबादी पर वाहनों की औसत संख्या एक सौ से अधिक है.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में राजधानी पटना या कोई दूसरा औद्योगिक शहर नहीं दिखता. इनमें से ज्यादातर अर्धविकसित कस्बे हैं. इन्हें शहर कहे जाने की एक ही वजह है कि ये अपने जिलों के मुख्यालय हैं, जहां कुछ सरकारी दफ्तर संचालित होते हैं. इन शहरों का देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नाम कैसे आ गया है, इसका सटीक कारण कोई नहीं बता पा रहा.

सीवान के सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार सिंह कहते हैं, ''हमारे लिए भी यह चौंकाने वाली सूचना है कि सीवान का नाम देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कैसे आ गया. अगर वाकई ऐसा है तो इसकी दो वजहें लगती हैं. एक तो शहर में पुरानी और आउटडेटेड गाड़ियां खूब धड़ल्ले से चलती हैं. अगर किसी चौराहे पर जाम में फंस जाएं, तो पांच मिनट में दम घुटने की नौबत आ जाती है. दूसरी वजह, यह धान की तैयारी का मौसम है और किसान जमकर थ्रेशर चलाते हैं. उससे निकलने वाले फसल अवशिष्ट के कण ठंड की वजह से ऊपर नहीं जाते. उनसे भी शायद यहां की हवा जहरीली बन रही है.''

पर्यावरण के मसले पर काम करने वाली संस्था सीड की बिहार प्रतिनिधि अंकिता ज्योति के मुताबिक, ''दरअसल इन शहरों के नाम पहली दफा देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आ रहे हैं, इसलिए सबको हैरत हो रही है. ये शहर पहले भी प्रदूषित रहे होंगे, मगर पहले यहां प्रदूषण जांच केंद्र नहीं हुआ करते थे. पिछले साल पहली दफा ये केंद्र स्थापित हुए हैं और इस साल आंकड़े आ रहे हैं और नए आंकड़े लोगों को हैरत में डाल रहे हैं.''

दरअसल 2021 से पहले बिहार में सिर्फ तीन शहरों में ही प्रदूषण जांच केंद्र थे. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष बताते हैं, ''हम लोगों को यह अंदाजा पहले से था कि राज्य के दूसरे इलाके भी प्रदूषित होंगे. इसलिए बोर्ड ने राज्य

के 22 नए शहरों में पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित कराए. अब राज्य के 25 जिलों में कुल 35 केंद्र आंकड़े दे रहे हैं. मार्च, 2022 से इन केंद्रों से आंकड़े आने शुरू हुए हैं और यह ठंड का पहला मौसम है, जब यहां से प्रदूषण के असली आंकड़े आ रहे हैं.''

हालांकि घोष इन आंकड़ों से बहुत परेशान नहीं दिखते. वे कहते हैं, ''कम से कम सच्चाई तो हमारे सामने आ रही है. अब जब यहां के आंकड़े आ रहे हैं तो हमें प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी आसानी होगी.''

इन इलाकों में प्रदूषण की भारी मात्रा पर बात करते हुए अशोक घोष कहते हैं, ''इसकी दो वजहें हैं. पहली, यह इलाका एल्यूवियल प्लेन का क्षेत्र है. यहां खेती या निर्माण की किसी भी गतिविधि से धूल उड़ती ही है. दूसरी, उज्ज्वला योजना के बावजूद इस इलाके में लोग खाना पकाने के लिए आज भी सूखे जलावन का इस्तेमाल करते हैं. ठंड में पुआल जलाते हैं. कुल मिलाकर बायोमास बर्निंग खूब होती है. इसलिए उत्तर बिहार के इलाके का एक्यूआई लेवल अधिक होना स्वभाविक है.''

यह पूछे जाने पर कि क्या इस इलाके में पराली भी जलाई जाती है, वे इस बात से इनकार करते हैं. घोष कहते हैं, ''पराली तो बिहार में उतनी नहीं जलाई जाती कि इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाए. मगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में खूब पराली जलाई जाती है. उस पराली का धुआं पछुआ हवा के साथ बिहार के सीवान, बेतिया और मोतिहारी जैसे शहरों में बह कर आता है और इन शहरों को प्रदूषित करता है.''

आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहार में पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम होती हैं. सात नवंबर से 22 नवंबर के बीच राज्य में पराली जलाने की सिर्फ 503 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि पंजाब जैसे राज्यों में ऐसे 50 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए हैं.

वैसे तो राज्य के इन नए शहरों में प्रदूषण के कारणों का अब तक कोई सिलसिलेवार अध्ययन नहीं हुआ है, क्योंकि इन शहरों के नाम अभी तक नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान में नहीं आए हैं. देश के कुल 132 शहरों में इस वक्त नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत काम चल रहा है. इसमें बिहार के सिर्फ तीन शहर पटना, गया और मुजफ्फरपुर ही शामिल हैं, क्योंकि पिछले साल तक सिर्फ इन तीन शहरों में भी प्रदूषण जांच केंद्र संचालित हो रहे थे और आंकड़े सामने आ रहे थे.

2018 में प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए राज्य के तीन शहरों पटना, गया और मुजफ्फरपुर में अध्ययन कराया गया, तो पता चला कि यहां सबसे अधिक प्रदूषण बाहरी कारणों से हो रहा है. राज्य की प्रदूषित हवा में दो तत्व सबसे अधिक पाए जा रहे हैं. पहला पीएम10 और दूसरा पीएम 2.5. इस अध्ययन के मुताबिक प्रदूषण में पीएम 2.5 तत्व की सबसे अधिक 22 फीसद भागीदारी घरेलू चूल्हों की वजह से है. 19 फीसद गाड़ियों की वजह से, 15 फीसद धूल की वजह से, 14 फीसद उद्योगों की वजह से, 14 फीसद ईंट भट्ठों के कारण, 11 फीसद कचरा जलाने के कारण और 5 फीसद जेनसेट की वजह से.

''इन आंकड़ों से बिहार में प्रदूषण की सच्चाई सामने आई है. यह अच्छा ही है क्योंकि अब इस आधार पर आगे प्रदूषण को नियंत्रित करने में आसानी होगी''

अशोक घोष

अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

18 से 27 नवंबर, 2022 के बीच बिहार में प्रदूषण की स्थिति

- छह दिन देश के शीर्ष दस प्रदूषित शहरों में दस के दस शहर बिहार के. शेष चार दिन राज्य के नौ शहर
- सभी दस दिनों में एक से सात नंबर पर बिहार के शहर
- दस में से नौ दिन तक रोजाना कम से कम दो शहरों का प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया. एक दिन चार शहरों का, दो दिन तीन शहरों का
- इस अवधि में कम से कम आठ शहरों का एक्यूआइ चार सौ के पार चला गया

जहां तक पीएम10 का सवाल है, इसकी सबसे बड़ी वजह (27 फीसद योगदान) निर्माण उद्योग से उठती धूल है और (23 फीसद योगदान) फीसदी सड़कों की धूल. यानी लगभग आधा प्रदूषण निर्माण उद्योग और सड़कों की वजह से हो रहा है.

हाल के वर्षों में राज्य में बड़े पैमाने पर निर्माण की गतिविधियां बढ़ी हैं. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इस वक्त राज्य में सिर्फ सड़कें और पुल-पुलिया बनाने की एक लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं संचालित हो रही हैं. इसके अलावा भवन निर्माण की सरकारी और निजी परियोजनाएं भी कम नहीं हैं. छोटे शहरों में इन परियोजनाओं में मानकों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता. इस वजह से यह उठती धूल हवा को प्रदूषित कर रही है.

पूर्णिया में सामाजिक मसलों पर सक्रिय विकास आदित्य कहते हैं, ''एक तो पूर्णिया और कटिहार के बीच बन रही सड़क से वहां के आसपास के लोगों का जीना मुहाल है. वहीं इन दिनों अतिक्रमण मुक्ति अभियान की वजह से भी शहर में इमारतों की तोड़-फोड़ हो रही है. इन दो वजहों से पूर्णिया शहर की हवा में जहां जाइए, धूल ही दिखती है.'' हालांकि राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस वजह को स्वीकार करने में हिचकता नजर आता है. वजह जो भी हो, मगर सच्चाई यही है कि बिहार के ज्यादातर इलाके इस वक्त भीषण प्रदूषण की चपेट में हैं.

इतने प्रदूषण के बावजूद राज्य में कहीं भी इससे बचाव के उपाय लागू होते नजर नहीं आते. बिहार के तीन शहरों पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया है. इसके मुताबिक 300 से अधिक एक्यूआई होने पर शहर में ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी, डीजल जेनसेट का प्रयोग बंद कराया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. एक्यूआई 400 के पार जाने पर ऑड ऐंड इवन स्कीम लागू होगी. 450 के पार जाने पर हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करते हुए स्कूल बंद किए जाएंगे. पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे सभी जिलों में लागू करें, मगर ये निर्देश कहीं लागू होते नजर नहीं आ रहे. ■

योगेंद्र प्रताप

सुरक्षा सबसे पहले

खरीदार अब सुरक्षा फीचर पर जितना ध्यान दे रहे हैं उतना पहले कभी नहीं दिया. सीट बेल्ट से लेकर क्रैश टेस्ट तक यहां वह सब है जिसकी पड़ताल आपको करनी चाहिए

हर महीने भारत भर से मुझे सैकड़ों लोगों के सवाल मिलते हैं कि उन्हें किस तरह की कार खरीदनी चाहिए. इनमें वे भी होते हैं जो सस्ती एंट्री लेवल की कारों के बारे में जानना चाहते हैं और वे भी जिनके लिए कीमत मायने नहीं रखती. बीते सालों में मैंने कई रुझान उभरते देखे. चाहे वह एक निश्चित बॉडी स्टाइल की तरफ झुकाव हो या कुछ निश्चित फीचर की चाह, मुझे पता है कि लोगों की दिलचस्पी किसमें है और वे क्या खरीदेंगे. बीते छह महीनों सें एक तो इलेक्ट्रिक कारों के बारे में पूछा जा रहा है और दूसरे यह कि अमुक कार कितनी सुरक्षित है. सुरक्षा फीचर कई साल से ग्राहकों के दिमाग में हैं, पर खरीद के असल फैसले का सुरक्षा चिंताओं से कोई लेना-देना नहीं होता था. यह अब बदलने लगा है. ज्यादा लोग सुरक्षा फीचर और रेटिंग से अधिकाधिक प्रभावित होकर खरीद का अंतिम फैसला ले रहे हैं. अलबत्ता कई लोग अब भी उलझन में होते हैं कि सुरक्षित कार क्या होती है और कैसे फैसला करें कि कौन-सी कार सुरक्षित है. यहां कुछ बातें हैं जिनकी पड़ताल करने से आपको ज्यादा सुरक्षित कार चुनने में मदद मिलेगी.

सबसे पहले, कार कितनी भी सुरक्षित हो या न हो, अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधते तो अपनी जिंदगी को सुरक्षा खूबियों से महफूज बनाने के बजाए उसे किस्मत के हाथों में सौंप देते हैं. यह बात केवल आगे की ही नहीं बल्कि कार की हर सीट के लिए है. दरअसल, पिछली सीट की सवारियां अगर सीट बेल्ट न बांधे हों तो वे आगे की सीट पर बैठी सवारियों को भी चोट पहुंचा सकती हैं (जो जानलेवा हो सकती हैं), फिर भले ही आगे की सीट की सवारियों ने सीट बेल्ट बांधी हो.

कई एजेंसियां कारों का क्रैश टेस्ट करती हैं, यानी नियंत्रित परिस्थितियों में नई कार की जानी-बूझी टक्कर करवाकर उनका मूल्यांकन करती हैं, और उन्हें रेटिंग देती हैं. इनमें ग्लोबल एनसीएपी भी है, जो अपने #SaferCarsForIndia अभियान के तहत भारत में बनी कारों की जांच करती है. इन कार्यक्रमों के तहत हर कार को वयस्कों और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिहाज से (कुछ में पैदल

हादसे से हिफाजत

1: एयरबैग सीट बेल्ट के पूरक हैं 2: सीट बेल्ट रोकथाम प्रणाली के प्राथमिक उपकरण हैं 3-4: महिंद्रा एक्सयूवी700 और स्कोडा कुशाक दोनों को फाइव स्टार रेटिंग मिली है

यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी) फाइव स्टार के पैमाने पर आंका जाता है. उनकी वेबसाइटों पर उन्हें मिले वास्तविक अंक होते हैं जो आपको समान स्टार रेटिंग वाली कारों में से चुनने में मदद कर सकते हैं. मसलन, ग्लोबल एनसीएपी ने हाल में ज्यादा कठोर व्यवस्था अपनाई है, इसलिए पहले की रेटिंग की तुलना इस साल बाद में की गई और भविष्य में की जाने वाली रेटिंग से नहीं की जा सकती. नई कारों के दूसरे आकलन कार्यक्रमों की रेटिंग भारत के समान मॉडलों पर लागू हो भी सकती हैं और नहीं भी.

मैंने पहले भी कहा है कि एयरबैग होना अच्छा है पर सुरक्षा के लिए अनिवार्य नहीं है. इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि कुछ कारों को केवल दो एयरबैग के साथ फाइव स्टार रेटिंग मिल जाती है, जबकि छह एयरबैग वाली कारों को बाज दफे तीन स्टार ही मिले. दूसरे ज्यादा जरूरी सुरक्षा कारक भी हैं और उनमें से एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है. अगर कार का आकलन किया गया है तो उसकी रेटिंग शीट पर इस बारे में टिप्पणी होगी. आखिर में, एडीएएस फीचर सड़कों को ज्यादा महफूज बनाते हैं और एबीएस तथा ईएसपी सरीखी सक्रिय सुरक्षा प्रणालियां दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती हैं. अच्छा तो यही है कि आपकी कार में वे हों, क्योंकि ये दुर्घटना होने की स्थिति में आपका महफूज रहना पक्का करने के बजाय दुर्घटना को रोकते हैं. अगर आपको जरा अंदाज नहीं है कि कार कितनी सुरक्षित है, तो इतना तो जरूर पक्का करें कि हर कोई सीट बेल्ट बांधे, क्योंकि इससे जिंदगी की रक्षा होगी, चोटों की गंभीरता कम होगी और लोगों को दुर्घटनाग्रस्त कार से एकदम सकुशल बाहर निकल आने में मदद मिलेगी. ■

JK TYRE
TOTAL CONTROL

THE FUTURE OF DRIVING IS HERE.

SMART TYRE

TYRE WITH A BRAIN

JK Tyre presents the future of driving, SMART TYRE – THE TYRE WITH A BRAIN. With inbuilt smart sensors and cutting-edge tech, Smart Tyre gives you real-time safety alerts and makes your journeys safer and smarter.

Smart Features

Detect Air Leaks

Monitor Tyre Pressure

Monitor Tyre Temperature

Bluetooth Connectivity

Creative Visualization

Scan the QR code to know more.

www.jktyre.com/SMARTTYRE | Follow us on:

/JKTyre | /jktyrecorporate

YouTube /jktyrecorporate | /jktyrecorporate

तेज रफ्तार के लिए

ये नई कारें खरीदारों को सड़क पर रोमांचक और सुखद अनुभव देती हैं

महिंद्रा एक्सयूवी300 टर्बोस्पोर्ट

महिंद्रा ने एक्सयूवी300 टर्बोस्पोर्ट को अधिक शक्तिशाली 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया है जो 130 बीएचपी और 230 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और 6-स्पीड मैनुअल शिफ्टर के साथ आता है. इस मोटर में एक डायरेक्ट इंजेक्शन फ्यूल सिस्टम है जो इसे 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल की तुलना में अतिरिक्त 20 बीएचपी देता है, जो 5 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने के लिए पर्याप्त है. इस वैरिएंट के लॉन्च के साथ ही महिंद्रा एक्सयूवी300 सब-4 एम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे शक्तिशाली पेशकश बन गई है. इस सेगमेंट में वेन्यू, सॉनेट, नेक्सॉन और ब्रेजा शामिल हैं.

प्रवेग डेफी

बेंगलूरु आधारित ऑटोमोटिव स्टार्ट-अप प्रवेग ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी डेफी नाम से पेश की है. इसके बाहरी हिस्से में तेज कोणीय रेखाएं हैं जो रेंज रोवर की याद दिलाती हैं और अंदरूनी डिजाइन का अभी खुलासा नहीं किया गया है. इसमें एक डुएल-मोटर सेट-अप ऑल-व्हील ड्राइव की क्षमता में सक्षम बनाता है. प्रवेग अपनी 90.9 किलोवाट प्रति घंटे की बैटरी पैक के साथ एक बार चार्ज होने के बाद 500 किमी की रेंज का दावा कर रहा है. इसकी बुकिंग 51,000 रुपये में आरंभ हो गई है जिसकी डिलीवरी 2023 की तीसरी तिमाही से शुरू होगी.

इंजन
डुएल इलेक्ट्रिक मोटर
पावर
402 बीएचपी
कीमत
39.50 लाख रु.
(एक्स-शोरूम)

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

ग्रैंड विटारा के साथ विकसित अर्बन क्रूजर हाइराइडर मारुति सुजुकी की अपने जुड़वां संस्करण तरह सुविधाओं और पावरट्रेन विकल्पों के साथ आ रही है. लेकिन थोड़ा अलग लुक और टेल लैंप का एक अलग सेट इसे उससे अलहदा करता है. यह भी 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रांग हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन के साथ आता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प के साथ-साथ एडब्ल्यूडी वेरिएंट भी उपलब्ध है.

इंजन
1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड
पावर
103 बीएचपी/ 103 बीएचपी
कीमत
10.48-18.99 लाख रु.
(एक्स-शोरूम)

इंजन
इलेक्ट्रिक मोटर
पावर
61 बीएचपी/ 75 बीएचपी
कीमत
8.49-11.79 लाख रु.
(एक्स-शोरूम)

टाटा टियागो ईवी

टियागो ईवी भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है, जिसकी कीमत 8.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. देखने में यह ईवी बाहर और अंदर जोड़ी गई खूबियों को छोड़कर अपने पेट्रोल समकक्ष की तरह ही डिजाइन को बरकरार रखे हुए है. टाटा टियागो ईवी को दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ आ रही है. 19.2 केडब्ल्यूएच वैरिएंट में दावा की गई रेंज 250 किमी है, जबकि 24 केडब्ल्यूएच वैरिएंट में यह रेंज 315 किमी है. इसमें एपलकारप्ले और 7-इंच टचस्क्रीन के माध्यम से एंड्राएड ऑटो कनेक्टिविटी, ऑटो एयरकॉन, क्रूजर कंट्रोल और कई रीजेन मोड समेत कई फीचर्स शामिल हैं.

इंजन:
2.0 लीटर डीजल
पावर:
177 बीएचपी
कीमत:
36.67 लाख रु.
(एक्स-शोरूम)

सिट्रन सी5 एयरक्रॉस

अपडेटेड सी5 एयरक्रॉस एसयूवी नए हेडलैंप, रिवाइज्ड टेल लैंप और बंपर सहित नए बाहरी हिस्से के साथ आ रही है. गियर बदलने के लिए टॉगल (एक तरह की बटन) के साथ 10 इंच की बड़ी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन के साथ एक रिवाइज्ड सेंटर कंसोल है, जिससे इंटीरियर में महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है. यह फाइव-सीटर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़े गए 2-लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित सिंगल ट्रिम में उपलब्ध है. इसके प्रतिद्वंद्वियों में हुंडई ट्यूसॉन और जीप कंपास शामिल हैं.

वोल्वो एक्ससी40

वॉल्वो ने अपनी एंट्री-लेवल एसयूवी को बदले हुए हेडलैंप्स, बंपर और इंटीरियर के साथ अपगेड किया है. दो नए रंगों–फियोर्ड ब्लू और सेज ग्रीन–में पेश की गई एसयूवी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए अपडेटेड एंड्राएड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसकी खूबियों में एपलकारप्ले, 14-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, पायलट असिस्ट, लेन-कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट शामिल हैं. एक नया 2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो 48वी इंटीग्रेटेड स्टार्टर-जनरेटर से जुड़ा है, जिससे पुराने इंजन के मुकाबले 7 बीएचपी ज्यादा ताकत पैदा होती है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर आगे के पहियों को पावर देता है.

बीएमडब्ल्यू एम5 50 याहर एम एडिशन

बीएमडब्ल्यू ने भारत में एम ब्रांड के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक्सक्लूसिव एम5 कॉम्पीटिशन 50 याहर एम एडिशन पेश किया है. जर्मन भाषा में वर्ष को याहर कहा जाता है. एवेंचुरीन रेड में रंगे इस विशेष संस्करण के आगे 50 याहर एम एम्ब्लम लगा है. कंफर्ट एक्सेस सिस्टम और सॉफ्ट क्लोज डोर को स्टैंडर्ड के रूप में पेश किया जाता है, जबकि बाकी खूबियों की सूची काफी हद तक नियमित एम5 कॉम्पीटिशन के समान है. इसके 625 बीएचपी टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल वी8 के साथ प्रदर्शन आश्चर्यजनक है, जो इसे केवल 3.3 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम बनाता है. बीएमडब्ल्यू इंडिया ने भारत में दस 50 याहर एम एडिशन कारों को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिनमें से आठ अब बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

जावा 42 बॉबर

जावा की नवीनतम पेशकश इसके बेस्टसेलिंग 42 मॉडल पर आधारित है और यह उसी आकार में आ रहा है जिसे हमने इस ब्रांड के पेराक के मामले में देखा है. यह सर्वोत्कृष्ट बॉबर लुक देता है और तीन रंगों में उपलब्ध है. इसमें एलईडी हेडलैंप और टेल लैंप हैं. इस मोटरसाइकिल में डुअल-चैनल एबीएस के साथ दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक हैं. इसमें पेराक की तरह 334 सीसी इंजन है, लेकिन इसकी कीमत काफी कम है.

इंजन
334 सीसी
पावर
30.6 बीएचपी
कीमत
2.07-2.09 लाख रु.
(एक्स-शोरूम)

नई पेशकश / बाइक

धूम मचाते दुपहिये

जावा और रॉयल एनफील्ड के नए मॉडलों के अलावा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेश किया गया है

रॉयल एनफील्ड हंटर

हंटर 350 को रेट्रो और मेट्रो वैरिएंट में पेश किया गया है, मेट्रो को डैपर और रिबेल शृंखला में विभाजित किया गया. विभिन्न डिजाइन एलीमेंट और रंगों के साथ, खरीदारों को 23 विभिन्न संयोजनों में से बाइक चुनने का मौका मिलता है. मेट्रो में डुअल-चैनल एबीएस के साथ डुअल-डिस्क ब्रेक हैं जबकि रेट्रो रियर में ड्रम ब्रेक और सिंगल-चैनल एबीएस हैं.

इंजन
349 सीसी
पावर
20.2 बीएचपी
कीमत:
1.50-1.69 लाख रु.
(एक्स-शोरूम)

ओला एस1 एयर

पारंपरिक टेलीस्कोपिक फ्रंट और ट्विन स्प्रिंग रियर सस्पेंशन के साथ ओला के एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर एस1 एयर में दोनों पहियों के लिए ड्रम ब्रेक का उपयोग किया गया है. यह 90 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है. 4.5 केडब्ल्यू मोटर 2.5 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक से ताकत हासिल करती है, जो एस1 एयर को ईको मोड में 101 किमी की सिंगल-चार्ज आइडीसी रेंज देती है और इसे होम चार्जर से 4.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है.

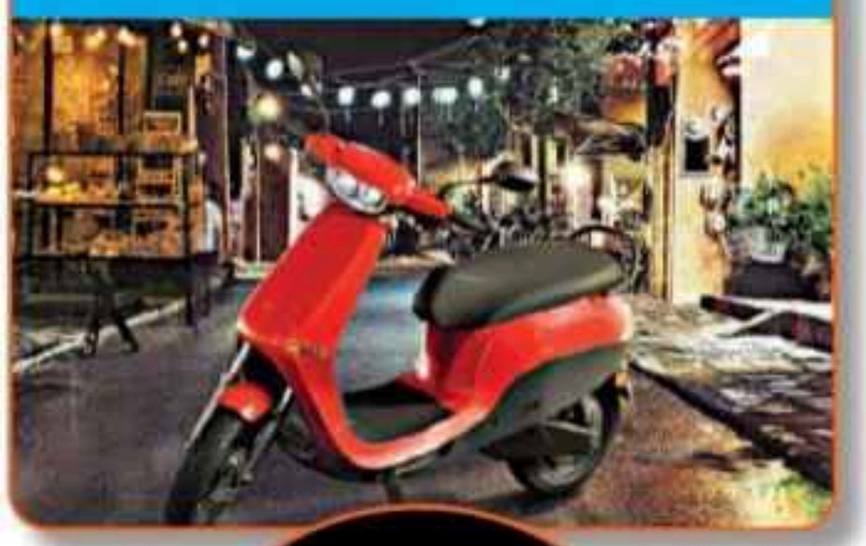

इंजन
इलेक्ट्रिक मोटर
पावर
6 बीएचपी
कीमत
84,999 रु.
(एक्स-शोरूम)

बेहद खूबसूरत

हमने हुंडई की प्रमुख एसयूवी टूसॉन की चौथी जेनरेशन की कार को यह पता लगाने के लिए चलाया कि खूबसूरती के अलावा इसमें और क्या है

योगेश शर्मा

मैं ने अमेरिका में पिछले साल के आखिर में चौथी जेनरेशन की टूसॉन को चलाया था और भारत में इसे चलाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. साथ ही, चूंकि इस देश में यह हुंडई की फ्लैगशिप गाड़ी होगी लिहाजा, मैं यह भी देखना चाहता था कि हुंडई इस कार में क्या बदलाव करेगी.

भारत में नई टूसॉन के एक्सटीरियर बिल्कुल उस कार की तरह हैं जिसे मैंने पिछले साल चलाया था और कार के लुक्स पर मेरी पहली राय आज भी बिल्कुल वैसी ही है. मैंने कहा था कि चौथी जेनरेशन की टूसॉन के लिए, हुंडई ने डिजाइन एलीमेंट्स के साथ उन्नत प्रकाश तकनीक को मिलाकर डिजाइन को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया है. इसके लिए हुंडई के ग्लोबल डिजाइन सेंटर के प्रमुख सांगयुप ली ने मोटर वाहन डिजाइन की भावनात्मक खूबियों को बढ़ाने के मिशन की खातिर इसमें स्पोर्ट्स कार की विशेषताएं डाली हैं. ज्यामितीय पैटर्न, जिसे हुंडई पैरामीट्रिक जुएल्स या रत्न कह रही है, को इस गाड़ी के पूरे डिजाइन में दोहराया गया है और लाइटिंग टेक्नोलॉजी के नए उपयोग से इसे और खास बनाया गया है. मिसाल के तौर पर, जब लाइट बंद कर दी जाती है, तो कोई यह नहीं बता सकता कि ग्रिल के पैरामीट्रिक डिजाइन एलीमेंट्स में डीआरएल इस्तेमाल किए गए हैं. हुंडई ने इन लाइट्स का नाम रखा है पैरामीट्रिक हिडन लाइट्स और इस फीचर का इस्तेमाल टेललाइट्स में भी किया गया है. इस डिजाइन फीचर का उपयोग दोनों साइड के साथ-साथ, पीछे के बम्पर पर भी किया गया है, जिसमें पैरामीट्रिक जुएल जैसे डिजाइन एलीमेंट भी इस्तेमाल हुए हैं.

इंस्ट्रूमेंट पैनल अल्कजार की तरह डिजिटल है, लेकिन बड़ा है और टूसॉन में मिलने वाले दो 10.25-इंच स्क्रीन में से एक है, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर्स हैं. दूसरी 10.25 इंच की स्क्रीन एक टचस्क्रीन है और इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए डिस्प्ले के रूप में काम करती है. एक ओर जहां यूएस-स्पेक टूसॉन में गियर शिफ्ट लीवर में वायर से गियर बदलने वाली टेक्नोलॉजी की जगह बटन से गियर बदलने की व्यवस्था थी, वहीं हुंडई इंडिया ने कोई जोखिम न लेते हुए इसे पारंपरिक गियर शिफ्ट लीवर रहने दिया है. इसके अलावा, बड़ा बदलाव एडीएएस फीचर्स

की पूरी शृंखला के साथ-साथ बोस सराउंड साउंड सिस्टम और फ्रंट पैसेंजर सीट के साइड में इलेक्ट्रिक बटन भी शामिल हैं, जिससे पीछे वाले यात्री को पीछे बैठे-बैठे अपने सामने की सीट को एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है. यह और अन्य विशेषताएं जैसे, पीछे की सीट पर रेक्लाइनिंग की सुविधा, एयर-कॉन वेंट्स के साथ रियर में चार्जिंग पोर्ट, टूसॉन को न केवल ड्राइवर की कार बनाती हैं, बल्कि पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी एक आरामदायक गाड़ी बनाती हैं—ये ऐसी खूबियां हैं जो भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण हैं.

हुंडई टूसॉन
सिम्बनेर 4डब्ल्यूडी
इंजन 2.0 डीजल
पावर 186 बीएचपी
टॉर्क 416 एनएम
गियर बॉक्स 8 स्पीड एटी
कीमत 34.50 लाख रु.
(एक्स-शोरूम)

हुंडई ने भारतीय बाजार में आजमाए और परखे गए 2.0-लीटर पावरट्रेन को उसी तरह रखा है. दोनों इंजनों को पिछली पीढ़ी के टूसॉन से बेहतर बनाया जा रहा है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाला डीजल वेरिएंट इसे बेहतरीन ड्राइवेबिलिटी के साथ-साथ, अच्छी दक्षता प्रदान करने के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ पावरट्रेन में से एक बनाता है. ऐसा लगता है कि नई जेनरेशन के मॉडल में किए गए बदलावों ने इसे क्विक एक्सीलेरेशन और ड्राइवेबिलिटी से कोई समझौता किए बिना, पहले से ज्यादा शांत और स्मूद बना दिया है. बेशक, अलग-अलग तरह के इलाकों में चलने में मदद के लिए इसमें ड्राइव मोड के साथ एचटीआरएसी 4डब्ल्यूडी सिस्टम भी है.

सवारी और हैंडलिंग की खूबियां भी काफी हद तक पिछली पीढ़ी के टूसॉन के समान ही हैं, जिसमें सस्पेंशन को ज्यादा सख्त साइड में लगाया गया है, ताकि न्यूनतम बॉडी रोल के साथ यह सड़क पर कार की तरह चले और खराब सड़क पर तेज गति से ग्लाइड करने में सक्षम हो.

टूसॉन कमोबेश वह सब कुछ देती है जो इस आकार की, पर्याप्त जगह वाली एसयूवी से उम्मीद की जा सकती है और इसमें वे खूबियां भी हैं जो लगभग इससे दोगुनी कीमत वाली हाइ-ऐंड प्रीमियम और लग्जरी कारों में होती हैं. यह पैसा वसूल गाड़ी है और इस मामले में यह कम और ज्यादा कीमत वाली एसयूवी, दोनों पर बीस साबित होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाड़ी ध्यान खींचती है. जब भी खरीदार किसी ड्राइव पर जाएगा, यह हर बार उसे अपनी खरीदारी पर सुकून का एहसास कराएगी. ■

JK TYRE
TOTAL CONTROL
PUNCTURE GUARD
SELF HEALING TYRE
Ab HawaNahinNiklegi
Goodbye hassling punctures!
Welcome JK Puncture Guard,
India's first puncture-resistant car tyre.
It comes with a unique sealant that heals
the tyre instantly after a puncture and
ensures minimum or no loss of air.
So, you can be assured,
ab #HawaNahinNiklegi!
Heals up to 6 mm injury
No need of puncture plug
Can take multiple punctures
Image simulated and for representational purpose only.
Scan the QR code to know more.
https://punctureguard.jktyre.com | Follow us on:
/JKTyre | /jktyrecorporate
YouTube /jktyrecorporate | /jktyrecorporate

नई और बेहतर

ग्रैंड विटारा के कंधों पर आया मारुति सुजुकी को मिड-साइज एसयूवी के सेग्मेंट में कामयाबी की राह पर ले जाने का भार

सुब सक्सेना

BHADOO SAHIB

अपने सेग्मेंट की अगुआ हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के साथ स्कोडा कुशाक, वीडब्ल्यू ताइगुन और एमजी एस्टर को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी ने टोयोटा से हाथ मिलाया है. ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हायराइडर में भले ही बहुत करीबी रिश्ता हो, पर मारुति सुजुकी ने अपनी एसयूवी को बहुत अलग और उम्दा पहचान दी है. सीधा-सपाट बोनट और उसके साथ बड़ी क्रोम ग्रिल और करीने से लगाए गए स्प्लिट हैडलैंप इस एसयूवी को नए जमाने का शानदार रंग-रूप देते हैं. पिछले हिस्से में बहुत आकर्षक स्टॉप लैंप हैं जो बिल्कुल बूट की लंबाई तक जाते हैं, जबकि रिवर्स लैंप और इंडीकेटर बंपर पर लगाए गए हैं.

लेआउट, स्विचगियर, स्टीयरिंग व्हील—सच कहें तो हरेक हिस्सा हायराइडर के समान ही है. इसमें मौजूद खूबियों की फेहरिस्त अच्छी-खासी बड़ी है. इनमें से कुछ हैं वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ 9 इंच का टचस्क्रीन, ऑटो-डिमिंग रियरव्यू मिरर, स्विच से एडजस्ट होने वाले ओआरवीएम, टीपीएमएस और 360 डिग्री का कैमरा व्यू. हवादार फ्रंट सीट, सिर के ऊपर डिस्प्ले और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग केवल स्ट्रांग हाइब्रिड मॉडल में हैं. आगे की सीट बेहद आरामदेह हैं, हालांकि उन्हें स्विच के जरिए एडजस्ट नहीं किया जा सकता. प्लास्टिक की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती थी. पिछली सीटों में पैरों और घुटनों के लिए काफी जगह है और जांघ के नीचे भी अच्छा सहारा दिया गया है, जबकि सीटों को पीछे झुकाकर और भी आराम से बैठा जा सकता है. हालांकि सिर के ऊपर की जगह बस काफी ही कही जाएगी.

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
अल्फा+
इंजिन 1.5 पेट्रोल हाइब्रिड
पावर 115.56 बीएचपी
गियरबॉक्स ई-सीवीटी
कीमत 19.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम)

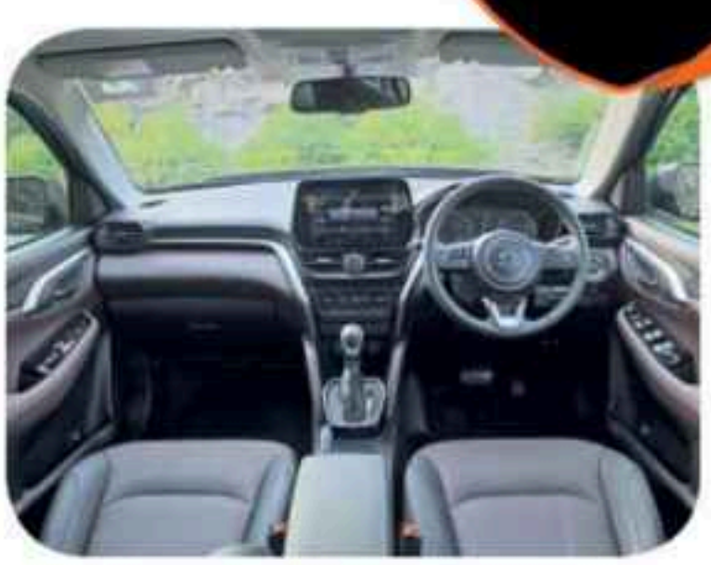

तकरीबन 116 बीएचपी की मिली-जुली ताकत के साथ यह हाइब्रिड कार काफी तेजी से फर्राटा भरती है. 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज का दावा किया गया है और 45 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार में 1,200 किमी से ज्यादा दूरी तक जा सकती है. राइड क्वालिटी के लिहाज से बात करें तो कम रफ्तार पर भले ही यह कुछ कर्कश है, पर रफ्तार बढ़ने के साथ काफी बेहतर होती जाती है और तिहाई अंकों की रफ्तार पर यह एसयूवी सड़क से बहुत अच्छी तरह चिपककर चलती मालूम होती है.

ग्रैंड विटारा की ढेरों खासियतें हैं, मसलन, नए जमाने का लुक, जानदार हैंडलिंग, अच्छी पावरट्रेनें, और सबसे बड़ी बात मन की शांति जो मारुति सुजुकी का मालिक होने से आती है. यह अपने स्थापित प्रतिद्वंद्वियों से खरीदारों का खासा बड़ा हिस्सा लेने के लिए तैयार लगती है. ■

लग्जरी हुई इलेक्ट्रिक

हमने पता लगाया कि भारतीय सड़कों पर एस-क्लास की समकक्ष इलेक्ट्रिक कारें ड्राइव करते हुए कैसा लगता है

योगेंद्र प्रताप

मर्सिडीज-बेंज
ईक्यूएस 580 4मैटिक
इंजन ड्यूएल इलेक्ट्रिक मोटर
पावर 524 बीएचपी
टॉर्क 850 एनएम
गियर बॉक्स सिंगल स्पीड
कीमत 1.55 करोड़ रु.
(एक्स-शोरूम)

मर्सिडीज ईक्यूएस 580 की ठीक-ठाक कीमत रख पाई, तो इसकी वजह नई जीएसटी व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक कारों को मिलने वाले फायदे हैं. भारत में एसेंबल होने की बदौलत इस कार पर महज 5 फीसद जीएसटी लगता है, जबकि एस-क्लास की कारों पर 50 फीसद जीएसटी वसूला जाता है.

आकार में ईक्यूएस एस-क्लास की कारों के समान ही है, बस यह 28 मिमी ज्यादा संकरी और 73 मिमी ज्यादा छोटी है, और इसका व्हीलबेस भी बस 6 मिमी ही छोटा है. मगर पीछे फास्टबैक स्टाइल और आगे काले पैनल के साथ अपने धनुष सरीखे कैब-फॉरवर्ड डिजाइन की वजह से ईक्यूएस अलग और खास है. कुल मिलाकर अपने आकार और विभिन्न डिजाइनों की बदौलत यह इतने बेहतरीन ढंग से हवा को काटते हुए आगे बढ़ती है कि ऐसा 0.20 की प्रोडक्शन कारों में पहले नहीं देखा गया. इसी की बदौलत इसने 857 किमी की एआरएआइ से प्रमाणित दूरी हासिल की है.

बाहरी रूप-रंग तो आकर्षक है ही, अंदर की सजावट भी एमबीयूएक्स हाइपरस्क्रीन के साथ क्रांतिकारी नजर आती है. इस स्क्रीन में तीन डिस्प्ले हैं—एक बीच में 17.7 इंच का, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आगे बैठी सवारियों के लिए इतना ही बड़ा एक और स्क्रीन. सीटों की व्यवस्था अल्ट्रा लक्जूरियस है, जिसमें पीछे की सीटों को जरूरत के हिसाब से झुकाया जा सकता है, जबकि 15 स्पीकरों का बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम कानों को शानदार तजुर्बा देता है.

ईक्यूएस 580 4मैटिक दो मोटरों से चलती है, जो हर एक्सल पर एक-एक लगी हैं और 500 बीएचपी तथा 850 बीएचपी की मिली-जुली ताकत पैदा करती हैं. मोटर को 107.8 केडब्ल्यूएच या किलोवॉट-ऑवर की लीथियम एनएमसी बैटरी ताकत देती है. कार के साथ स्टैंडर्ड थ्री-फेज एसी वॉलबॉक्स चार्जर आता है जिसे लगाकर 10 घंटे में पूरा चार्ज किया जा सकता है.

ईक्यूएस ड्राइव करते हुए लगता है कि यह हवा पर चल रही है और स्पोर्ट्स कार सरीखे एक्सलेरेशन से इसे जब चाहे तब ताकत दी जा सकती है. रियर-व्हील ड्राइव स्टीयरिंग पिछले पहियों को 10 डिग्री तक घुमा सकती है. स्टीयरिंग बहुत हल्का और आसान है और ऊर्जा भरने के लिए कई मोड हैं. एयर सस्पेंशन से लैस यह कार 25 मिमी ऊपर उठ जाती है, जिसकी हमारे यहां की जरा कमतर सड़कों पर बहुत जरूरत है. इसके अलावा ड्राइवर की मदद के लिए कई चीजें और सहायता प्रणालियां हैं जिनका जोर सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने पर है.

ईक्यूएस 580 की शक्ल में आपको एक ऐसी कार मिलती है जो आराम और विलासिता से भरी-पूरी है, साथ ही टेक्नोलॉजी और हरित मोर्चों पर आगे है, आइसीई कारों से टक्कर लेने वाली रेंज के साथ दूरी की फिक्र से मुक्ति देती है और जब कोई जोशो-खरोश से भरी ड्राइव करना चाहे तो स्पोर्ट्स कार की तरह चलती है. ■

रोमांचकारी भविष्य

हीरो मोटोकॉर्प के बिल्कुल नए वीडा वी1 प्रो ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में कंपनी के प्रवेश की घोषणा की

राहुल घोष

वीडा ब्रांड ने वी1 प्रो और वी1 प्लस के लॉन्च के साथ हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक स्कूटर मूवमेंट की कमान संभाली है. हमने प्रो की सवारी की, जो एक बड़ी बैटरी और बढ़िया प्रदर्शन के साथ सबसे अच्छा संस्करण है. सामने एक बड़ी एलईडी हेडलाइट है और फिर एक छोटी विंडस्क्रीन की बगल में मोटरसाइकिल जैसी एलईडी विंकर्स है. टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन अच्छा है और यह स्कूटर स्मार्ट अलॉय व्हील्स पर चलती है. इसका 7 इंच का रंगीन डिस्प्ले चमकीला है और कड़ी धूप में भी आसानी से पढ़ा जा सकता है. इसके ट्विन-सीट सेटअप में दो कम्पार्टमेंट हैं, जिनमें से एक रिमूवेबल बैटरी पैक के लिए जबकि दूसरा स्टोरेज के लिए जगह प्रदान करता है. कुल मिलाकर इसमें 26 लीटर कार्गो स्पेस की पेशकश की गई है. राइडर की सीट के ठीक नीचे बैटरियों को रखने की व्यवस्था की वजह से बैठने की जगह नीची है, जिससे आरामदायक राइडिंग पोजीशन बनती है. सीट की ऊंचाई भी 780 मिमी पर सवारी के अनुकूल है.

पीछे की तरफ स्लीक विंकर्स के साथ एलईडी टेल लाइट है. आकर्षक रंग पैलेट के साथ वीडा वी1 प्रो काफी आकर्षक दिखता है.

हीरो वीडा वी1 प्रो दो रिमूवेबल लिथियम-आयन बैटरी से चलता है जिसमें प्रत्येक की क्षमता 1.97केडब्ल्यूएच है. एक ओर जहां इन्हें रिचार्ज के लिए निकाला जा सकता है, वहीं इस स्कूटर को डेडिकेटेड प्लग का उपयोग करके सीधे चार्ज किया जा सकता है. हीरो मोटोकॉर्प एक बार चार्ज करने पर 165 किमी की कुल रेंज का दावा करती है जो कि काफी अच्छा है. कोई भी व्यक्ति इस स्कूटर को 65 मिनट में 80 फीसद तक फास्ट चार्ज कर सकता है. यह स्कूटर इको, राइड और स्पोर्ट मोड के साथ आता है और एक कस्टम मोड भी है. वी1 प्रो 3.2 सेकंड में 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने तक इसकी रफ्तार बढ़ती रहती है.

यह तेज रफ्तार में भी सड़क पर स्थिर रहता है और रफ्तार बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है. अगर किसी को जल्दबाजी में ओवरटेक करना है, तो बस इतना करना है कि थ्रॉटल को अधिकतम घुमाना है. इससे स्कूटर 'बूस्ट' मोड में चला जाता है और थोड़ी देर के लिए अधिकतम शक्ति प्रदान करता है. यह स्कूटर बेहद फुर्तीला है और इससे लेन बदलने या यातायात को आसानी से काटने में मदद मिलनी चाहिए.

हीरो वीडा वी1 प्रो आरामदायक राइडिंग पोजिशन प्रदान करता है. इसमें रिमूवेबल बैटरी का होना सबसे अच्छी बात है. दिक्कत की बात सिर्फ एक है और वह इसकी कीमत, जो ज्यादा है. लेकिन आपको हीरो मोटोकॉर्प से जो स्कूटर मिल रही है, वह इस प्रीमियम के लायक है. ■

JKTYRE
TOTAL CONTROL

NO TERRAIN IS ROUGH TERRAIN TOUGH TERRAIN

RANGER
SERIES

STAY WILD AT HEART

100 to 0 in 4 sec | Tougher Side Wall

Hilly and Highway Terrain Specialist

Image simulated for illustrative purpose. Based on internal test result.

www.jktyre.com | Follow us on: /JKTyre /jktyrecorporate YouTube /jktyrecorporate /jktyrecorporate

इंटेलिजेंट ड्राइविंग

ज्यादातर सड़क हादसे इनसानी गलतियों की वजह से होते हैं, पर कारों में नई टेक्नोलॉजी आने से इन गलतियों को कम से कम किया जा सकता है. यहां हम ऐसे ही एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स यानी एडीएएस के बारे में जानकारी दे रहे हैं

अभीक दास

BHADOO SAHIB

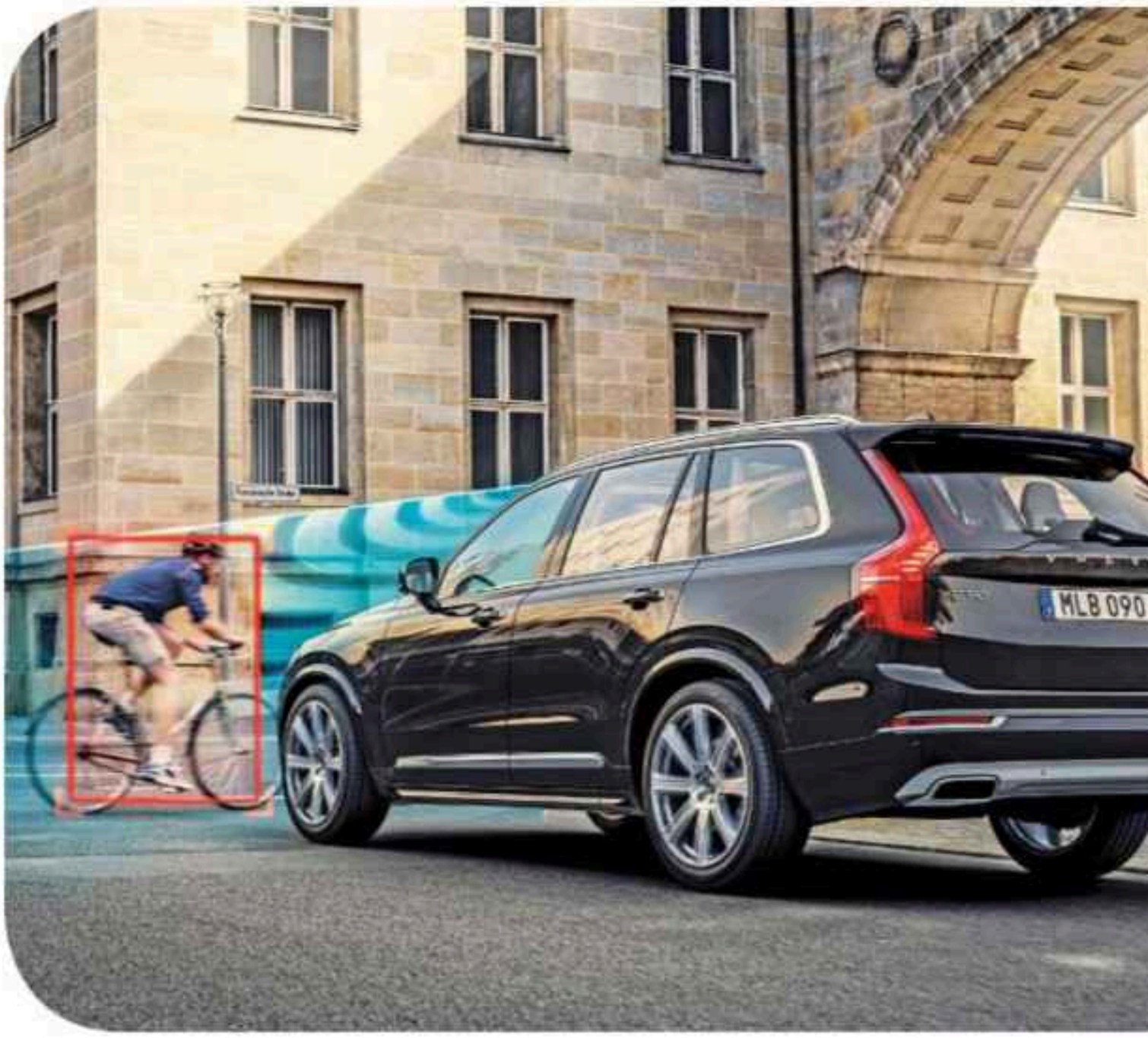

इनसानों को इस तरह नहीं बनाया गया है कि कोई प्रतिक्रिया देने में वे बाकियों के बराबर समय लें. हम सबको अलग-अलग परिस्थितियों ने बनाया होता है, इसलिए अचानक किसी हरकत या संभावित स्थिति के जवाब में हमारी प्रतिक्रियाएं भी काफी अलग-अलग होती हैं. अलबत्ता यह समझा जा सकता है कि इनसानी गलतियों की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, पर दिमागी समझ-बूझ में मदद करने वाली तमाम मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें कम

से कम जरूर किया जा सकता है. टेक्नोलॉजी सड़क पर ड्राइव या राइड करने वाले हर शख्स को एक धरातल पर ला खड़ा करने की भूमिका निभा सकती है. ठीक यहीं एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम्स (एडीएएस) यानी ड्राइविंग में सहायक उन्नत प्रणालियों की भूमिका शुरू होती है.

बहुत सी बेहद अहम तकनीकें, जो पहले महंगी कारों के ही नसीब में थीं, अब कीमत के लिहाज से इतनी सस्ती हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैन्यूफैक्चरर उन्हें अपने कस्टमर को दे पा रहे हैं. इस तरह, वे सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बना रहे हैं. अब जब महिंद्रा की एक्सयूवी700 के अलावा एमजी एस्टर और ग्लोस्टर सरीखी कारें भी एडीएएस लगा रही हैं, तो सभी यह जानना चाहते हैं कि यह कैसे काम करती है.

एडीएएस क्या है?

सीधे-सादे ढंग से कहें, तो एडीएएस में कैमरे और राडार-आधारित सेंसर शामिल होते हैं, जिनसे वाहन और उसके ड्राइवर को पता चलता रहता है कि उनके आसपास की स्थिति और माहौल कैसा है. ऐसा करते हुए कैमरे और सेंसर दूसरे वाहनों, पैदलों, सड़क के संकेत चिन्हों, अड़चनों और लेन वगैरह से जुड़ी बातों की जानकारी बटोरते हैं और तय करते हैं कि बाहर की चीजों के मुकाबले उनके वाहन की स्थिति क्या है. इन जानकारियों में यह गणना भी शामिल होती है कि इन सारी बदलती स्थितियों के संदर्भ में वाहन की रफ्तार कितनी है, ताकि एक सुरक्षित दूरी बनाई जा सके, अगर जरूरत हो तो इमरजेंसी ब्रेक लगाए जा सकें या स्टीयरिंग को लेन के भीतर रहने के लिए मुस्तैद किया जा सके.

सुरक्षित सफर

ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने वाली तकनीक पहले महंगी कारों तक ही सीमित थी लेकिन अब यह आम कारों में भी इस्तेमाल होने लगी है

क्या इसका मतलब यह है कि एडीएएस से लैस कार अपने आप चल सकती है?

एडीएएस को ऑटोमेशन के छह अलग-अलग स्तरों में बांटा गया है, जिनमें केवल चेतावनी की सुविधा से लेकर आंशिक स्वचालन नियंत्रण और वाहन को पूरी तरह स्वचालित ढंग से चलाने की इजाजत देने वाले सबसे ऊंचे स्तर तक शामिल हैं. बुनियादी कामों में सहायता करने वाली सुविधाओं को लेवल 0 के खाने में रखा गया है. मसलन पार्किंग सेंसर, आसपास का नजारा दिखाने वाले कैमरे, ट्रैफिक संकेत की पहचान, लेन से हटने की चेतावनी, पीछे से काटते हुए गुजरने वाले ट्रैफिक के बारे में अलर्ट, आगे से टक्कर की चेतावनी और अन्य विशेषताएं जो कुछ भी करने का अंतिम फैसला ड्राइवर पर छोड़ती हैं. संक्षेप में कहें, तो ड्राइवर को किसी भी संभावित वस्तु, रुकावट और लेन से भटकने सरीखी गलतियों के बारे में अलर्ट करने वाली कोई भी चेतावनी प्रणाली एडीएएस का बुनियादी लेवल है.

चेतावनियों को अनदेखा किए जाने पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने, लेन से भटकने का पता चलने पर स्टीयरिंग में सुधार करने जैसे कुछ दूसरे काम, लेवल 1 और लेवल 2 के हिस्से आते हैं. फैसला लेने की इनसानी समझ पर भरोसा करते हुए प्रणाली सबसे पहले लेवल 0 चेतावनियों का ही इस्तेमाल करती है, पर इसे हस्तक्षेप की स्थिति में सहायता के लिए प्रोग्राम किया गया होता है. लेवल 1 और लेवल 2 के बीच फर्क यह है कि लेवल 1 केवल एक कार्य संभाल सकता है जबकि लेवर 2 बहुत-से कामों को नियंत्रित कर सकता है. एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल लेवल 1 की ऑटोनॉमी का उदाहरण होगा, जबकि ऑटोनॉमस पार्किंग लेवल 2 की ऑटोनॉमी के खाने में रखी जाएगी. भारत में मिलने वाली मौजूदा कारों में लेवल 0 से लेवल 2 तक की एडीएएस की खूबियां दी जाती हैं. ये खूबियां कीमत के हिसाब से नहीं बदलतीं,

एडीएएस में कौन-कौन सी खूबियां हैं?

एक आधुनिक कार जिसमें एडीएएस लगा हो, उसमें इस सिस्टम के लेवल और दूसरी तकनीकों के आधार पर आपको ये सुविधाएं मिल सकती हैं

एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (एसीसी)

एसीसी कंट्रोल सिस्टम आगे के वाहन से दूरी मापने के लिए फ्रंट कैमरे और सेंसर का इस्तेमाल करता है और उस हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता है. एसीसी हमेशा सामने वाले वाहन से ऐसी दूरी बनाकर चलता है जिस पर ब्रेक लगाना सुरक्षित हो.

ऑटोमेटिक इमर्जेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (एईबी)

एसीसी के साथ या फिर स्वतंत्र रूप से भी एईबी अपने कैमरों और सेंसरों के जरिए सामने वाले वाहन की स्पीड मापता है और सुरक्षित दूरी से कम पर किसी वाहन के अचानक करीब आने की स्थिति में ब्रेक लगा देता है.

फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (एफसीडब्ल्यू)

लेवल 0 इनेबल्ड एडीएएस कारों के सामने किसी दूसरे वाहन या वस्तु के नजदीक आ जाने पर यह सिस्टम ड्राइवर को वार्निंग देता है. लेवल 1 और 2 सिस्टम एईबी का इस्तेमाल करता है ताकि टक्कर टाली जा सके या नुक्सान कम से कम किया जा सके.

लेन डिपार्चर वॉर्निंग (एलडीडब्ल्यू)

कार के अचानक लेन बदलने पर एलडीडब्ल्यू सिस्टम ऑडियो वॉर्निंग देता है या फिर स्टीयरिंग पर वाइब्रेशन देता है ताकि ड्राइवर संभल जाए.

ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (बीएसडी)

साइड या ओआरवीएम कैमरों के जरिए ब्लाइंड स्पॉट में आने वाले वाहनों को तुरंत डिटेक्ट किया जा सकता है. ये अपेक्षाकृत ज्यादा बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं. दूसरी तरफ कॉन्वेक्स ब्लाइंड स्पॉट मिरर कभी-कभी छोटे वाहनों, जैसे बाइक को डिटेक्ट नहीं कर पाते.

ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंस

पहले ये सिस्टम सिर्फ महंगी कारों तक सीमित थे लेकिन अब ये करीब-करीब आम हो चुके हैं. सिस्टम कार के पीछे और साइड की जगह का अनुमान बताता है और स्टीयरिंग का पूरी तरह से नियंत्रण ले लेता है. इस दौरान ड्राइवर सिर्फ ब्रेक लगा सकता है.

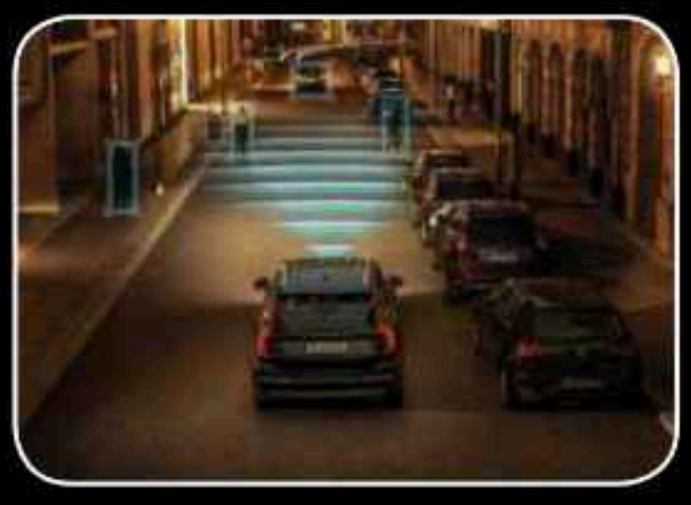

अन्य खूबियां

एडीएएस में कुछ और इंटेलीजेंट फंक्शन शामिल किए गए हैं जैसे एडेप्टिव हेडलैंप. ये ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप डिम हो सकते हैं, या अंधेरी और खाली सड़क पर हाइ बीम मोड में आ सकते हैं. इसके अलावा, अगर ड्राइवर सुस्त हो रहा है, उसकी आंख लग रही है तो कैमरे आई मूवमेंट से इसकी पहचान कर चेतावनी जारी कर सकते हैं.

जिसे अलग-अलग कारों के जरिए देखा जा सकता है. मसलन, मर्सिडीज-एएमजी ई 63एस में केवल बुनियादी चेतावनियां हैं, नई स्कोडा स्लैविया में मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग सहायता और महिंद्रा एसयूवी में एडीएएस के कार्यों का लेवल 2 का ऑटोमेशन दिया जाता है. फिलहाल ये प्रणालियां न तो कानूनन अनिवार्य हैं और न मानकीकृत की गई हैं, पर इन्हें मानक बनाने की जरूरत है, ताकि वे कई परिस्थितियों में असरदार ढंग से काम कर सकें. लेवल 3 से लेवल 5 तक की प्रणालियां पूरी तरह ऑटोनोमस ड्राइविंग की सुविधा देती हैं, जिनमें इनसानी हस्तक्षेप कम से कम होता है या इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है.

क्या एडीएएस सभी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है?

मैन्युफैक्चरर जब एडीएएस अपनाएंगे और ज्यादा सस्ती कीमतों पर मुहैया कराएंगे, तो आने वाले सालों में सड़क हादसों में कमी आना तय है. ज्यादा बड़ा सवाल प्रणाली पर भरोसा करने का है. यह प्रणाली कैसे और किन परिदृश्यों में सबसे अच्छे ढंग से काम करती है, यह सीखने और समझने में वक्त लगेगा.

भारत में सुव्यवस्थित से लेकर अव्यवस्थित तक, हर तरह का ट्रैफिक है. कहीं सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो कहीं नदारद. फिर ड्राइविंग में अनुशासन की कमी और कानून लागू न करने जैसी कई और भी समस्याएं हैं.

अपने टेस्ट में हमने पाया कि ऐसी सड़कों पर एडीएएस का इस्तेमाल सबसे अच्छा होगा, जहां साफ लेन बनी हुई हैं, ट्रैफिक मध्यम है और उसका अंदाज लगाना मुमकिन है. भारत में चलने वाली कारों में उपलब्ध एडीएएस का मौजूदा स्तर हमेशा ड्राइवर के ध्यान की मांग करता है. भारतीय ड्राइवर का मतलब है, उसके हाथ हमेशा स्टीयरिंग व्हील पर होंगे. ऑटोमेटेड प्रणालियों और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता की तरफ बढ़ते हुए इन प्रणालियों में भरोसा विकसित करना अच्छी शुरुआत है. ■

ई-डेट या जज्बात का अखेट

डेटिंग ऐप के जरिए बनने वाली रिलेशनशिप के भावनात्मक जोखिम तो हैं ही, यह आपको शारीरिक खतरे में भी डाल सकती है

सोनाली आचार्जी | *इलस्ट्रेशनः* नीलांजन दास

ल 2021 की बात है. कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 23 वर्षीया अन्यया लोहानी को संग-साथ और भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस हुई. पुणे की इस रिसर्च इंटर्न ने डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने का फैसला किया. मनमाफिक मैच खोजने में उन्हें दो हफ्ते लगे. अगले दो महीने दोनों ने रोज बातें कीं, वर्चुअल डेट पर गए और एक-दूसरे को बताया कि वे कैसी जिंदगी, कैसे सपने चाहते थे. 2022 में लोहानी अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से रू-ब-रू मिलने को तैयार थीं. मगर वह टालमटोल करता रहा. लोहानी कहती हैं, ''हम डेट तय करते और आखिरी वक्त कैंसल कर देते. दो हफ्ते यही होता रहा. मैं आजिज आ गई. मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं दिखता.''

मगर फैसला मानने के बजाय उनका ऑनलाइन प्रेमी पीछे ही पड़ गया. वे बताती हैं, ''मुझे अपना नंबर, ईमेल आइडी और सोशल मीडिया अकाउंट बदलने पड़े, क्योंकि वह लगातार मेसेज करता. ज्यादातर माफी मांगता, पर कभी-कभी पीकर गुस्से में अनाप-शनाप भी बोलता, यहां तक कि धमकियां देता.'' इस तजुर्बे से वे इतना डर गईं कि ई-डेटिंग से ही तौबा कर ली. वे याद करती हैं, ''डरावनी बात यह थी कि जिस पर आपने भरोसा किया, उसका ऐसा पहलू भी हो सकता था.''

कोविड के लॉकडाउन के दौरान जब ऑफलाइन साथी खोजने-मिलने की गुंजाइश कम हो गई, तो कई लोगों ने मन बहलाने, नए दोस्त बनाने या लंबा साथ निभाने वाला संभावित साथी तलाशने के लिए डेटिंग ऐप का रुख किया. रिसर्च फर्म सेंसर टॉवर के मुताबिक जनवरी 2019 से जनवरी 2022 के बीच दुनिया भर में लोकप्रिय तीन डेटिंग ऐप टिंडर, बम्बल और हिंज का इस्तेमाल कुल 17 फीसद बढ़ा. बम्बल के भारत में 45 लाख से ज्यादा यूजर हैं. 2021 के एक सर्वे से पता चला कि 42 फीसद यूजर इस ऐप पर पहली बार उसी साल आए. यह भी पता चला कि 65 फीसद भारतीय यूजर 2022 में अपने जोड़ीदार से रू-ब-रू मिलने की उम्मीद कर रहे थे. मुंबई की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दीक्षा अथवानी कहती हैं, ''डेटिंग ऐप के इस्तेमाल की स्वीकृति और लोकप्रियता बढ़ी है. कई माता-पिता इसे सही मानते हैं. लेकिन दर्दनाक रिश्तों के बुरे असर से निपटने में यूजर की मदद के लिए बहुत काम नहीं हुआ.''

विशेषज्ञों का कहना है कि बेहिसाब स्वाइप (संभावित जोड़ीदार को पसंद या खारिज करने), घोस्टिंग (शानदार डेट के बाद गायब हो जाने) और धोखा देने की डिजिटल डेटिंग संस्कृति कई बार यूजर का आत्मविश्वास तोड़ देती है, उन्हें भावात्मक रूप से खाली कर देती है. यहां तक कि वे स्वाइप (या डेटिंग ऐप) से थकने लगते हैं. हिंज के एक वैश्विक सर्वे से पता चला कि उनके 61 फीसद यूजर आधुनिक डेटिंग से तंग आ चुके थे. वहीं, अप्रैल 2022 के एक अमेरिकी सर्वे से पता चला कि पांच में चार ऑनलाइन डेटर भावनात्मक रूप से थके हुए थे. भारत में डेटिंग ऐप क्वेक क्वेक के 2022 के एक सर्वे में खुलासा हुआ कि उसके एक तिहाई यूजर परेशान थे कि ऐप पर उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था. 41 फीसद इसलिए नाखुश थे कि पहले हफ्ते में उन्हें कोई मैच नहीं मिला.

जो लोग रिश्ते को ऑफलाइन ले जा पाए, उन्हें ज्यादा मायूस करने वाले नतीजे झेलने पड़े. टीवी चैनलों पर जारी 26 वर्षीया श्रद्धा वालकर की खौफनाक कहानी तो मिसाल है ही. उसके अलावा भी डेटिंग ऐप पर बने रिश्तों में बलात्कार, नाजायज वसूली और चोरी-छिपे पीछा करने के मामले बीते एक साल के दौरान लगातार खबरों में रहे हैं. ऐसे में ऑनलाइन मिले किसी शख्स पर क्या वाकई भरोसा किया जा सकता है? सोशल मीडिया विशेषज्ञ और

छल-छद्म भरी डेटिंग की अपनी अलग जबान

अस्वीकार्य डिजिटल व्यवहार-बर्ताव की नई शब्दावली

नेगिंग

निगेटिव फीडबैक का संक्षिप्त नाम. ऐसा करते समय आलोचना को तारीफ के लबादे में छिपा लिया जाता है. मसलन, 'आप उतने बेवकूफ नहीं हैं जितने दिखते हैं.'

ब्रेडक्रंबिंग

जब एक संभावित पार्टनर उम्मीदें तो बहुत जगा देता है पर पूरी नहीं करता—डेट बार-बार खिसकाता है और लंबे समय तक साथ निभाने का वादा करने तक तो बात ही नहीं पहुंचने देता

फ्लीबैगिंग

यह जुमला डार्क सिटकॉम फ्लीबैग से आया है. यह ऐसे चक्कर को कहते हैं जिसमें आप उस शख्स के प्रेम में पड़ते और निकलते रहते हैं जिसने आपको भावनात्मक रूप से थका दिया है

ऑर्बिटिंग

यह उन लोगों के बर्ताव के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपको कभी तो ना और कभी हां कहते रहते हैं

कुशनिंग

उसे कहते हैं जब कोई किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे लोगों के साथ रोमांटिक विकल्प की संभावना बनाए रखता है

रोचिंग

जिसे आप डेट कर रहे हैं उससे यह तथ्य छिपाना कि आप और लोगों से भी इस सिलसिले में मिल रहे हैं

पॉकेटिंग

जब एक पार्टनर दूसरे को सबके सामने आने से बचाता-छिपाता है और रिलेशनशिप को गोपनीय रखना चाहता है

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहांस) बेंगलुरू में मनोचिकित्सक डॉ मनोज शर्मा कहते हैं, ''पारंपरिक तौर पर जोड़ियां दोनों की जान-पहचान के किसी शख्स के जरिए मिलाई जाती थीं. परिवार का सदस्य, दोस्त या सहकर्मी, कोई ऐसा होता था जो (संभावित जोड़ीदार के) चरित्र और व्यक्तित्व की जिम्मेदारी ले. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप शुरू से शुरू करते हैं, लिहाजा जरूरी है कि लोग एक दूसरे को जानने के लिए समय लें. अकेले चैटिंग से तो यूजर की देहभाषा पता नहीं चलती. इसलिए वीडियो कॉल होने चाहिए. ऑफलाइन मुलाकातें सार्वजनिक जगहों पर हों और किसी भरोसेमंद दोस्त को इसकी जानकारी हो.''

विशेषज्ञों का कहना है कि बदसुलूकी के पहले संकेत ऑनलाइन बातचीत और यूजर के संवाद के तौर-तरीके में खोजे जा सकते हैं. नारीवादी एक्टिविस्ट कविता कृष्णन कहती हैं, ''ऑफलाइन बदसुलूकी, या दरअसल हत्या, रातो-रात नहीं बल्कि सामान्यत: घरेलू हिंसा के लंबे दौर के बाद होती है. हमें चाहिए कि बदसुलूकी के शिकार लोगों को पहली बार में ही सहारा दें, आवाज उठाने और बदसुलूकी के खिलाफ कदम उठाने का आत्मविश्वास दें. जब आप मीन-मेख निकाले बगैर मदद करते हैं, तभी पीड़ित खतरे में होने पर हर बार आपको कॉल करेगा और उसकी जिंदगी बच सकेगी''

सुरक्षित डेटिंग के नौ सीधे-सरल फंडे

1. छल-छद्म भरे डेटिंग बर्ताव को भांपकर तुरंत उस बारे में आवाज उठाएं
2. साफ-साफ तय कर लें कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं और सीमाएं क्या हैं
3. ऐसे वीडियो और फोटो शेयर न करें जिन्हें लेकर बाद में आपको पछतावा हो
4. अपने बैंक संबंधी डीटेल और पासवर्ड इत्यादि साझा करने से बचें
5. रिश्ता गांठने की हड़बड़ी में न फंसें, पहले सामने वाले व्यक्ति को ठीक से समझें
6. आमने-सामने मुलाकात से पहले एक बार वीडियो पर चैट जरूर कर लें
7. पहली कुछ मुलाकातें सार्वजनिक किस्म की जगहों पर करने को वरीयता दें
8. रिश्ता ऑफलाइन बन जाने के बाद भी परिजनों/रिश्तेदारों को लूप में बनाए रखें
9. अपने डेटिंग ऐप के सेफ्टी फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी रखें

डेटिंग के दर्दनाक रुझान

जून में 28 वर्षीया एक महिला का दिल्ली के होटल में एक ऐसे शख्स ने कथित बलात्कार किया जिसे वह डेटिंग ऐप पर मिली थी. महीने भर पहले फरीदाबाद की पुलिस ने वसूली के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया. उन्होंने एलजीबीटीक्यू समुदाय के सोशल नेटवर्किंग ऐप ग्रिंडर पर 25 लोगों के कथित आपत्तिजनक वीडियो बनाए. अजनबियों से ऑनलाइन मिलने में सुरक्षा के बढ़ते सरोकारों के अलावा दूसरी मनोवैज्ञानिक चिंताएं भी हैं. डेटिंग ऐप के कई यूजर बताते हैं कि वे डेटिंग के दर्दनाक पहलुओं से गुजरे. इनमें दबंगई से लेकर चोरी-छिपे पीछा करने और ब्रेडक्रंबिंग या दाना डालने (झूठे वादे और उम्मीदें देने का सिलसिला) से लेकर घोस्टिंग यानी अचानक गायब होकर रिश्ते तोड़ लेना तक शामिल है. 2021 में बम्बल के एक सर्वे से पता चला कि भारत में इस ऐप का इस्तेमाल कर रही 83 फीसद महिलाएं ऑनलाइन उत्पीड़न झेल रही थीं और तीन में से एक तो हर हफ्ते झेल रही थी. सर्वे में शामिल आधी से ज्यादा महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थीं और 48 फीसद नाराज थीं. उसी साल साइबर सुरक्षा प्रदाता कैस्पर्स्की के एक वैश्विक सर्वे में सामने आया कि नौ लोकप्रिय डेटिंग ऐप (जो भारत में भी हैं) के सुरक्षा फीचर बेहतर होने के बाद भी साइबरस्टाकिंग (साइबर दुनिया में पीछा करना) और डॉक्सिंग (किसी की निजी जानकारी ऑनलाइन जाहिर करना) का खतरा बना हुआ था.

लोग ऐसा इसलिए भी कर पाते हैं कि उन्हें इसके नतीजे नहीं भुगतने पड़ते. वरिष्ठ वकील कुलजीत रावल कहते हैं, ''समय के साथ ऑनलाइन डेटिंग की बाकी समस्याओं के अलावा, निजता पर इसके दूरगामी असर भी देखे गए हैं. वजह है ऑनलाइन डेटिंग ऐप को उनके वाजिब इस्तेमाल तक सीमित रखने वाले कानूनों का न होना.'' सूचना प्रौद्योगिकी कानून में वाकई ऐसी कोई अलग धारा नहीं है जो साइबरस्टॉकिंग को अपराध के तौर पर परिभाषित करती हो. मामला दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को पीड़ित को भेजी या उसके बारे में पोस्ट की गई अश्लील सामग्री

भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख डेटिंग ऐप

और अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए वे क्या तौर-तरीके अपनाते हैं

क्चेक क्चेक

रोजाना डाउनलोड: 16,000

सुरक्षा के उपाय: यह यूजर्स को प्रोफाइल ब्लॉक करने और सर्च में किसी कॉन्टैक्ट को फिल्टर करने की सहूलियत देता है. डेटर्स को सुरक्षा संबंधी सलाह भी देता है

टिंडर

रोजाना डाउनलोड: 15,500

सुरक्षा के उपाय: सभी यूजर्स के लिए फोटो वेरिफिकेशन उपलब्ध. लैंगिक हिंसा और दुर्व्यवहार की तुरंत रिपोर्टिंग का इंतजाम. फोटो या मैसेज के आधार पर रिपोर्टिंग के लिए एक नया फीचर

बंबल

रोजाना डाउनलोड: 13,500

सुरक्षा के उपाय: अपने सदस्यों को ऑनलाइन ट्रॉमा सपोर्ट मुहैया करता है. दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग करने वालों की पहचान गुप्त रखता है; मैसेज सेव रखता है जिससे दुर्व्यवहार करने वाले साक्ष्य डिलीट न कर सकें

ट्रूली मैडली

रोजाना डाउनलोड: 8,600

सुरक्षा के उपाय: निजता बचाए रखने को यह यूजर्स को ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देता. यूजर्स को हर कदम पर सुरक्षा के उपाय सुझाता है. यूजर पॉलिसी न मानने वालों की प्रोफाइल ब्लॉक कर देता है

हैपन

रोजाना डाउनलोड: 8,020

सुरक्षा के उपाय: प्रोफाइल रिपोर्ट या ब्लॉक करने की सहूलियत. वीडियो साक्ष्यों के आधार पर प्रोफाइल को मंजूरी. प्रमाणित प्रोफाइल पर ब्लू सील लगा देते हैं

*रोजाना डाउनलोड के भारत के आंकड़े फरवरी 2022 के औसत के आधार पर.
(स्रोत:apptweak.com)

सरीखे प्रमाण देने पड़ते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि गलत ऑनलाइन बर्ताव के कई दूसरे रूप भी मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि अपराध करने वाला सजा से बच निकलता है. डॉ शर्मा कहते हैं, ''कभी-कभी आपको परेशान किया जाता है या भावनात्मक तकलीफ पहुंचाने वाले संदेश भेजे जाते हैं, जो 'अश्लील' नहीं भी हो सकते हैं पर आपके मनोबल और सुरक्षाबोध को उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं.''

विशेषज्ञ बताते हैं कि बर्ताव में दिखती कुछ चीजें—जैसे, अचानक गायब होकर रिश्ता तोड़ लेना, दाना डालना, झूठ बोलना, आक्रामक होना—आम तौर पर व्यक्तित्व की ज्यादा बड़ी गड़बड़ियों की तरफ इशारा करती हैं. मसलन, घोस्टिंग को ही लें. बम्बल के एक सर्वे से पता चला कि पांच में से एक भारतीय ने घोस्टिंग का सामना किया. फोर्टिस हेल्थकेयर में मानसिक स्वास्थ्य के डायरेक्टर डॉ समीर पारिख कहते हैं, ''कुछ लोग जज्बात का सामना नहीं करते, वे मुश्किल और कष्टदायक बातचीत किए बगैर आगे बढ़ जाना ज्यादा आसान समझते हैं और सामने वाले की भावनाओं से हमदर्दी नहीं जता पाते.'' रिसर्च से साबित हुआ है कि अचानक छोड़ दिए गए शख्स के दिलो-दिमाग पर इसका खासा असर पड़ता है. साइबरसाइकोलॉजी जर्नल में सितंबर 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि जिन्हें घोस्टिंग झेलनी पड़ी, वे उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बहिष्कृत महसूस करते हैं जिन्हें दूसरे तरीकों से ऑनलाइन अस्वीकृति मिली. दिल्ली के 18 वर्षीय छात्र करण शर्मा (बदला हुआ नाम) छह हफ्तों से डेटिंग ऐप पर बातचीत कर रहे थे. हाल में उनका जोड़ीदार अचानक गायब हो गया. वे कहते हैं, ''ऐसा तजुर्बा कहीं और मुमकिन नहीं, जब सामने वाला न कोई सफाई देता है, न कोई चेतावनी, बस किनारा कर लेता है. आपको लगता है आपका इस्तेमाल किया गया, आप बेकार हैं, खारिज हो चुके हैं. रोमांस का विचार भी आपको मायूस कर देता है.''

सुरक्षित डिजिटल डेटिंग के उपाय

विशेषज्ञों का कहना है कि ऑफलाइन डेट की तरह ही डिजिटल चैट के दौरान भी भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए (देखें सुरक्षित डेटिंग के 9 आसान नियम). जरूरी है कि ऐप यूजर एक दूसरे को बताएं कि डिजिटल डेटिंग में वे क्या चाहते हैं और साथ में कितने सहज हैं. रू-ब-रू मुलाकात का फैसला करने से पहले वक्त देकर अपने जोड़ीदार की पृष्ठभूमि, रुचियों और व्यक्तित्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है. रावल कहते हैं, ''सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि यूजर समझदारी बरते, समझ-बूझ से काम ले, धीरे-धीरे आगे बढ़े और सबसे अहम यह कि डिजिटल धोखेबाजों या घोटालेबाजों से सावधान रहे. ''

डेटिंग ऐप के सुरक्षा फीचर जानना भी जरूरी है. मसलन, टिंडर ने यौन हिंसा और उत्पीड़न रिपोर्ट करने का नया तरीका जोड़ा है. यूजर किसी से 'अनमैच्ड' होने के बाद भी ऐप पर रिपोर्ट कर सकते हैं. उसने फोटो वेरिफिकेशन भी लॉन्च किया है, जिसमें प्रोफाइल को ब्लू टिक निशान मिलता है. बम्बल ने भी यूजर की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है (दिल्ली पुलिस के मुताबिक, श्रद्धा वाल्कर अपने लिव-इन पार्टनर और कथित हत्यारे आफताब पूनावाला से 2019 में बम्बल पर ही मिली). इस अमेरिकी फर्म के प्रवक्ता कहते हैं, ''बम्बल में सभी इस अकथनीय अपराध के बारे में सुनकर स्तब्ध रह गए. हम दिल से श्रद्धा के परिवार के साथ हैं. हमारे सदस्यों की सुरक्षा और सलामती हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारे यहां उनकी जरूरतों के लिए समर्पित वैश्विक टीम है.'' यह ऐप उत्पीड़न रिपोर्ट करने वालों की पहचान की हिफाजत करता है और (अपनी रिटेंशन पॉलिसी के मुताबिक) तमाम मेसेज सेव करके रखता है, ताकि 'अनमेचिंग' के जरिए सबूत डीलिट न किए जा सकें. यौन हमले और रिश्तों में बदसुलूकी झेलने वाले यूजर को काउंसलिंग दिलवाने के लिए 2021 में बम्बल ने ट्रॉमा सपोर्ट साइट ब्लूम से भी हाथ मिलाया.

डेटिंग ऐप में सहूलत, मजा और संभावनाएं हैं, पर किसी भी रिश्ते को अपनी सलामती के अहसास से ऊपर नहीं रखना चाहिए. अथवानी कहती हैं, ''अगर आपको लगे कि कोई गैरवफादार, आक्रामक और तिकड़मी है, तो जरूरी है कि उसे बता दें आप कैसा महसूस करते हैं और साफ सीमाएं तय करें. अगर वे नहीं बदलते, तो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए या ऐसा करने के लिए मदद लेनी चाहिए.'' अगर रिश्ता ऑफलाइन जाता है, तो अपने को सामाजिक तौर पर कभी अलग-थलग न करें, ताकि खटास की नौबत आने पर मदद के लिए हमेशा कोई हो. ■

अनुष्का मेनन

‘लौटने को बेताब हूं मैं’

इस साल दो ग्रैमी अवॉर्ड के लिए मनोनीत अनुष्का शंकर एक कंसर्ट टुअर के लिए भारत लौटी हैं. अपने संगीत और व्यवहार दोनों में क्यों आखिर वे व्यापक विस्तार वाला नजरिया अपनाती हैं? उन्हीं से जानते हैं

सवाल + जवाब

● आपका भारत दौरा एक नियमित आयोजन बन चुका है. कोरोना में आप नहीं आ पाईं. क्या इसे मिस किया?

बार-बार लौटकर आने में अच्छी बात यह है कि कहीं न कहीं आपको यहां घर जैसा महसूस होता रहता है. यह ख्याल नहीं उठता कि कभी यहीं से गए थे. एक रिश्ता जिंदा रहता है. एक जगह की धड़कन आपको महसूस होती रहती है. आपको घर जैसा लगे, इसके लिए यह सब जरूरी है. हिंदुस्तान से लंबे अरसे तक दूर रहने पर लगने लगता है, जैसे अब यह मेरा नहीं रहा. इसलिए मैं लौटने को बेताब हूं.

● आप श्रोताओं को बाकायदा यह एहसास करवाना चाह रही हैं कि सितार क्लासिकल दायरे से बाहर आवाजाही कर सकता है?

श्रोताओं से ज्यादा तो मैं खुद यह जानने को उत्सुक हूं कि सितार में आखिर कितनी संभावनाएं हैं. संस्कृतियों के बीच बुनते-बनते रिश्ते और दूसरों से सीखना, मुझे दोनों भाते हैं. भिन्न-भिन्न परंपराओं के दायरे में काम करना भी मुझे पसंद है. तरक्की के लिए यह बहुत जरूरी है.

● मुंबई वाले कंसर्ट में आप *इन ज्योति'ज़ नेम* बंदिश का विस्तार पेश कर रही हैं. यह ट्रेक 2012 में दिल्ली के गैंगरेप हादसे से प्रभावित है...

उस हादसे से तो हम सब खौफजदा हो गए थे. उस वक्त पूरी दुनिया महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार पर बात कर रही थी. और बदलाव की खातिर हमें वह सब करना जरूरी था. उस हादसे की दसवीं बरसी पर इसकी अपनी अहमियत है. यह संगीतमयी श्रद्धांजलि है क्योंकि सच पूछिए तो आखिर बदला क्या है? आपको लगता है कुछ बेहतर हुआ है?

● आप सात बार ग्रैमी में मनोनीत हो चुकी हैं, इस साल भी दो अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई हैं. उस ट्रॉफी की कितनी ललक है आपको?

ऐसा कुछ नहीं है. जाहिर-सी बात है कि आप जीतने की उम्मीद करते हैं और न जीत पाने से थोड़ी निराशा होती है. पर मैं यह भी नहीं सोचती कि किसी के लिए जीतना पक्का ही है. मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि मुझे अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया.

–सुहानी सिंह